छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | द्वितीय सत्र

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024

(माघ 23, शक सम्वत् 1945)

[अंक 06]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024

(माघ-23, शक संवत् 1945)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में जनता की समस्या उठाने के बजाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष पलायन कर देते हैं या तो दिन भर के लिए बहिष्कार कर देते हैं। यह लोग जनता की लड़ाई लड़ने के बजाए, वहां कांग्रेसियों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसे निपटाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा हताश, निराश और निष्क्रीय विपक्ष नहीं बना। यहां सदन में लोग आ भी नहीं रहे हैं। वहां सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं। वह भी नारा लिखाने के नाम से, अपना-अपना नाम लिखवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हम लोग उपस्थित हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हम हैं। (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यहां पर सदन में विपक्ष है। (हंसी)

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की संख्या 15 से अधिक है, आप चिन्ता मत करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तो सदन में ही नहीं आ रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सदन में आएंगे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय भईया को विपक्ष की ज्यादा चिन्ता है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में युवराज आ रहे हैं वह तो ठीक है। हमें यह गुटबाजी की लड़ाई देखने को मिली कि भूपेश बघेल जी का नाम नीचे विनीत में लिखा, उसको मिटाकर पूरा उमेश पटेल लिख दिया। रायगढ़ के पूरे समाचार पत्र रंगे पड़े हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय लखेश्वर जी, भूपेश जी और उमेश जी का नाम मिटाया गया तो उसमें यादव जी का एक स्थगन दे दीजिए। उनका नाम क्यों मिटाया गया, आप इसमें एक स्थगन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रस्ताव दे दीजिए। आपके पास और कोई मैटर तो नहीं है। इसलिए आप उसी में स्थगन प्रस्ताव दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य यह प्रश्नकाल है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें स्थगन प्रस्ताव बनाकर दीजिए। हम लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य प्रश्न लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय लखेश्वर भाई, आपको यह किसने बनाकर दिया? आपने जिस प्रश्न को लगाया है, यह किसने बनाकर दिया है?

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे मैंने बनाया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सही कह रहे हैं?

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां। आपको कोई शक है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप स्थगन भी बना लीजिए। उसमें क्या है ? आपमें काबिलियत की कमी थोड़ी है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अलग मैटर है।

<u>बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत कार्य</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 840) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छ.ग. राज्य के आदिवासी विकास प्राधिकरणों (बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र) के द्वारा वर्ष 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक कुल कितने-कितने कार्य व राशि स्वीकृत की गयी ? क्षेत्रवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ अथवा अधूरे स्थिति में बंद हैं ? कृपया बतावें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश"क" के स्वीकृत कार्यों तथा जिनकी प्रशासकीय स्वीकृतियां भी जारी हो गई हैं, उन कार्यों पर विभाग के द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कौन- कौन से कार्य ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 1554 कार्य हेतु राशि रूपये 5093.23 लाख स्वीकृत। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 704 कार्य हेतु राशि रूपये 3499.59 लाख स्वीकृत तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 462 कार्य हेतु राशि रूपये 3260.50 लाख स्वीकृत की गई। **(ख)** बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 331 कार्य पूर्ण, कुल 1045 कार्य अपूर्ण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं कुल 178 कार्य अप्रारंभ हैं। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 96 कार्य पूर्ण, कुल 542 कार्य अपूर्ण एवं कुल 66 कार्य अप्रारंभ हैं। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल 33 कार्य पूर्ण, कुल 368 कार्य अपूर्ण एवं कुल 61 कार्य अप्रारंभ हैं। **(ग)** कार्यों पर रोक नहीं लगाया गया है बल्कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अप्रारंभ कार्यों को वित्त विभाग की सहमति पश्चात प्रारंभ करने के निर्देश हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने, माननीय मंत्री जी से बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछा था? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। लेकिन इसमें पूर्ण और अपूर्ण कार्यों से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। यह ब्लॉक, जिला लेवल के अधिकारी देते हैं, वहां कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि कुल 178 कार्य अप्रारंभ हैं। इसी प्रकार सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत अलग अपूर्ण कार्य बताया गया है और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अंतर्गत कुल 61 कार्य अप्रारंभ बताया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह इस प्रकार का विरोधाभाष क्यों है ? आपने ब्लॉक, जिले और प्रदेश में अलग-अलग जानकारी दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाकर पूछ लीजिए। आप यहां पूछने के बजाए, आपको न्याय यात्रा में सब पता लग जाएगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भईया, यहां भी तो न्याय मांग रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भईया, न्याय वहीं मिलेगा।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, जो बस्तर विकास प्राधिकरण के स्वयं उपाध्यक्ष रहे।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष रहे और आप काफी लम्बे समय से उस क्षेत्र से सम्माननीय सदस्य रहे हैं। यह आपके समय का है। आपने इसकी स्वीकृति दे दी और आपने स्वीकृति दे दी तो महोदय, समय पर आपको यह काम पूरा करना था। अभी आप यह प्रश्न लगा रहे हैं। महोदय, हमने इसमें पूरी जानकारी दी है कि जो अभी तक इतने दिनों के बाद, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य दर्द और दवा एक साथ मांग रहे हैं। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही दवा देना।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने उसकी जानकारी दी है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा था कि वहां के ब्लॉकों से जानकारी आयी है कि वहां अप्रारंभ किए हुए कार्य निरंक बता रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जवाब में यह दिया गया है कि वहां इतने कार्य अप्रारंभ हैं, लेकिन ब्लॉक द्वारा जानकारी में निरंक है। खैर, आप यह मामला छोड़िए। आपने अपने उत्तर के "ग" में बताया है कि कार्यों पर रोक नहीं लगाया गया है बल्कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अप्रारंभ कार्यों को वित्त विभाग की सहमति पश्चात् प्रारंभ करने के निर्देश हैं लेकिन कलेक्टरों के द्वारा जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही जो अपूर्ण कार्य हैं, प्रारंभ नहीं किये गये थे, उसमें रोक लगा दी गई थी। आज तक उन कार्यों को प्रारंभ करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। सिर्फ प्राधिकरण कार्य के लिए ही वित्तीय अनुशासन की बात है या और दूसरे कार्यों के लिए भी है ? यह आदिवासी लोगों का पैसा है। डेढ़ लाख, दो लाख के छोटे-छोटे कार्य स्वीकृत हुए थे, उसको वित्तीय संतुलन के लिए उन कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जिला स्तर पर और भी काम स्वीकृत हुए हैं। डी.एम.एफ. फंड, समग्र विकास के पैसे से और भी बड़े-बड़े काम स्वीकृत हुए हैं, उसमें वित्तीय संतुलन के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ आपके द्वारा प्राधिकारण से आदिवासियों के हित के लिए जो छोटे-छोटे काम करते हैं, उसके लिए रोक लगाई गई है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि वह छोटे काम होते हैं और उन कार्यों को समय पर पूरा करना होता है। इतने दिन के बावजूद कर अगर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, यहां तक उन कार्यों का ले-आउट तक पास नहीं हुआ। ऐसे कार्य को निरस्त करके जो स्थिति बनेगी, हम फिर से देखेंगे। हमारी नई सरकार आई है, हम अपनी मंशा और आपकी मंशा के अनुरूप वहां की जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप निर्णय करेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता थी, इसलिए प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन करके उसको कार्य जारी किया गया था। लेकिन उन कार्यों की फिर से समीक्षा होगी, यह तो समझ से परे है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह छोटे-छोटे कार्य हैं और इस प्रकार से आदिवासियों के साथ आदिवासी मंत्री भेदभाव न करें और मैं यह चाहता हूं कि उन अप्रारंभ कार्यों को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दें।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अभी हमारे नये प्राधिकरण का गठन होगा और प्राधिकरण का गठन होगा तो आप माननीय सदस्य तो रहेंगे ही। आप इस विषय को वहां भी रखियेगा। उस पर जरूर पुर्नविचार किया जायेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री महोदय, उस काम को पिछली सरकार में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण की बैठक में पहले स्वीकृत किया है, नई सरकार आई है तो नया काम दे न, आपको कौन रोक रहा है ? लेकिन आप लोग पुराने काम को क्यों रोक रहे हैं ? जो पुराने काम स्वीकृत हुए हैं, उसके लिए जनता की मांग थी, आम आदमी को जाने के लिए दिक्कत हो रही थी,

सी.सी. रोड बन रही है, पुलिया बन रही है और आधी तो रोड और पुलिया बन चुकी हैं लेकिन इसके लिए पैसा नहीं निकल रहा है। उसमें दिक्कत है। जो उस रोड और पुलिया में मजदूर, मिस्त्री वगैरह काम किये हैं, सरपंच को उसका भुगतान करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी जांच करके जितना काम हुए है, उसका भुगतान कर दीजिए। जो उस में काम करने वाल गरीब आदमी है, वहां सरपंच बोल रहे हैं कि सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, उस पर रोक लगा दी गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, सरकार बनते ही आपने इतना पैसा वापस बुलाया था, वह आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। वह पैसा कहां गया, आज तक पता नहीं चला। वह परंपरा आपने ही डाली है, आज ही उसको भुगतो।

श्री कवासी लखमा :- उसको आप कर देना। आप बीच में अडंगा डालने का काम मत करना। हम लोग बधाई देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य सरपंच को दिये हैं, सरपंच ने आधी खुदाई करवा दी है, रेती, मिट्टी डलवा दी है, उसमें मजदूर लोग काम किये हैं, उसका पैसा मजदूरों को नहीं मिल रहा है, वह मजदूर लोग सरंपच का घेराव कर रहे हैं, सरंपच को मारने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोतीलाल साहू ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कार्य किया है, वह लोग क्या करेंगे ? अगर जितना काम किये हैं, उनको तो उनकी मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा न। वह गांव के गरीब आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपको कुछ बोलना है ? माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम यह पूरी बात रखेंगे तो आपका यहां खड़ा होना मुश्किल हो जायेगा।

श्री कवासी लखमा :- हमको खड़ा होना मुश्किल हो जाने दीजिये, इससे क्या होगा ? आप ई.डी. लायेंगे और जेल में भेज देंगे। आप व्यर्थ की बात मत करिये, यह जनता का काम है। यह हमारे काम की बात नहीं है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बस्तर के लोगों को काम है, इस कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मन हम ला डरवात हे। का चीज ला तुमन डरवाथो, हमन ला का खड़ा नई होना चाहिए ? जेल भेजिहा और का करिहा।

श्री कवासी लखमा :- क्या यह हम हमारे घर के काम के लिए बोल रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता का काम है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- हम लोगों को जनता ने जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वह मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया यह तीनों प्राधिकरण में जितने कार्य अप्रारंभ हैं और जो कार्य अपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कवासी जी, माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं, उसको सुन लीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य अपूर्ण हैं, उसमें मैंने बता दिया कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपूर्ण कार्य 1045 हैं, उसको पूर्ण कराना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। लेकिन तमाम सारे विभाग के जितने भी अप्रारंभ कार्य थे, उसकी जो निर्माण एजेंसियां थीं, उन सबको शासन के निर्देश से ही निरस्त किया गया है। यह शासन ने आदेश जारी किया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार निरस्त कर रही है। इसके पहले भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं। इसलिए कृपा करके आरोप-प्रत्यारोप लगाना बंद करिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, आप भी उसका निरीक्षण करिए, क्योंकि बहुत सारे सरपंच हो या समन्वित एजेंसी हो, बिना काम किए वहां एक ढेला भी काम नहीं हुआ। इसके बावजूद उसमें से 40 प्रतिशत राशि निकाल ली गई है। वह इधर-उधर भटक रहे हैं। वह दौड़ रहे हैं कि काम कैसे पूरा करें? मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि इस बात का भी तस्दीक करिये और यह संबंधित के खिलाफ जो दोषी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप मदद करिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। नेताम साहब, आपने जो कहा, उसके अनुसार हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। जो आदमी पैसा खाएगा, उसको जेल होना चाहिए। वह चाहे मेरा बेटा क्यों न हो। उसमें आप हम लोगों की सहयोग करिए। हम लोग उसमें एफ.आई.आर. दर्ज करने में विचार करेंगे। अगर बिना काम किया पैसा नहीं निकला, उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं। अगर किसी ने चार सौ बीसी काम किया, उसको जेल भेजिए। उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन जो कार्य किया है, वह घर का पैसा कहां से देगा? इसलिए मंत्री जी, मेरा छोटा सा निवेदन है कि जो कार्य नहीं किया है, फर्जी निकला है, उसको जेल भेजिए। हम आपके साथ हैं। आप उसको जेल भेजिए, लेकिन जो कार्य किया है, उसको आप स्वीकृत करेंगे न?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपने बात रख दी। हो गया।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, जो काम नहीं किया है। मंत्री जी ने कहा है। हम भी उसी चीज को पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी से पूछ लीजिये।

श्री कवासी लखमा :- चाहे वह हमारी पार्टी का हो, तुम्हारे पार्टी का हो, चाहे पंच हो या चाहे कोई भी हो, उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन जो काम किया है, उसको आप स्वीकृत करेंगे न?

श्री राम विचार नेताम :- करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी, यह सभी कार्य आचार संहिता के पहले स्वीकृत हैं। सभी कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है। इसके लिए राशि भी जारी हो गई है, दो-दो किश्त राशि जारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपके द्वारा जो अघोषित कार्य प्रारंभ नहीं करने की बात कही गई है, उसके कारण से रोक लगाई गई है। बाकी राशि जारी हो गई है, सब कुछ जारी हो गई है। मेरा निवेदन है कि यह छोटे-छोटे काम हैं। यह हितग्राहीमूलक काम है। इसमें ट्यूबवेल का काम है। ऐसे ही छोटे-छोटे काम हैं। इसको रोक लगायेंगे, फिर बरसात का मौसम आ जायेगा, फिर प्रक्रिया करते-करते साल भर हो जाएगा। दूसरा प्राधिकरण का गठन होगा, वह स्वीकृत होगा। यह सब छोटे-छोटे काम हैं। उसमें मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि यह कार्य तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री मोतीलाल साहू।

<u>अनुसूचित क्षेत्र के लिए "प्रयास" आवासीय विद्यालय का प्रारंभ</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 698) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक कितने "प्रयास" आवासीय विद्यालय, कहां-कहां पर प्रारंभ किये गये हैं। (ख) "प्रयास" आवासीय विद्यालय में वर्ष 2018 तक कुल कितने विद्यार्थी तथा वर्ष 2019 से 2023 तक कितने विद्यार्थी वर्षवार सम्मिलित हुए? उनको प्राप्तद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के साथ परीक्षा परिणाम का प्रतिशत वर्षवार देवें। (ग)वर्ष 2018 तक इंजीनियारिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयनित एवं प्रवेशित तथा वर्ष 2019 से 2023 तक इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयनित एवं प्रवेशित छात्रों का विवरण वर्षवार देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2019 से 2023 तक 05 निम्न प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये गये हैः- 1. नवीन बालक एवं कन्या प्रयास (अनुसूचित जनजाति) आवासीय विद्यालय पिनकापार, जिला-बालोद (छ.ग.) 2. नवीन बालक प्रयास (अनुसूचित जाति) आवासीय विद्यालय पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 3. नवीन कन्या प्रयास (अनुसूचित जाति) आवासीय विद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 4.. नवीन बालक प्रयास (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर,

जिला-रायपुर (छ.ग.) 5. नवीन कन्या प्रयास (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग) (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के अंतर्गत अनूसूचित क्षेत्र के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित है। इसमें माननीय मंत्री की तरफ से जवाब आया है कि कक्षा 10वीं बोर्ड का परिणाम वर्ष 2010-2018 तक लगभग 100 प्रतिशत रहा। उसके बाद वर्ष 2023 के आते-आते कक्षा 10वीं बोर्ड का परिणाम मात्र 92.6 प्रतिशत आ गया । छात्रों का 10वीं बोर्ड का जो परिणाम वर्ष 2018 तक 100 प्रतिशत रहा, लेकिन यह चिंतनीय विषय है कि वह वर्ष 2023 के आते तक 92.6 प्रतिशत हो गया। उसी प्रकार 12वीं का भी प्रतिशत शुरूआती दौर पर वर्ष 2018 तक शत् प्रतिशत रहा और वर्ष 2023 के आते तक 95 प्रतिशत तक पहुंच गया। मुझे इस बात का बड़ी चिंता है कि जिस उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा के लिए इस प्रयास आवासीय विद्यालय का शुरूआत किया गया है। शुरूआत बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन 5 सालों में उसमें गिरावट आया है। चूंकि इसका अध्यापन और कोचिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है। मुझे इस बात की पूरी शंका है कि इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और जो आंकडे भी बताये गये हैं । इंटरनेट में जो आंकड़े हैं और इनके द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है उसमें वर्ष 2019 का जो परिणाम है उसके भी प्रतिशत में अंतर है इस प्रकार मुझे शंका है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है इस कारण...।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न । आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि इसमें यह गिरावट आयी है । वर्ष 2018 तक का परिणाम और वर्ष 2023 तक का परिणाम तो मैं माननीय मंत्री जी से इस गिरावट का कारण जानना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी इसका कारण बता दीजिये । वे बस इसका कारण पूछ रहे हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रयास विद्यालय खोला गया है । यह आपकी दूरदृष्टि, आपकी इस समाज के प्रति एस.टी., एस.सी. एवं ओ.बी.सी. के बच्चों को कैसे शहरी क्षेत्र में लाकर के, बड़े शहरों में लाकर के उनको आज की जो ऑलइण्डिया सर्विसेस हैं या कॉम्पीडिशन की वे कैसे तैयारी कर सकें । महोदय, इसके लिये आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अर्थात् उस समय आपने जो निर्णय किया । यह दिखाता है कि इस समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता कितनी है । उस समय तक यह बहुत अच्छा चला और हमारा एक मॉडल स्कूल होता था । मॉडल क्लास को दिखाने के लिये हम लोग न जाने किन-किनको ले गये । इसके पहले बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है ।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है इसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके पहले आपको मालूम है कि वर्ष 2017 में हमारा परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत होता था और वर्ष 2018 तक 99 प्लस होता रहा लेकिन यह बात सही है कि वर्ष 2018 के बाद लगातार इसमें गिरावट आयी । मैं आप सबको हमारे जो प्रतिपक्ष के साथीगण बैठे हैं । इस वर्ग के प्रति आपके मन में भी कहीं न कहीं संवेदना होगी । इस वर्ग को ही आप बिलांग करते हैं । आपकी चिंता होनी चाहिए थी कि जब हम इन बच्चों को ला रहे हैं, प्रयास में प्रवेश देकर के उनको कैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार कर सकें, हम कैसे उनको उत्कृष्ट शिक्षा दे सकें । कैसे हम उनको Competition की तैयारी करवा सकें यह सब सोचकरक किया गया था लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2018 के बाद निश्चित ही इसमें कम ध्यान गया । केवल राजनीतिक भर्तियां होती गयीं । वहां पढ़ाई के नाम पर पूरा बोगस होता रहा और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैं प्रभार संभालने के बाद सबसे पहले वहां गया था । (मेजों की थपथपाहट) हमने प्रयास स्कूल जाकर विजिट किया । लोगों के बीच गया, बच्चों से बात की । मैंने वहां देखा कि मेस की हालत वैसे ही खराब है । वहां दो साल पहले से कम्प्यूटर की पूरी लाईट जली हुई है, दो साल तक ऐसे ही चलता रहा और उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी । बच्चों के खेल की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिये अच्छी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है । मैंने वहां पर तत्काल यह आदेश दिया कि तत्काल लैब का काम शुरू हो जाना चाहिए, हमने कलेक्टर से भी बात की और वहां पर हमने तत्काल काम की शुरूआत की है । यह काम किया है, ऐसे काम होता है । इस वर्ग के बच्चों को आप ला रहे हैं तो उनके लिये क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । मंत्री जी यह आदेश सभी...।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वहां पर बच्चों को कांजी हाउस जैसी जगह पर लाकर रखा है । हम इस तरीके की व्यवस्था नहीं होने देंगे । हमने हमारी सरकार, चूंकि यह माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । (मेजों की थपथपाहट) यह नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी वाली सरकार है और इसलिये उस गारंटी के तहत् इस वर्ग के बच्चों के लिये अथवा चाहे लोगों के लिये हो, उनके लिये जो भी बेहतर शिक्षा होगी, उनके लिये जो भी बेहतर सुविधा दी जा सकती है वह सुविधा देकर हम बेहतर Competition की तैयारी के लिये काम करेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- 12-15 जगह आदिवासी समाज के जाति प्रमाण-पत्र नइ बनत हे तेहू ला तो बना देवओ । जाति प्रमाण-पत्र नइ बनत हे, तुहू ला बो बना देवौ। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ विधायक हैं। उधर प्रश्न पूछें, हम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया, 5 साल के अध्ययन तो कर लवौ, जो छोड़कर गये हो ओला सुधारे ला तो पड़ही न। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- रामविचार साहब, पिछला कार्यकाल मोदी जी का था, उसमें तो कर्ज के बारे में कुछ नहीं किया। (व्यवधान) हम पर उंगली उठाने का काम मत करो। सरकार ने जिम्मेदारी दी है, उसका पालन करो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मोतीलाल जी, आप प्रश्न करिए। (व्यवधान)

श्री नीलकंठ नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में केवल आत्मानंद पर ध्यान दिया गया, उसमें भी कोई क्वालिटी नहीं आ पाई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। प्रश्नकर्ता ने अभी प्रश्न नहीं किये हैं। इनका हो जाए, फिर मैं लूंगा। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- पूरा झोल-झाल कर दिये। बद से बद्‌तर कर दिये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये कांग्रेस नहीं रहतिस तो कहां ले बइठव। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आत्मानंद से इतना चिढ़कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाये हैं। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- प्रयास और मॉडल स्कूल में कब-कब, कौन-कौन अधिकारी निरीक्षण में गये हैं? वह बुलाकर दिखवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आत्मानंद स्कूल में जाकर तो देखिए, इंग्लिश मीडियम के विद्‌यार्थी आत्मानंद में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भाई आपका प्रश्न नहीं है। मोतीलाल जी का प्रश्न है। उनका प्रश्न हुआ नहीं है। आप लोग खड़े हो रहे हैं। जिसका प्रश्न है, वह पहले 3 प्रश्न कर ले, उसके बाद यदि कोई प्रश्न आता है तो मैं उनको अवसर दे सकता हूं। मोतीलाल जी, आप अपना प्रश्न करिए।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों के भविष्य का विषय है..।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं, यह पूछ लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ये प्रश्न थोड़ी करथे, भाषण देथे।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय मंत्री जी ने स्वयं जांच कर पाया है कि उसमें अनियमितताएं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, उसे जांच कर संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रामविचार नेताम :- मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णु देव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार है। जो भी दोषी होगा। जो भी भ्रष्टाचारी होगा, उसको किसी भी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं, हम उनको दंडित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। उमेश पटेल जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में एक पूरक प्रश्न है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने आपकी बात तो पूरी कर दी। और कोई प्रश्न है?

श्री मोतीलाल साहू :- नहीं-नहीं, इसमें इस विषय से संबंधित ही बात है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, कोई सुझाव है या प्रश्न है।

श्री मोतीलाल साहू :- नहीं, विषय से ही संबंधित है। मैंने एक प्रश्न और किया था कि वर्ष 2010 से वर्ष 2018 जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में उक्त बच्चों का जो प्रवेश हुआ है, उस विषय में मैंने प्रश्न किया था और मुझे जानकारी आयी है कि 676 बच्चों का प्रवेश इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है और इंटरनेट से देखने पर पता चलता है कि इसमें 613 बच्चों का प्रवेश हुआ है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। वर्ष 2019 के बाद आज तक इंटरनेट में वो अपलोड भी नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या आने वाले समय में पारदर्शिता को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या आने वाले परिणाम को इंटरनेट में अपलोड करेंगे? वर्ष 2019 के बाद से वर्ष 2023 तक हुआ नहीं है। 5 सालों में नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। समझ गया। बताइए।

श्री रामविचार नेताम :- जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रयास आवासीय विद्यालय के संबंध में जानकारी चाहूंगा। मैं बड़े भैया मोतीलाल साहू जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है। मेरे विधान सभा में पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से पिनकापार में प्रयास आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, लेकिन उस स्वीकृति के बाद दुर्ग में वे स्कूल संचालित हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये पिनकापार में कब संचालित हो जायेंगे? क्योंकि वहां के बच्चे डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव ये तीनों विधान सभा का बॉर्डर पड़ता है डॉ. साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय। वहां कोलियारा के बाद से राजनांदगांव विधान सभा लग जाता है। रतनभाट के पास से डोंगरगांव विधान सभा, इधर खुज्जी लग जाता है तो 4-4 विधान सभा के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, ये प्रयास विद्यालय पिनकापार में संचालित हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपने सुझाव दे दिया, मंत्री जी ने नोट कर लिया। माननीय उमेश पटेल जी।

प्रश्न संख्या 3 :   XX   XX

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन सुविधा

[वित्त]

4. (*क्र. 631) श्री सुशांत शुक्ला (श्रीमती शेषराज हरवंश)(श्रीमती भावना बोहरा) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओपीएस पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है ? कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी हैं ? **(ख)** क्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संगठनों द्वारा इस योजना में प्रावधानों की कमियों को लेकर आवेदन दिया गया है? यदि हां, तो उनके प्रमुख बिन्दु क्या-क्या थे? उसे दूर करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के एनपीएस खातों में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खातों को नियमित/जीवित रखने हेतु एनपीएस में क्या प्रावधान है ? वर्तमान में की जा रही राशि की कटौती एवं पूर्व में एनपीएस योजना के तहत् काटी गई राशि के समायोजन हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं एवं एनपीएस की राशि कब तक प्राप्त होकर अधिकारियों/कर्मचारियों के खाते में जमा करा दी जावेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छ.ग. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। छ.ग. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किये गये हैं। (अधिसूचना की **प्रति पुस्तकालय में रखे प्रप्रत्र** में है) केन्द्र सरकार से नही, अपितु पीएफआरडीए से कुल राशि रूपये 19136.81 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है। **(ख)** छ.ग. अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पत्र क्रमांक 376 दिनांक 17.02.2023 द्वारा ओपीएस/एनपीएस विकल्प चयन हेतु निर्धारित तिथि में वृद्धि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था। तत्संबंध में वित्त निर्देश 12/2023 द्वारा विकल्प चयन की तिथि में वृद्धि करते हुए दिनांक 08 मई, 2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। **(ग)** ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिये एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित/जीवित रखने के संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित होने संबंधी प्रावधान नहीं है। वर्तमान में एनपीएस विकल्प का चयन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से ही एनपीएस योजना के प्रावधान अनुसार नियमित कटौती की जा रही है। ओपीएस के विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के पूर्व में एनपीएस अंशदान के रूप में वेतन से कटौती की जाकर एनएसडीएल में जमा की गई राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय

सेवक के मृत्यु/सेवानिवृत्त होने पर उनके एनपीएस खाते के अंतिम भुगतान से शासकीय कोष में जमा की जावेगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा आपसे प्रश्न प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन सुविधा से संबंधित है। प्रश्न का जवाब लिखित के रूप में आ चुका है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि पीएफआरडीए में 19136.81 करोड़ रूपये राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि की प्राप्ति हेतु अभी तक राज्य सरकार के द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं? कब तक प्राप्त हो जायेगी?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केन्द्र सरकार से नहीं, बल्कि पीएफआरडीए, जो पेंशन रेग्यूलेटरी अथॉरिटी की संस्था है, उससे कुल 19,136 करोड़ रूपए प्राप्त होना है, किंतु उसमें इन्-बिटविन यानी कोई एन.पी.एस. को समाप्त कर देता है तो उसको तत्काल इम्प्लायर को अर्थात् स्टेट के कंट्रीब्यूशन के लिए वापस पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन और इंप्लॉयर का का कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है । केन्द्र सरकार से नहीं, बल्कि पीएफआरडीए से इसमें राशि प्राप्त होगी और कुल 19,136 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होगी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- जब पीएफआरडीए की तरफ से पैसे वापस ही नहीं होने है तो ओ.पी.एस. लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किस आधार पर किया ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने एन.पी.एस. के सिस्टम को समाप्त करके ओ.पी.एस. का सिस्टम लाया । कर्मचारियों के लिए उनको कौन सा अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, यह तो अलग प्रश्न है किंतु मुझे लगता है कि 19,136 करोड़ रूपए पर तत्कालीन सरकार की गिद्धदृष्टि थी (शेम शेम की आवाज)। वे चाहते थे कि उस पैसे को ले लिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए । एन.पी.एस. जो कि 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय लागू हुआ था । उस एन.पी.एस. के तहत् 10 प्रतिशत राशि इम्प्लायर को देना होता है और 10 प्रतिशत राशि इम्प्लाई देता है । जो भी सरकार वर्तमान में रहती है उसको प्रतिमाह 10-10 प्रतिशत के हिसाब से एन.पी.एस. के अंतर्गत राशि देना पड़ता है । तत्कालीन सरकार 10 प्रतिशत की राशि देना नहीं चाहती थी । साथ में 2004 से 2022 तक इन्होंने लागू रहा । इन्होंने 11 मई 2002 लागू किया था । इस 18 साल ड्यूरेशन में जिसमें से 15 साल आपके मुख्यमंत्रित्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । उसने 19,136 करोड़ में से लगभग 15 हजार करोड़ रूपए की राशि उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया था । उस पैसे को वापस लेकर ये फिर से बंदरबांट करना चाहते थे । इनको इम्प्लाई के मन से कोई लेना देना नहीं था । 19,136 करोड़ रूपए पर इनकी गिद्धदृष्टि थी (शेम शेम

की आवाज़) जो 10 प्रतिशत की एन.पी.एस. की राशि देनी होती है वह भी देने से ये बचना चाहते थे । खा-पीकर बर्बाद करना चाहते थे, इसका उद्देश्य यही था।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, चलिए । श्रीमती शेषराज हरवंश ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी । चूंकि अब आपकी सरकार है और इसके पहले हमारी सरकार रही है । दोनों ही सरकारों की मंशा प्रदेश को सुदृढ़ बनाने की, जनता का ध्यान रखने की और समस्याओं का समाधान करने की रही है । माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया है । आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि कर्मचारियों के हित में निर्णय लें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, 11 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ राजपत्र के चौथे क्रमांक में प्रकाशित था कि भविष्य निधि में लेखा एवं पेंशन से संबंधित कार्यवाही हेतु पृथक संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी । तो क्या इसकी स्थापना हो चुकी है या भविष्य में इसकी स्थापना होना है?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है । इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ओ.पी.एस. को जारी रखेगी या भविष्य में एन.पी.एस. योजना लागू की जाएगी । दोनों में से कौन सी योजना निकटतम् भविष्य में लागू रहेगी ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है । जो सिस्टम चल रहा है, वह चल रहा है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्मय से एक प्रश्न और है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत हो गए । उनके परिवारजनों को ओ.पी.एस. में आने का विकल्प दिया गया था । उस विकल्प के तहत एन.पी.एस. से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी । आज एक साल गुजर गए हैं । ऐसे किसी भी कर्मचारी को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है । क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने यह नियम बनाया था कि NPS में जो उनकी Contribution की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही OPS को एडॉप्ट कर सकते हैं और NPS की Contribution की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है, क्योंकि PFRDA बीच में उनको पैसा नहीं देती है तो PFRDA ने जब उनको पैसा नहीं दिया इसलिए उन्हानें जमा नहीं किया है और पिछली सरकार ने यह प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास PFRDA से जो OPS के लिए पैसा आना था, वह कब तक आएगा? इसमे जो पैसा पेंडिंग है, उसको लाने के लिए आगे क्या प्रावधान किया जा रहा है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, PFRDA से OPS के लिए कोई पैसा नहीं आना था। 1 अप्रैल 2004 को पूरे देश में NPS लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 01 नवंबर, 2004 को लागू हुई थी, उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है, उसका 10 प्रतिशत का योगदान शुरूआती दौर में जाता था और जो Employer (रोजगार प्रदाता) है, उसकी ओर से 10 प्रतिशत राशि दी जाती थी, बाद में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। यह भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14 प्रतिशत की राशि को राज्य के लिए लागू ना करके 10 प्रतिशत ही कर रही थी। यह Employer का Contribution 10 प्रतिशत और employee का Contribution 10 प्रतिशत, ये दोनों PFRDA के माध्यम से NSDL (National Securities Depository Limited) में जमा होता जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- चौधरी जी, मेरा आग्रह है, OPS और NPS इन दोनों के बारे में विधायकगणों को एक नोट भिजवा दें, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कन्फ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं तो आप सभी को थोड़ा सा नोट भिजवा देंगे तो क्लीयर हो जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बोल दिया ना। भाई, मैंने सब के लिए बोल दिया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके तीन सवाल हो गए, बहुत हो गए।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों राशि है, चाहे वह NPS की राशि हो या OPS की राशि हो, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजना ज्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि एक जो है, वह डायरेक्ट रिटायरमेंट के बाद उनके एकाउंट में आता है और एक जिस हिसाब से शेयर के रेट बढ़ते हैं, उस हिसाब से मिलता है तो पेंशनधारी के लिए दोनों में कौन सी ज्यादा बेहतर है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- एक्चुअली इसको समझना employee के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में भारत की इकोनॉमिक स्टोरी में बिलिव करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग NPS को ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि 1980 से ले करके 2020 तक का हम पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16 प्रतिशत का सी.ए.जी.आर. बैठता है, 16 प्रतिशत का सी.ए.जी.आर. जो कम्पाउंडिंग तरीके से होता है, वह बहुत बड़ी राशि बन करके उभरकर आता है। जिन लोगों को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलिव है और इनकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है क्योंकि इनकोनॉमिक्स में सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते

हैं, उस दृष्टिकोण से NPS की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है। बट जो लोग एक्सेफ रिटर्न चाहते हैं, उनको OPS में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है। वे सुरक्षित महसूस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां शेयर में पड़ रहे हो। आपका तो प्रश्न ही नहीं है। मैं आगे मौका दे दूंगा, इसमें प्रश्न मत करिए।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसी में प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें क्या समझ में आ रहा है। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं कलेक्टर साहब ला कहत हंव जे ग्रोथ वाला बात कर हे। ऐ भारत के शेयर हा घटत हे कि बढ़त हे, तेखर ले ओ पेंशन ला फिर से बतावव। आप पुराना ला चलाईहा कि नया ला चलाईहा एला बतावव। घुमा-घुमा के झन बतावव। कलेक्टर मन के पेंशन और गरीब मन के पेंशन अलग अलग होथे।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कलेक्टर क्या करेगा ? श्री इंद्र साव ।

प्रश्न संख्या 05 : XX XX

6. (*क्र. 904) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक सामग्री का वितरण किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो कितने किसानों/ हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में वितरित की गई थी? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की वितरित सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में भ्रष्टाचार की क्या शिकायतें प्राप्त हुई उन पर क्या- क्या कार्यवाही की गई व दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी, हॉ। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत जिला कबीरधाम में 08 किसानों/हितग्राहियों को वर्ष 2020-21 में सतही पानी दोहन हेतु प्रति हितग्राही 75 मीटर के मान से 08 बंडल एप्रोक्स पाईप वितरित की गई थी। **(ग)** वितरित सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, फलस्वरूप दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, आदिम जाति विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि तक कितनी सामग्री वितरण की गयी है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस प्रश्न के परिशिष्ट को देखेंगे तो उसमें सभी जानकारी दी गई हैं, इसलिए आप एक बार परिशिष्ट को देख लीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 से लेकर वर्तमान तक जो 3 साल का समय है, यदि हम उसमें वितरण की बात करते हैं तो सिर्फ 18 बण्डल पाईप का वितरण हुआ है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हमारा जो लक्ष्य था कि इतनी सामग्री का वितरण करना है तो क्या हमने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है ? क्योंकि जो रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है और जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें सिर्फ 8 बण्डल पाइप का ही वितरण किया गया है। क्या आप मुझे इसकी जानकारी देंगे कि हमारा लक्ष्य इतना ही था या हमने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है ? बजट में इसके लिए किस तरीके से प्रावधान था या इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया ? क्योंकि 3 साल में केवल 8 बण्डल सामग्री का वितरण हुआ है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राशि परियोजना मत की है। परियोजना मत में एक क्लस्टरवार हितग्राहियों की चयन सूची जारी होती है। परियोजना में जो तय हुआ था, उसके आधार पर महीडबरा के दो, ग्राम दमगढ़ तथा ग्राम छिरछा के 3 कुल 8 हितग्राहियों को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, गौरेला से सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिंचाई पाईप के वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इतनी ही जानकारी है। माननीय सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर परियोजना वहां पर अपना प्रस्ताव रखता है और माननीय सदस्यों की उपस्थिति में क्लस्टरवार जो प्रस्ताव आते हैं, उसकी अलग-अलग स्वीकृति की जाती है कि किसी का पाईप के विस्तार का काम है, किसी का बोरिंग का काम करना है। इस तरह के छोटे-छोटे कामों को लिया जाता है। यदि इसके बावजूद आपके संज्ञान में कोई प्रस्ताव या बात हो तो निश्चित ही आप मुझे दे दीजिए, उस पर हम विचार करके कार्रवाई भी करेंगे और यदि वह स्वीकृति के योग्य होगा तो हम स्वीकृति भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री लखेश्वर बघेल जी चरणदास महंत जी का प्रश्न करेंगे।

<u>रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी स्थित भूमि का विक्रय एवं मॉल का निर्माण</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (*क्र. 849) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल कितनी भूमि थी ? इसमें से कितनी भूमि का किन-किन दरों पर विक्रय/पट्टा किया गया तथा कितनी भूमि पर सिटी सेंटर मॉल का निर्माण किसके द्वारा, कितनी लागत से किया गया ? **(ख)** क्या सिटी सेंटर मॉल के लिए हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण को लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों एवं क्या-क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ

और उसे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** रायपुर विकास प्राधिकारण की सिटी सेन्टर मॉल के कारण कितनी-कितनी लेनदारियां तथा देनदारियां किसके-किसके प्रति है ? प्राधिकरण को लगभग कितनी आर्थिक क्षति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121.11 एकड़ भूमि थी। पंडरी स्थित प्राधिकरण की भूमियों के विक्रय/पट्टा एवं दरों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र†[2] अनुसार** हैं। प्राधिकरण की पंडरी स्थित भूमि में से कुल 5.70 एकड़ भूमि (23082 वर्गमीटर) में मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेन्टर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमि. द्वारा किया गया हैं जिसकी लागत रू. 129.38 करोड़ थी। **(ख)** रायपुर विकास प्राधिकरण को उक्त सिटी सेन्टर मॉल से रू. 41,00,51,000/- राजस्व प्राप्ति हुई तथा प्रति वर्ष रू.2,66,53,315/- लीजरेंट (ग्राउंडरेंट) प्राप्त होता हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। **(ग)** वर्तमान में सिटी सेन्टर मॉल के कारण प्राधिकरण को कोई देनदारी/लेनदारियां नहीं हैं। प्राधिकरण को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ. चरणदास महंत द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि परिशिष्ट चार में बताया गया है कि सभी भू-खण्ड 30 वर्षीय पट्टे पर दिये गये हैं। सन् 1993 के पश्चात् दिये गये पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि लीज की 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् क्या पट्टों का नवीनीकरण और दरों का पुन: निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है और कब तक किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्री लखेश्वर बघेल :- चंद्राकर जी, आपको तो टोका-टाकी का मेडल मिलना चाहिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह चरणदास महंत जी का प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री लखेश्वर बघेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- यह उनके बदले में प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121 एकड़ भूमि थी। पंडरी स्थित प्राधिकरण की भूमि के विक्रय पट्टा और दरों की पूरी जानकारी चार्ट बनाकर उपलब्ध करा दी गई है। प्राधिकरण की पंडरी स्थित 5 एकड़, 70 डिसमिल (लगभग 23082 वर्गमीटर) भूमि पर मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 129 करोड़ रूपये है।

अध्यक्ष महोदय :- आप और प्रश्न पूछिये।

---

[2] † परिशिष्ट "चार"

श्री लखेश्वर बघेल :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था तो क्या यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है और क्या इसके कारण बैंक द्वारा ऋणदाता सिटी माल की नीलामी कर दी गई है ? यदि नीलाम कर दी गई है तो उसे किसने और कितने में लिया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- टाइम पास कर रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त कंपनी N.C.L.T. दिवालिया हो चुकी है। इस कंपनी के मैटर को लेकर गये थे और उसके पश्चात् एक दूसरी कम्पनी उसको ले चुकी है । उसका नाम मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा और एन.सी.एल.टी के माध्यम से उसने लिया है और उसकी जो भी *Responsibility* थी, वह नई कम्पनी को *Transfer* हुई है । उस कम्पनी का नाम आर.डी.बी. रियलिटी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने एन.सी.एल.टी. में जाकर उसको लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- और कुछ पूछना है तो पूछिए । संतुष्ट हैं तो बैठ जाईए।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसमें और भी प्रश्न है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय यात्रा चल रही है । यह विषय माननीय राहुल गांधी तक जाएगा ।

श्री रामकुमार यादव :- दिल्ली तक पहुंच गे हे, चिन्ता मत करौ ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राधिकरण को कितना निर्मित क्षेत्र प्राप्त होना था और कब प्राप्त हुआ और प्राधिकरण ने इसका क्या उपयोग किया है ?

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण को उक्त सिटी सेन्टर मॉल से 41 करोड़, 51 हजार रूपए की राजस्व प्राप्ति जो एक मुश्त होनी थी, वह हुई है । उसके अलावा लीज रेंट जो ग्राउण्ड रेंट है, वह रेग्युलर बेसिस पर 2,66,53,315 प्रतिवर्ष के हिसाब से प्राप्त होता है । शुरूआती दौर में उनका जो एग्रीमेंट था, उनके अनुसार 41 करोड़, 51 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई है । आर.डी.ए. के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो उनकी बॉडी और उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार इस पैसे का खर्च किया जा रहा है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लिखित उत्तर में बताया है कि वर्तमान स्थिति में सिटी सेन्टर मॉल के कारण प्राधिकरण को कोई लेनदारी नहीं है । हमारी जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करके र्माण करने के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण पर लगभग 18 करोड़ रूपए की पेनाल्टी लगाई गई थी । पेनाल्टी की यह राशि

वास्तव में कितनी थी और उसका कितना भुगतान प्राधिकरण के द्वारा कब किया गया ? इसके अतिरिक्त क्या 95 लाख रूपए सम्पत्ति कर भी देय है ? क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखण्ड का विक्रय नीलामी के जरिए किया गया था ? यदि हां तो कब तक, कितने भू-खण्डों का किन-किन दरों पर विक्रय किया गया था ?

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एन.सी.एल.टी. का निर्णय है, उसमें मेसर्स गुप्ता से आर.डी.बी. इंफ्रा को शिफ्ट हुआ है, उसमें जो-जो *Responsibility* Decide की गई, उसको आर.डी.बी. इंफ्रा ने पूरा किया है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि आखिर इनको नगर निगम से क्या लेनदारी है ? अगर कोई ऐसा विषय है तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है । उसको पता करके माननीय सदस्य को कल तक बता दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस मामले में किसी को बचाना चाहते हैं, ऐसी कोई साजिश तो नहीं है ? मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं । लेकिन किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने इस प्रकार से उत्तर दिया है । मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न 8 श्री धरमलाल कौशिक की जगह श्री अजय चन्द्राकर जी प्रश्न पूछेंगे ।

<u>बाल्को संयंत्र, कोरबा द्वारा फ्लाई ऐश के उत्सर्जन एवं निष्पादन की शिकायत पर कार्यवाही</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

8. (*क्र. 399) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बाल्को संयंत्र, कोरबा के द्वारा जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक कुल कितना फ्लाई ऐश का उत्सर्जन किया गया है? माहवार जानकारी देवें? फ्लाई ऐश उत्सर्जन एवं निष्पादन हेतु एनजीटी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या नियम वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा इस संबंध में किस अधिकारी के द्वारा कब जांच की गई व जांच में क्या निष्कर्ष दिये गए एवं क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाई ऐश के निष्पादन हेतु, किस स्थान की अनुमति, कब कितनी मात्रा के लिये दी गई तथा इन चिन्हाकित क्षेत्रों में कितनी मात्रा का निष्पादन उक्त क्षेत्रों में किया गया? माहवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाई ऐश निष्पादन हेतु उक्त अवधि में किसे, किस आधार पर व कब कार्य दिया गया था? उनके द्वारा कितने फ्लाई ऐश का परिवहन किया गया? उन्हें कितना भुगतान किया गया है? माहवार, फर्मवार व निष्पादन मात्रावार जानकारी देवें। उक्त कार्य के लिये प्राप्त भुगतान के एवज में कितना जीएसटी जमा किया जाना था, कितना जमा किया गया व कितनी राशि जमा किया

जाना शेष है? **(घ)** कंडिका "क" के कार्य हेतु किसके द्वारा, क्या शिकायत, की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बालको कोरबा के ताप विद्युत संयंत्रों से माह जनवरी 2022 से माह नवम्बर 2023 तक माहवार जनित फ्लाई ऐश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है । फ्लाई ऐश के निपटान हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 30.12.2022) वर्तमान में प्रभावशील है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार है। माहवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ग)** फ्लाई ऐश के अपवहन की जिम्मेदारी संबंधित ताप विद्युत संयंत्र के स्वयं की है । अतः जानकारी निरंक है। **(घ)** जानकारी निरंक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है, उससे संबंधित जो पन्ना है, वही पेज नम्बर 7 गायब है । परिशिष्ट में एक पन्ना ही गायब है तो इस प्रश्न को अगले दिन के लिए रख लिया जाये । क्योंकि जो कार्यवाही बतानी है, उसी का एक पन्ना गायब है तो मैं कैसे पूछूंगा ? कार्यवाही तो हुई नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- अब समझ लौ कि धीरे-धीरे कईसे गायब हो जाथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव, ये ह अकल वाले बात हे ।

श्री रामकुमार यादव :- अकल वाले बात हे, तेखरे खातिर उही मेर बैठे हवव।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जिसमें कार्यवाही होनी है, मुझे जो राजपत्र दिया गया है, उसका एक पन्ना ही गायब है । आप चाहें तो इस प्रश्न को अगले दिन के लिए रख लिया जाये, जब मुझे पूरा परिशिष्ट दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न तो करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो गड़बड़ी हुई है, उसमें कार्यवाही की जो कंडिका है।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपको मंत्री जी बता देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, लेकिन परिशिष्ट में तो गायब है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको उपलब्ध करा देंगे । चौधरी जी बताईए ।

(श्री ओ. पी. चौधरी के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं है, आप क्या बताने जा रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- येती पत्ता गायब होत हे ओती हमर मंत्रिमण्डल ले चन्द्राकर जी गायब होवत जाथ हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पूछिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न में देखेंगे, कुल 52 लाख टन राखड़ निकला है और 16 लाख टन राखड़ का निष्पादन हुआ है। लगभग 35 लाख टन राखड़ का निष्पादन नहीं हुआ है। तो इसका निष्पादन नहीं होने के कारण वह राखड़ कहां पर है ? जो गैर निष्पादित राखड़ है, उसके डिस्ट्राय के लिए क्या-क्या नियम प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक माहवार कितना-कितना राखड़ बाल्को संयंत्र कोरबा के द्वारा उत्सर्जित राखड़ है, उसमें फ्लाई ऐश ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधा-सीधा पाईण्टेड प्रश्न है। इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें सीधा-सीधा प्रश्न है कि आपने जो परिशिष्ट दिया है, उसमें से एक पन्ना गायब है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, वह उपलब्ध करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 35 लाख मीट्रिक टन राखड़ निकला है। एक बाल्को के एक 540 मेगावाट प्लाण्ट से 16 लाख 34 हजार पांच सौ इक्यासी टन राखड़ निकला है। आपने मात्र 16 लाख मीट्रिक टन राखड़ निष्पादित किया है, तो बाकी जो बचा हुआ राखड़ है, वह कहां गया ? इसके निष्पादन हेतु एन.जी.टी. के सम्बन्ध में नियम क्या है ? गैर-निष्पादित राखड़ की स्थिति क्या है, यह आप मुझे बतायें ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो राखड़ निष्पादित किया गया है, उसकी पूरा विस्तृत चार्ट मेरे पास उपलब्ध है। एन.जी.टी. या भारत सरकार के जो नियम हैं, उसके अनुसार बाल्को के ब्रिक्स निर्माण, निचले एरिये के भू-भराव में, माईन भराव में, सड़क निर्माण में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से प्रश्न में आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 16 लाख टन राखड़ का निष्पादन कर दिया। लगभग 36 लाख टन राखड़ जो निष्पादित नहीं हुए हैं, वहां कहां है ? उसकी स्थिति क्या है ? उस सम्बन्ध में एन.जी.टी. क्या कर रही है ? आप क्या कर रहे हैं, यह बतायें ? फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राखड़ निष्पादित नहीं हो पाता है, उसको साइलो में स्टोर करके रखा जाता है। क्रमिक रूप से फ्लाई ऐश निष्पादन की जो अधिसूचना है, उसके अनुसार निष्पादन किया जाता है। मैं इसकी कॉपी भी माननीय सदस्य को जरूर उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने 23 महीने का प्रश्न पूछा है। आप 23 महीने में कितनी बार निरीक्षण करने गये ? जब 23 महीने में 36 लाख टन राखड़ निष्पादित नहीं हुआ तो उसमें पेनाल्टी का भी नियम है, उसमें आप कितनी पेनाल्टी की राशि वसूल किए हैं ? पहले तो आप यह बता दें कि इन 23 महीनों में कितनी बार निरीक्षण करने गये, यह

बताईये ? यदि 23 महीने तक राखड़ का निष्पादन नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं ? यदि निष्पादित नहीं हुए तो आपने उसमें कितनी पेनाल्टी वसूली की है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा इन 23 महीनों में चार बार जाकर कार्यवाही किया गया है। इसमें जो 4 बार कार्यवाही की गई है, उसमें स्थल भराव स्थल, ग्राम कुरूडीह जिला- कोरबा है, वहां पर क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कनिष्ठ वैज्ञानिकों ने ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब-कब, कहां-कहां कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी चाही गई है, मैं वही जानकारी बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सुनिये न। (सदस्य श्री कवासी लखमा द्वारा पूछे कहे जाने का प्रयास किये जाने पर) एक तो आप सीनियर विधायक हैं, आपको बैठे-बैठे बोलना नहीं चाहिए। बैठे-बैठे बोलना है तो आप न्याय यात्रा में जाओ।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, यह ना तो आपका प्रश्न है ना आपसे सन्दर्भित है। कृपया बैठकर ना बोले, कोई प्रश्न करना है तो आप अनुमति लेकर बोले तो अच्छा है। आप बहुत सीनियर हैं। कृपया इसकी चिंता करें।

श्री रामकुमार यादव :- ये चन्द्राकर जी भी बैठे-बैठे बोलथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एन.जी.टी. सख्त कार्यवाही करती है। पर्यावरण का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने इन 23 महीनों में 36 लाख टन राखड़ का निष्पादन नहीं किया। उसका निष्पादन ना करके सड़कों में बिछा दिया, कहीं भी फेंक दिया गया।

श्री रामकुमार यादव :- अनचेती चल दिस, ओला फेके नहीं हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठ ना यार, एन.जी.टी. के मतलब भी नहीं जानथ अऊ ओ हा पूछथ हे।

श्री रामकुमार यादव :- जानथंव साहब, जानथंव मैं । तुमन जब ले आय हव राखड़ ला किसान के खेत म फेंकथव । यही ल त पूछथे ? राखड़ कहां हे किहिस, कंपनी ला सौंप दे हव । वही ल त पूछथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- होगे ? और किसी को टोकना है तो टोक लो ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृपया बैठिये । आप प्रश्न करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा आपने निष्पादन कहां-कहां किया, यह नहीं है । मैंने यह पूछा कि कितनी बार आपने निरीक्षण किया है, आपने चार बार बताया है और कितनी बार करना चाहिये ? निरीक्षण के बाद जब निष्पादन नहीं हुआ तो की गई कार्यवाही और उसमें पेनाल्टी के क्लॉज हैं तो कितनी पेनाल्टी वसूल की गई, यह है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा था । माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत जायज है, जितना राखड़ फ्लाई ऐश का उत्पादन हो रहा है, उसका निष्पादन हो रहा है कि नहीं ? जो चार्ट उपलब्ध कराये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि फ्लाई ऐश का जितना प्रतिमाह उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा यूटिलाईज हो रहा है, उसमें डिस्पोज करने के दो अलग-अलग टेबल हैं, उन दोनों को एक करके माननीय सदस्य देंखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जायेगा कि जो मंथली प्रोडक्शन है, उससे ज्यादा यूटिलाईजेशन प्रतिमाह हुआ है । उनका पुराना जो बचा हुआ था, उसका भी फ्लाई ऐश डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है और जो कार्यवाही की गई है, मैं उसी का विवरण दे रहा था । ग्राम कुरूडीह का निरीक्षण किया गया है, ग्राम ढ़ोकदरहा का निरीक्षण किया गया है, ग्राम कुकरीचोली का निरीक्षण किया गया है, ग्राम पांड़ीमार का निरीक्षण किया गया है । 11 सितम्बर 2023 को दो निरीक्षण किये गये हैं और 13 सितम्बर 2023 एक निरीक्षण किया गया है, 12 सितम्बर को 2023 को एक निरीक्षण किया गया है । इस तरह से वर्ष 2023 में चार निरीक्षण किया गया है । इसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितना-कितना पेनाल्टी इम्पोज किया गया है तो 1 लाख 25 हजार प्रथम केस में, 1 लाख 25 हजार दूसरे केस में और तीसरे केस में 1 लाख 25 हजार किया गया है और चौथे केस में 3 लाख की पेनाल्टी इंपोज की गई है । अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने पेनाल्टी का प्रोविजन जानना चाहा है तो जो फ्लाई ऐश डिस्पोज हुआ रहता है, उसमें प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी इंपोज किया जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों का, मैंने जो पढ़ा है, चूंकि यह पर्यावरण से और एनजीटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है । आपने मुझे जो 540 मेगावाट का बताया है और 1200 मेगावाट का अलग-अलग बताया है । आपने दोनों को अलग-अलग बता दिया, थैंक्यू । लेकिन, कुलमिलाकर लगभग 36 लाख निष्पादित नहीं हुआ और वह पन्ना गायब है । आप कृपा करके मुझे यह बतायें कि एनजीटी की कितनी बार उनको निरीक्षण करना चाहिये ? आपने 23 महीने में चार बार कहा है, एनजीटी के नियमानुसार कितनी बार निरीक्षण करना चाहिये ? 36 लाख मिट्रिक टन निष्पादित नहीं हुआ है तो पेनाल्टी कितनी वसूल होना चाहिये ? दोनों में एनजीटी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है तो आपने डिपार्टमेंट के ऊपर, जांच करने वाले के ऊपर, कम पेनाल्टी वसूलने वालों के ऊपर क्या कार्यवाही की है? यह मुझे जानना है । आप जो 36 लाख बकाया है, जो आप कह रहे हैं कि उसको भी निष्पादित करने की कोशिश हो रही है, अब तक जो बकाया है, आप उसको कब तक निष्पादित कर लेंगे ? जितना आपने निष्पादित किया है, वह कई गुना ज्यादा है, यह मैं जानना चाहता हूँ । उस पर स्पेसिफिक बता दीजिए ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो फ्लाई ऐश उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा का निष्पादन होता जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा । चलिये, अंतिम प्रश्न करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाये । मैंने यह कहा कि जो 36 लाख डम्प है, वह मैंने मान लिया । 36 लाख जो डम्प है, वह मैंने पूछा है और दूसरा उसका निष्पादन कब तक, किस तरह से करेंगे ? आपको नियमों के तहत कितनी बार जांच करनी चाहिये ? आपने कितनी बार जांच की है ? नियमों के तहत 36 लाख में कितना पैसा जुर्माना या पेनाल्टी वसूल होना चाहिये ? कितना पेनाल्टी वसूल हुआ और दोनों काम नहीं किये हैं, उसके ऊपर क्या कार्यवाही किये ? यह मेरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कार्यवाही बता दीजिए ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में किया जाना है, यह नहीं किया गया है । मुझे भी लगता है कि जितने बार इंसपेक्शन किया गया है, वह कम है । हम भविष्य में ज्यादा फ्रिक्वेंट इंसपेक्शन विभागीय रूप से कराते रहेंगे । सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में करना है, यह कानून में नहीं लिखा है। जनसामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इसको देखेंगे और माननीय सदस्य ने जो पेनाल्टी की बात कही है, मैं उसको भी विभागीय रूप से चेक करा लूंगा कि जो पेनाल्टी इंपोज की गई है, वह गलत तो नहीं की गई है या कम तो नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पर्याप्त न हो तो कर देना । धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ?

श्री रामकुमार यादव :- इसी में ।

अध्यक्ष महोदय :- करिये । ठीक है, इनका भी कर दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, मोर आपसे निवेदन हे कि मोर एरिया हा, तोर समय कलेक्टर रहात ले वो समय कंपनी खोले रहिसे, आज किसान मेर राखड़ ला फेंक के भाग जाथे । बिहनिया खेत जावथे अऊ संझाकन राखड़ पटा जावथे । ऐसे-ऐसे शिकायत मिले हे । आपसे निवेदन हे कि वोमा कार्यवाही करिहव का ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी को लिखकर दीजिए ?

श्री रामकुमार यादव :- अउ दूसरा, ओमन गाड़ी मा गली-गली मा राखड़ हर ढो के निकालथे। जब-जब उठात जाथे। मे हर आप ला लिखकर दिहा, आप मन एला मना करिहा। आप दमदार कलेक्टर हरे तो एला करिहा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ? आप कहां सुकमा क्षेत्र के हैं और आप कोरबा आ गये। चलिये, पूछिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्राकर जी का दिल इतना जल रहा था। एक तो यह वरिष्ठ सदस्य, कौशिक जी का प्रश्न था। चन्द्राकर जी भी वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाने से वह कितने जल रहे हैं। ये विद्वान सदस्य मंत्री बन गये तो इनको दिल से खुल के बता रहे थे कि उनका दिल जल रहा था, इसलिये वह भाग गये। वह बहिर्गमन करके चले गये।

अध्यक्ष महोदय :- आप दु:खी तो नहीं है ?

श्री कवासी लखमा :- मैं तो ठीक हूं।

अध्यक्ष महोदय :- तब ठीक है।

महासमुंद जिले में पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि का आवंटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (*क्र. 872) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महासमुंद जिले में पिछले 03 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 10-01-2024 तक पीड़ित क्षतिपूर्ति के तहत कितने पीड़ितों को कितनी राशि आबंटित की गई है? वर्षवार हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी बतायें? **(ख)** प्रश्न "क" में उल्लेखित अवधि के दौरान कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं? वर्षवार हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[3] अनुसार है। **(ख)** उल्लेखित अवधि के दौरान महासमुंद जिले में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिम जाति विकास मंत्री महोदय से यह पूछना चाहत हव कि महासमुंद जिले में पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 10.01.2024 तक पीड़ित क्षतिपूर्ति के तहत कतेक पीड़ित मन ला कतेक राशि आवंटित करे गे हे ? वर्षवार हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी बतायें ?

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में जवाब दिहा।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे हिन्दी में बोलना है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको जो भी भाषा पसंद है, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर हिन्दी, छत्तीसगढ़ी में बोल सकती हैं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, तै ये बिढ़या से देख ले। एकर परिशिष्ट में पूरा नाम सहित विवरण दर्ज है। आप मन ओला देख लो अउ कोई दिक्कत होही तो फिर से मोर से मिल लेबे, बात कर लेबे। मे ओला निपटाये देव।

---

[3] परिशिष्ट ''चार''

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, मोला दिक्कत हावय, तभी तो प्रश्न लगाय हव।

अध्यक्ष महोदय :- चातुरी नन्द जी, आप प्रश्न करिये।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, उल्लेखित अवधि के दौरान कतेक प्रकरण का-का कारण से लंबित हे ? वर्षवार हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी बतायें ?

श्री रामकुमार यादव :- तै जल्दी-जल्दी बोल ता ओती साय-साय दीहि।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी रख दूंगा। यदि विशेष रूप से किसी का नाम बचा है तो वह दे दें। मेरे पास पूरी जानकारी है कि किन-किन कारणों से प्रकरण लंबित है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिये।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, ए मा ऐसे लइका मन हे, जे मन के प्रथम किश्त तो मिले हे। लेकिन अभी तक द्वितीय किश्त नहीं मिल पाये हे। जैसे एक झरनादास नाम के लइका हे। यह बसना ब्लॉक के लइका हे अउ एकर उपर पॉक्सो एक्ट लगे रिहीसे। आवेदन करै के बाद भी ये लइका मन ला पहली किश्त मिले हे लेकिन एकर दूसरी किश्त अभी तक के जमा नइ होये हे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिये।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं एला दिखवा के दिलवाये दूंहू।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनको कब तक दूसरी किश्त दिलवायेंगे ? यह बता दीजिये।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, मे हा ये जानना चाहत हव कि ओला दूसरी किश्त कब तक मिल जाही ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उनको कब तक दूसरी किश्त मिल जायेगी। बता दीजिये।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र।

अध्यक्ष महोदय :- श्री आशाराम नेताम जी।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न है ?

श्रीमती चातुरी नन्द :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- करिये, करिये।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, मे हा ये जानना चाहत हव कि यह जो पीड़ित क्षतिपूर्ति हे, एला कतेक दिन में देय के शासन के आदेश हे ? ए मा कतेक दिन में निराकरण होना चाहिए अउ एकर निराकरण हर काबर अतका लंबा जाथे ? मे एकर जानकारी चाहत हव।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इसमें अलग-अलग धाराएं और जो अलग-अलग संज्ञेय अपराध हैं, उसके तहत प्रकरण दर्ज होते हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद उसकी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तफतीश होती है और वह न्यायालय तक जाता है। उसके अलग-अलग केस के आधार पर उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। जैसे किसी को सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिये अलग से प्रथम सूचना रिपोर्ट में 25 प्रतिशत राशि देते हैं। जब आरोप पत्र न्यायालय भेजा जाता है तो 50 प्रतिशत राशि देते हैं फिर यदि वह न्यायालय से दोषसिद्ध होता है तो उसे फिर से 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। अलग-अलग अपराध के आधार पर राशि निर्धारित है, उसके तहत क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय
12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूँ।

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005(क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 के नियम 22 एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूँ।

(5) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-21

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं,वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 202-23

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूँ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) पटल पर रखता हूँ।

(8) राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

12.03 बजे

ध्यान आकर्षण सूचना

(1) नवा रायपुर स्मार्ट सिटी तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को कार्य आवंटित किया जाना

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बिना दस्तावेजों की जांच किये, बिना तकनीकी दक्षता देखे, मिलीभगत करके करोड़ों रूपये के काम अपात्र कंपनियों को दे दिए गए हैं। अधिकारियों से मिलीभगत के चलते दोनों स्थानों पर लगभग 1000 करोड़ रूपये के काम अपात्रों को आवंटित किये गये हैं, जिसे उन अपात्र कंपनियों ने सबलेट कर दिया है। इस प्रकार से नियमों के प्रतिकूल की गई कार्यवाहियों की सूक्ष्य जांच हेतु एक उच्चधिकार प्राप्त समिति का गठन जरूरी है। अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर मामले को दबाए जाने के कारण जन साधारण में अत्यंत रोष व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत एक स्मार्ट शहर की परिकल्पना, एक विकसित प्लानिंग के साथ में शहर बसना चाहिए, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों, जो एक शहर की आवश्यकता होती है। रायपुर शहर या नया रायपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये आने के बाद जिस प्रकार से स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ। अस्थाई काम जो नगर निगम काम कर सकता है, जिसको हम नान टाईन्ट फंड बोलते हैं, नगर निगम को 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये दे दो।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, मंत्री जी का वक्तव्य आया नहीं है, आप प्रश्न करने लगे हैं। मंत्री जी का वक्तव्य पहले सुन लीजिए। उससे जो प्रश्न उद्भूत होगा, उसके बाद आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। चलिये, माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही नहीं है कि नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बिना दस्तावेजों की जांच किये, तकनीकी दक्षता देखे बिना मिलीभगत करके करोड़ों रुपये के काम अपात्र कंपनियों को दे दिये गये हैं। वरन तथ्य यह है कि नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत सभी स्वीकृत परियोजनाओं प्रोजेक्ट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी मूल्यांकन समिति के द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा किये जाने के पश्चात पात्र निविदाकारों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वित्तीय प्रस्ताव खोले गये। तत्पश्चात वित्तीय मूल्यांकन समिति के द्वारा वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन कर न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदाकार को कार्यादेश प्रदान करने की अनुशंसा की गई। वित्तीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम दर पर आमंत्रित निविदा को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यादेश जारी किया गया। यह भी सत्य नहीं है कि सक्षम निविदाकार द्वारा उनको आवंटित कार्यों को सबलेट कर दिया गया है। कुछ प्रकरणों में ओल्ड रायपुर स्मार्ट सिटी के प्रकरणों में भी सबलेट का जो 25 प्रतिशत तक प्रावधान है, उसमें किया गया है।

इसी प्रकार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर अंतर्गत सभी स्वीकृत परियोजनाओं हेतु खुली निविदा आंमत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी मूल्यांकन समिति एवं स्मार्ट सिटी हेतु नियुक्त पी.एम.सी. (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंसी) के द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा किये जाने के पश्चात पात्र निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोले गये। तत्पश्चात वित्तीय मूल्यांकन समिति/पी.एम.सी. (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंसी) के द्वारा वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन कर न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदाकार को कार्यादेश प्रदान करने की अनुशंसा की गई। वित्तीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम दर पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त पर कार्यादेश जारी किया गया। निविदा शर्तों के अनुरूप कुछ निविदाकार द्वारा उनको आवंटित कार्यों में से कुछ भाग को अनुबंध की शर्तों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सबलेट किया गया है।

यह कथन भी सही नहीं है कि अधिकारियों से मिलीभगत के चलते दोनों स्थानों पर लगभग 1000 करोड़ रुपयों के काम अपात्रों को आवंटित किये गये है एवं अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर मामलों को दबाए गये हैं। अत: नियमों के अनुकूल की गई कार्यवाहियों की सूक्ष्म जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कार्य संपादित किया गया है एवं मामले को दबाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अत: यह कहना सही नहीं है कि जन साधारण में रोष व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा वक्तव्य है। बाकी आदरणीय सदस्य महोदय के जो भी विशेष बिन्दु हैं, उन्हें रखें तो उसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला ही प्रश्न कर देता हूं। यह नया रायपुर का उत्तर है, रायपुर का उत्तर कहां है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आवास पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है, वह भी हमने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उनसे हमने ले करके सेकंड पैराग्राफ में यह जानकारी रखी है। बाकी सदस्य महोदय के जो भी विशेष बिन्दु हैं, उसको एड्रेस करने का हम दोनों प्रयास करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- चलिये, आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आप भी रायपुर के कलेक्टर, कमिश्नर भी रहे हैं और नगर निगम में आपने काम भी किया है। मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं कोई व्याख्या नहीं करता हूं और न कोई भूमिका बांधता हूं, सीधा प्रश्न पर आ जाता हूं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आई, उसमें रायपुर, नया रायपुर, बिलासपुर और अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया, जिसकी 926 करोड़ रुपये की 70 मुख्य परियोजनायें एवं 314 उप-परियोजनायें स्वीकृत हुईं। इसमें कितनी परियोजनायें पूर्ण हैं और कितनी अपूर्ण हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, उसमें कुल 14 टेण्डर के कार्य थे। उस 14 पैकेज में से जो 10 पैकेज धीमी गति से चल रहे थे, उसका Total value 399 करोड़ रूपये का था, उसको जो पहले contractor था, उसी के risk and cost पर धारा-14 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है। उसमें 180 करोड़ का काम हो चुका था, बाकी जो काम चल रहे थे, उसको 399 करोड़ के 10 पैकेज को निरस्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह चिंता जायज है कि वह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे थे। हमने पिछले 10 पैकेज को already निरस्त करने की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें Total 399 करोड़ रूपये का टेण्डर पैकेज था और नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो कुल कार्य हैं, उसमें कुल मिलाकर 55 कार्य थे, उसमें से 7 कार्य पूर्ण हैं और 48 अपूर्ण कार्य हैं। माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल जायज है कि वह कार्य धीमी गति से चल रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो नया रायपुर की जानकारी बता रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायपुर शहर के अंदर 185 परियोजनाएं और 314 उप परियोजनाएं हैं, उसमें कितने में कार्य पूर्ण हुए और कितने कार्य में धीमी गति से काम चल रहे हैं ? यदि आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नवा रायपुर में जो धीमी गति से काम चल रहे थे, उसके अंतर्गत हमने लगभग दो तिहाई पैकेज, लगभग 65 प्रतिशत पैकेज को already निरस्त कर दिया है। जबकि भारत सरकार से कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, फिर भी हमने उसको वहां से विशेष चर्चा करते हुए निरस्त कर दी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि जो पुराना रायपुर है, उसको हम नगरीय प्रशासन विभाग से जानकारी लेकर माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह कह रहे हैं कि जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब आप एक decision कर सकते हैं। वर्ष 2018 की स्कीम चल रही है और केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद कर दी है। आखिरी में बंदरबांट किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें उदाहरण देता हूं। आप भी राजधानी में आते-जाते रहते हैं। यहां सचिव रहते हैं, पी.एस. रहते हैं। ओ.पी. चौधरी जी यहां के कमीश्नर रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं। स्मार्ट सिटी ने पूरे रायपुर शहर के ट्रेफिक कंट्रोल करने के लिए 209 करोड़ रूपये खर्च किए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको बार-बार क्यों याद करा रहे हैं कि वह यहां के कलेक्टर रहे हैं। वह कब का कलेक्टर पद छोड़ चुके हैं। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, अभी भी हैं। इंटरेस्ट पूरा है। इनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। इनके नेतृत्व में तेलीबांधा तालाब बना है। बहुत से अच्छे काम हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी ने रायपुर में ट्रेफिक कंट्रोल करने के लिए 209 करोड़ रूपये खर्च किए। मल्टी लेवल पार्किंग में 28 करोड़ रूपए खर्च किए गए। बूढ़ा तालाब तो प्रयोग का केन्द्र बन गया। जब से लेकर राज्य बना है, तब से लेकर आज तक वहां लगभग 5 एजेंसियां काम कर चुकी हैं। वही खम्भा जिसके ऊपर लाईट लगी और वही खम्भा हटाकर जिस पर सोलर पैनल लगा, वह सोलर पैनल को हटाकर खम्भा लगाकर उसमें सिर्फ एक लाईट लगा दी गई। उसने रोड बंद कर दी। माननीय बृजमोहन जी ने अभी वह रोड खुलवाई। शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 40 लाख के काम करने का प्रावधान है? अध्यक्ष महोदय, शहर के अंदर यह स्थिति बन गई कि मूल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जीरो कर दिया गया। इस रायपुर शहर में सिर्फ 5 बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, जिसका सदुपयोग नहीं होता है। दोनों पार्किंग में दूसरे काम चल रहे हैं। एक तेलीबांधा तालाब बना है, जिसमें प्राईवेट सेक्टर को दुकान लगाने की जगह दे दी गई। बूढ़ातालाब, इसके अंदर एक स्मार्ट रोड नहीं बनी है। स्मार्ट रोड की परिभाषा क्या है ? इस रायपुर शहर ने एक नया प्रयोग कर लिया- "चौपाटी" । मुझे थोड़ा समझा दें कि जिसकी शासकीय लेण्डयूज जीरो है, जहां खेल का काम होता है, जहां पर ऑलरेडी कॉलेज, यूनिवर्सिटी है और आपने Youth hub का टेण्डर किया तो Youth hub कैसे चौपाटी में परिवर्तित हो गया और किसने किया? माननीय मंत्री जी, कृपया केवल इसी प्रश्न का स्पेसीफिक उत्तर दे दें ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है उसमें कुल परियोजनाओं की संख्या 312 है । उसमें पूर्ण कार्य 300 हैं और जो कार्यादेश एवं प्रगतिरत हैं वह 12 हैं अर्थात् 12 अपूर्ण हैं । इसमें माननीय सदस्य ने चौपाटी का जो विषय रखा है और इसमें जो बिंदू रखे हैं । जिस एजेंसी के पास चौपाटी के ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य था उसको रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपने जिस चीज का टेंडर किया है उसमें स्कोप (Scope) का जो प्रावधान था। ग्रीन कॉरीडोर Youth hub, पहला तो टेंडर करने के बाद नियम स्पष्ट है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते । मास्टर प्लान में उस जमीन का लेण्डयूज अर्धशासकीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में दर्ज है और वह जो जमीन है वह खेल विभाग के पास है । बिना एन.ओ.सी. के, हमें केवल यहीं पर गुमराह नहीं कर रहे हैं । मैं इस प्रकरण में हाईकोर्ट तक गया हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न में आ जाईये ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इसको बिना जानकारी के किसी ने किया है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही कर यह चौपाटी बंद करने की घोषणा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जवाब दे दीजिये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चौपाटी के ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है और Youth hub से इसे चौपाटी के रूप में कैसे कन्वर्ट किया गया उसको नगरीय प्रशासन विभाग से जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो इतने सारे दस्तावेज हैं चूंकि लैण्डस्केपिंग 2 करोड़ रूपये की, 8 करोड रूपये का वृक्षारोपण यह सब क्या किया है ? क्या सरकार नाम की कोई चीज थी या नगर-निगम में जिसकी इच्छा हो, वह जो करना चाहे वह कर सके । मैं इन दस्तावेज के साथ में यह बोल रहा हूं, मेरे पास नगर-निगम के दस्तावेज हैं । नगर-निगम ने हाईकोर्ट को भी गुमराह किया है, नगर-निगम हाईकोर्ट में जाकर कहता है कि काम कम्पलीट तो आपने किसका टेंडर लगाया है ? Youth hub ग्रीन कॉरीडोर । न तो Youth का कुछ बना और न ही ग्रीन कॉरीडोर है । आपने तो वहां पर टिन-टप्पर की चौपाटी खड़ी कर दी और इतनी जल्दी क्या थी कि आचार संहिता के पहले चौपाटी के एलॉटमेंट का टेंडर कर दिया । जब मालूम है कि कोर्ट में केस चल रहा है, निर्णय आया तो इतनी जल्दी क्या थी ? वह चौपाटी किसके नाम पर बनी ? इसके पीछे किनका संरक्षण था ? मेरा स्पष्ट मत है कि जिन लोगों ने भी यह गलत काम किया है । चूंकि आपका स्पष्ट नियम है कि जब तक लेण्ड हमारे पास...।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हाईकोर्ट में जिसका मामला चल रहा होता है उस पर यहां बहस होती है ?

श्री राजेश मूणत :- हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है । भैया, आप बैठ जाईए ।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन तो कानून वाला हओ । साहब जी ला बुद्धिमान बताथे, ओ कलेक्टर साहब हे ।

श्री राजेश मूणत :- आप बैठ जाईये । आपको समझ में नहीं आयेगा । यह सब गड़बड़ी आपके ही कार्यकाल की है । बैठ जाईये ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर कार्यकाल में तो किंदरत हओ, 5 साल मा काय करिहा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आपके पास लेण्ड नहीं होगा तब तक आप काम चालू नहीं कर सकते और जब कोई कर नहीं सकता तो किन व्यक्तियों ने उसकी स्वीकृति देकर वह काम पूर्ण किया ? उसके स्कोप (Scope) में जिस चीज

का प्रावधान था वह स्कोप (Scope) चेंज करने का अधिकार किसको था ? बिना किसी जानकारी के उसने कैसे कर दिया ? आप कृपया इसका स्पष्ट उत्तर दे दें और जिन अधिकारियों ने यह किया है तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हम लगभग 13 दिनों तक वहां पर चौबीसों घंटे भूख-हड़ताल पर बैठे हैं । आप भी आये, जूस पिलाकर हमारा अनशन तोड़ा । पार्टी के पूरे नेता लोग आये हैं । स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर के अंदर जिस प्रकार की लूट मचाकर रखी थी । जो गोरख धंधा चला है, लाइट लेलो, 30 परसेंट दे दो, जहां चाहे वहां लाइट लगा दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको गिनाउंगा, मेरे पास इससे संबंधित पूरी चीजें हैं, अगर आप कहेंगे कि मंत्री जी को दे दो तो मैं मंत्री जी को देने को तैयार हूं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? इसलिए स्पेशिफिक प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों ने नियम के विपरीत जाकर काम किया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और वहां पर आसपास हमारे बच्चे रहते हैं। एज्यूकेशन हब है, वहां एन.आई.टी. है, वहां आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां साइंस कॉलेज है। रविशंकर विश्वविद्यालय है। उसके बीच में चौपाटी खोलकर क्या दर्शाना चाहते हैं भाई? क्या वहां चौपाटी की जगह लाइब्रेरी या ऐसी कोई चीज बनायेंगे? स्पष्ट घोषणा करें, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है और वे स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहे हैं और वह क्षेत्र उनका constituency भी रहा है और उस क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम किये हैं। ऑडिटोरियम हो, नालंदा परिसर हो, ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण हो और जब तक उनका कार्यकाल रहा, उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, पर बाद में वाकई बहुत सारी दिक्कतें वहां पर आयी हैं, इससे कोई इंकार नहीं है और जो चौपाटी की बात है उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस के काम को ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है और आगे उसमें विभागीय जांच की जायेगी और कैसे उस जगह की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित की जा सकती है, इसके संबंध में हम काम करेंगे। चौपाटी हटाने के संबंध में भी अर्बन डेव्लपमेंट डिपार्टमेंट से चर्चा करके हम उसमें भी निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, समय-सीमा में सब काम कर दें।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी। और जो गलत है, उस पर जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत अच्छा जवाब आ गया।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको, आपके डिपार्टमेंट को और उप मुख्यमंत्री, श्री अरूण साव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो जिस साहस और विश्वास के साथ में सरकार आयी है, जिन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि जो प्रतिवेदन और जो हमने लगभग इस शहर के 400 परियोजनाओं को जिन्होंने छोटी-छोटी

परियोजनाओं में बांट दिया है, क्या उसका नगर-निगम की भा.ज.पा. पार्षद दल के नेता और इनके साथ बैठकर एक बार परीक्षण करेंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री जी से चर्चा करके जो ओल्ड रायपुर क्षेत्र है, उसमें भी हम पूरा देखेंगे और जांच करायेंगे और माननीय सदस्य महोदय से और नेता प्रतिपक्ष इन सबसे भी सलाह लेकर उचित कार्रवाई करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, हो गया। इतना स्पष्ट जवाब आने के बाद..।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहीं बैठे हैं, इसमें आपस में चर्चा क्या करनी? दोनों यहीं बैठे हैं। एक ही चीज का निर्णय है। जो गलत है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं..।

श्री राजेश मूणत :- एक मिनट। फिर आप पूछ लेना। सर, मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर जनप्रतिनिधि को नहीं पूछ रहे हैं, उनके क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ काम कर दे रहे हैं, कहीं कोई काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक कंपनी बनाकर जनप्रतिनिधि को किनारे करके अपने हिसाब से अपना निर्णय करके वहां के 20-20, 25-25 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद को मालूम नहीं कि उसके यहां पर क्या काम हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय :- वे अब करेंगे। बता दिया न। आप उन्हें बस धन्यवाद दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं। उप मुख्यमंत्री जी नगरीय प्रशासन बैठे हैं। वे बहुत ही संवेदनशील हैं। वे सब चीजों को जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी का बयान सरकार का बयान है और उनकी तरफ से बयान आ गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। बघेल लखेश्वर जी। ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे।

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विद्वान सदस्य ने केवल भा.ज.पा. के पार्षद को शामिल करने की बात कही, वह अनुचित है। निर्वाचित पार्षदों की बात होनी चाहिए। निर्वाचित पार्षद को उसमें सम्मिलित करने में क्या आपत्ति है?

श्री राजेश मूणत :- उन्हीं लोगों ने तो गड़बड़ किया, पूरे शहर को बेच खाया जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- निर्वाचित पार्षद हा पार्षद होथे। आप मन विधायक हो, हम भी विधायक हन। हर चीज का बी.जे.पी.। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- जब मेयर ने भा.ज.पा. के पार्षद को पूछना उचित नहीं समझा। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद क्यों रहेंगे? नहीं नीति में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही उसमें सम्मिलित होंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हीं मन तो बनाये रहो। (व्यवधान) नींबू में बिलई रेंगथे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- निर्वाचित पार्षद होते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पुरंदर जी, आपको क्या पूछना है? चलिए, आप भी एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सर बिलासपुर भी स्मार्ट सिटी है, इसलिए एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका विषय नहीं है । रायपुर के विधायकगण बोल सकते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- ओखर तरी मा रेंगथन तो डर्राथन, का बनाए हौ ता ओला तोड़व या ओला बनाव ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- रायपुर को विकसित करने के लिए मेरे उत्तर विधान सभा में मल्टी पार्किंग बन गया क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मल्टी पार्किंग के बारे में जवाब दे दीजिए, ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- कलेक्टोरेट वाला ?

श्री पुरंदर मिश्रा :- जी ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- कलेक्टोरेट वाला मल्टी पार्किंग बन चुका है । मेरी जानकारी के अनुसार वह रायपुर नॉर्थ में ही आता है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- उसको किसकी देखरेख में रखा गया है, यह बता पाएंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- इसका ऑपरेशन/मेंटेनेंस किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी जानकारी मैं नगरीय प्रशासन विभाग से लेकर उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- मुझे चिंता इस बात की है कि पिछले समय खबर पढ़ने को मिली थी कि यहां बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या उसी के लिए उसको छोड़कर रखा गया है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह विशेष कन्सर्न का विषय है । जिस पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से और उस जगह को बेहतर से बेहतर कैसे संचालन हो सके । क्योंकि पिछली सरकार के समय उसे बहुत अच्छी तरह से विकसित किया गया है । उसमें माननीय सदस्य महोदय की सलाह लेकर काम करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुरंदर मिश्रा :- एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न हो गया ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- एक छोटा सा प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा और है ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- शहर के मध्य स्थित सी.एम.हाऊस पास बहुत बड़ा गार्डन है, जहां लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भ्रमण किया करते थे । वह कब तक बन जाएगा, यही पूछना चाहता हूं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- गांधी उद्यान ?

श्री पुरंदर मिश्रा :- जी हां ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र आपकी सरकार में 2018 से पहले 19 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया है । वहां पर तमाम तरह के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, उस जमीन की वेल्यू 1004 करोड़ रूपए है । उसके बावजूद उस समय की सरकार ने उसको अर्बन फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया । जो लंग्स ऑफ सिटी के रूप में काम कर रहा है । जो गांधी उद्यान है उसको भी माननीय सदस्य से चर्चा करके दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए पर्याप्त हो गया ।

<u>(2) नारायणपुर जिले में एक आदिवासी किसान द्वारा बैंक से लिये गये कर्ज को अदा नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या की जाना.</u>

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश की सरकार के दिग्गजों द्वारा चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी को लेकर मंचों व पम्पलेटों व विज्ञापनों क माध्यम से किये गये वायदों का चुनाव के बाद उनके मुखिया की गारंटी का हिससा न बताना, उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है । यह सरासर आम जनता विशेषकर किसानों के साथ किया गया अन्याय है और किसानों से किया गया यही अन्याय बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले के एक आदिवासी किसान स्व. हीरू की मौत का कारण बना है । गरीब आदिवासी किसान स्व. हीरू ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लेम्प्स समिति से रूपए 1,11,282 का कर्ज लिया था । वह इस राशि को पटाने में अपने आपको असमर्थ पा रहा था । चुनाव के दौरान उनके मुखिया की गारंटी को पूरा करने की गारंटी देने वाली पार्टी के द्वारा किसानों को 02 लाख रूपए तक का कर्ज माफ करने की गारंटी देने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बाद, चुनाव जीतने के बाद अपनी बात से मुकर जाने के कारण स्व. हीरू अवसद में चला गया और बाद में यह गारंटी ही उसकी मौत का कारण बन गयी । 09 अक्टूबर, 2023 को चुनाव की घोषणा के बाद 24 अक्टूबर 2023 को स्व. हीरू को बैंक नोटिस, 03 दिसम्बर 2023 को नवगठित सरकार के द्वारा अपने ही वायदे से मुकर जाना और 12 दिसम्बर 2023 को स्व. हीरू के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना हुआ है । नई सरकार के द्वारा किये गये अपने वायदे से मुकर जाना इस परिवार के मुख्य कर्ताधर्ता की मौत का कारण बना । परिवार अपने मुखिया, कर्ताधर्ता की मृत्यु से दुखी व सरकार के प्रति गुस्से में है । परिवार के साथ ही पूरे बस्तर क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं व स्व. हीरू व उसके परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं ।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि मृतक किसान स्व. श्री ही द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर अंतर्गत जिला नारायणपुर की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लेम्प्स) से रू. 1,11,282 का ऋण लिया था एवं राशि पटा पाने में असमर्थ था, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि मृतक स्व. श्री हीरू नारायणपुर जिले के किसी भी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लेम्प्स) अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का ऋणी कृषक नहीं था। अत: उनको बैंक/लेम्प्स द्वारा वसूली के लिए नोटिस जारी करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मृतक स्व. श्री हीरू की मृत्यु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उनकी मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से दिनांक 13.12.2023 को हुई थी, वे विगत् दो-तीन माह से बीमार चल रहे थे।

अत: उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि पूरे बस्तर क्षेत्र के लोग आक्रोषित है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मृतक के नाम से ऋण नहीं था। यह सत्य है, लेकिन वह घर का मुखिया था, एक लमसेना के रूप में कोयलीबेड़ा का निवासी था। वह 40-50 साल पहले घर जमाई के रूप में लमसेना के रूप में वहां पर था। उसकी सास 70 वर्षीय थी और उनकी देखभाल का जिम्मा, उनके परिवार का जिम्मा हीरू राम का था। यह कहना गलत है कि हीरू राम इस प्रकार का नहीं था। सास का कर्ज उनके नाम से पटता था, वह सब कुछ था, एक लमसेना के नाम से पटा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने सास के नाम से 1,11,282 रू. कर्ज लिया था। यह कहना गलत है कि उसके नाम से नहीं था, लेकिन वह मुखिया तो था, मुखिया की जवाबदारी होती है, लमसेना के रूप में 40-50 साल से आया था। उसके रूप में काम कर रहा था तो वह कर्ज उनके नाम से नहीं था लेकिन वह घर का मुखिया था। वह दहसत में था। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान पार्टी के द्वारा बड़े जवाबदार लोग 2 लाख रूपये कर्जमाफी की घोषणा किए थे, चाहे वह सोशल मीडिया, विज्ञापन या पाम्पलेट के थ्रू हो, अब वह मुकर जा रहे हैं कि नहीं था। वह दहसत में था, हमने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, वहां स्वयं विधायक दल पहुंचे थे। वहां गांव के लोगों और परिवार के लोगों का स्पष्ट कहना था कि कोई बीमार वगैरह नहीं था, वह खेती मिंजाई का काम कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए ना।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि क्या मंत्री महोदय यह घोषणा करेंगे कि उनको कोई अनुदान देंगे या उनका कर्ज माफ करेंगे ? यह मंत्री जी के इतने बड़े क्षेत्र का मामला है, उनका कर्ज माफी हो या उनका कोई मुआवजा घोषित करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि जो संबंधित मृतक है, वह बैंक का ऋणी नहीं रहा है, वह घर जमाई के रूप में था। जिनके नाम से खाता है उनको वर्ष 2014-15 की बोनस की राशि 18480 रूपए दी गयी है। चूंकि वह मेरा ही विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, विपक्ष वहां पर जबर्दस्ती जाकर ऐसा माहौल क्रियेट कर रहा था कि उसने ऋण के कारण से आत्महत्या की है। उन्होंने ऋण के कारण आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि वह मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मैंने वहां पर पता भी लगाया। उनके बीच में आपस की लड़ाई हुई, उनके बेटे के साथ लड़ाई हुई और लड़ाई के कारण से उसने जहर खा लिया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर को एक प्रश्न और करने दीजिए।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप मृतक परिवार के लिए क्या चाहते हैं ? दूसरी बात, हमने गांव के सारे लोगों, गणमान्य नागरिकों और उनके परिवार के सभी सदस्यों का एक बयान लेकर आए हैं। इसका मतलब वहां के ग्रामीण लोग गलत बोल रहे हैं और उसके परिवार का चाहे उसका बेटा हो, उसकी सास हो, सभी लोग गलत बोल रहे हैं कि बीमार था, लड़ाई झगड़ा था ? उनका स्पष्ट कथन था। हमने उनसे पूछा कि क्या दबाव में आकर इस प्रकार का बयान दिया है ? यह आपके क्षेत्र का मामला है इसलिए आप इसको थोड़ी संवेदनशीलता से लीजिए। आप कम से कम इस तरह की बात न बोलें। यदि आप इस तरह की बात बालेंगे तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप शांति मिलने लायक कुछ बात कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कुछ शांति होने लायक बात कीजिए। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मृतक ने 12 दिसम्बर को जहर खाया और सरकार को बने हुए जुम्मा-जुम्मा 7 दिन हुए थे और 7 दिन के भीतर ही ऐसा क्या हो गया कि उसने ऋण माफी को लेकर आत्महत्या कर ली ? यदि ऐसी स्थिति होती तो आप लोगों ने देश को इतने सालों तक ठगा, असत्य आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी किसी देशवासी ने आत्महत्या नहीं की। यदि ऐसा होता तो पूरा भारत व्यक्तिविहीन हो जाता।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, हम लोगों ने सरकार बनने के 2 घण्टे के भीतर कर्ज माफ किया था। आप तो 7 दिन की बात कर रहे हैं। आप देश की बात कर रहे हैं। हमने किसानों का 71,000 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया था। आपने आज तक किसानों की फूटी कौड़ी भी माफ नहीं की है और न ही किसी के लिए की है।

श्री धर्मजीत सिंह :- राहुल गांधी जी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, आप नहीं जानत हों, हमन जानत हन। सब छत्तीसगढ़िया आदमी मन एक आस लगा के बइठे रीहिस हें कि सरकार बनही ता कर्जा माफ करही। तुमन कर्जा माफ नहीं करेव ता कतको घर के चूल्हा नहीं जले हे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप कर्ज में राहुल गांधी जी को कहां से ला रहे हैं?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप मन तो एकमुश्त धान के रेट ला भी नहीं दे हों।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के किसान मन अपन घर मा जाके बिना खाए सो ए। ओखर बाद आप कहात हो कि हमन का लूटे हन अऊ 75 साल ले काए करिस ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। रामकुमार जी, आपकी बात आ गई।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन जो करे हो, जो दीस, तेखर खातिर मैं कहना चाहत हो। ओ तुहर क्षेत्र के किसान हे। तुंहर 1 लाख कतका करोड़ रूपये के बजट हे तो ओला 2-4-20 लाख रूपये दे दीहौं ता का हो जाही ? समुद्दर ले एक ठन बूंद निकाल ही डारहूं ता का हो जाही ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग एक-एक करके बोलिये।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसने सरकार बनने के 7 दिन बाद आत्महत्या की। यहां पर उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय बोल दिया कि वह जुमला था। हो सकता है कि उस किसान ने इसलिए आत्महत्या की थी कि उसने सोचा होगा कि उसका कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि उसने इसके कारण ऐसा किया ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओमन मरही नहीं ता का डी.जे. लगा के डांस करही ?

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि वह एक तरफ बोलते हैं कि 18,000 रूपये बोनस मिला तो फिर कर्जा नहीं लिया। लखेश्वर

बघेल जी बार-बार बोल रहे हैं कि वह घरजिया था। उसके नाम पर पट्टा नहीं था। वह अपनी सास के नाम से खेती करता था। सारे काम वही करता था। जैसे नोटिस पहुंचा।

अध्यक्ष महोदय :- कुल-मिलाकर मामला लमसेना का है। लमसेना को कर्ज लिया था, वह नहीं लिया था। केवल इतना ही तो है और क्या है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, वह डोकरी अभी जिंदा है और उसको कुछ भी हो सकता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक ही निवेदन है कि उसको कुछ न कुछ दिया जाए। या तो उसको मुआवजा दिया जाए या उसका कर्जा माफ कर दिया जाए। इतनी बड़ी सरकार है तो एक छोटी सी घोषणा कर दीजिए। आप 7 दिन की बात करते हैं। 1 घण्टे में सरकार बदलती है। बिहार में रोज सरकार बदल रही है। सरकार बनने के 7 दिन बाद का यह मामला है। आपके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। आप भी बस्तर से हैं। वह बस्तर का आदिवासी है इसलिए आदिवासी को ध्यान में रखकर उसका कर्जा माफ कर दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, का होगे ? सबके मन के भावना हे कि गरीब ला मिल जाए। यहां हम सब बइठे हन ता गरीब के भला बर ता आए हन। मंत्री जी, आपसे निवेदन हे। आपके क्षेत्र के मन देखत होही। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप उस किसान को मुआवजा ही दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- आप महिला मन ला ठग देहौं, किसान मन ला ठग देहौं, गरीब मन ला ठग देहौं। जम्मो ला ठगते जात हों। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आप बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में जब इनकी सरकार बनी थी तो श्री राहुल गांधी जी। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें राहुल गांधी जी कहां से आये ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी जो कहे रीहिन हे, आप तेला बताओ न। कालाधन ला। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको सुनना तो पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री बालेश्वर साहू :- आपको राहुल गांधी जी के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और लोक सभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप मोदी जी की गारंटी की बात करिये। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- यह गलत है। मैं तो बात करूंगा ही। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप मोदी जी की गांरटी की बात कीजिए। मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यदि आप लोग कर्जा माफ करते तो वह आत्महत्या नहीं करता। यह 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं और 1 सप्ताह में हसदेव में कटाई शुरू हो चुकी थी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप मन ढिंढोरा पीटे रहे हों। अब सरकार बनगे तो कर्जा माफ करो न। काबर नहीं करत हों ? भोरहा मा मत रहिहुं। तुंहर सरकार में किसान मरत हे। जंगल ला काट देहौं। नहर ला बिगाड़त हों। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 1 सप्ताह में जंगल काट सकते हैं, लेकिन कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे राहुल गांधी कहते ही आप लोग इतने भड़क क्यों गये? प्रदेश की जनता तो उनके नाम से भड़क ही रही है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, हम लोग बस्तर से हैं या राहुल गांधी जी बस्तर से हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार थी तो किसानों के धान की खरीदी की। आप किसानों को धोखा देने का काम करते हैं (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार बनिस त पूरा प्रदेश के किसान के कर्जा ह माफ होए रिहीसे । तुमन किसान ला नहीं दे सकव । (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
12:40 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्‍वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्‍वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया) ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सन् 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करेंगे और ये लोग राजनीति कर रहे हैं । जिनके नाम से कर्ज नहीं हैं, वह मरा है, कर्जदार तो जिन्दा है । कर्जदार जिन्दा हैं, जिनके नाम से कर्ज

नहीं है, वह मरा है । अब वे कहीं पर भी मरेंगे तो भूख से मरेंगे, कर्ज से मरेंगे । राहुल गांधी बोले थे तो कर्ज माफ क्यों नहीं करा दिए थे ? कुछ भी बात करते हैं । विपक्ष गैर जिम्मेदार है, सदन के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे वरिष्ठ लोग अभी सदन में नहीं हैं । सदन की कितनी गरिमा है, वह हम समझ रहे हैं ।

समय :
12:41 बजे **नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री लखेश्वर बघेल
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्रीमती गोमती साय
5. श्री ललित चन्द्राकर

समय :
12:41 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्रीमती अनिला भेंडिया
2. श्री दलेश्वर साहू
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

समय :
12:42 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। श्री कवासी लखमा जी चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह बजट सिर्फ जनता का बजट नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । छत्तीसगढ़ विधान सभा में मुझे 23-24 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा बजट देखा है । एक राजनीतिक, चुना हुआ आदमी जो बजट पेश करते हैं, वह गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, तेंदूपत्ता तोड़ने वाले को जानता है । जिस मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वे कलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने सब कुछ कलेक्टर के चश्में से देखा है । कलेक्टर के बारे में जानते हैं कि चाहे उनके पास मुख्यमंत्री जी का पत्र जाता हो, चाहे मंत्री का पत्र जाता हो, उसे कलेक्टर घूमा सकता है । चौधरी जी हमारे दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर थे, इनके कार्यकाल को हमने देखा है । मेरे ख्याल से इस देश में तीन लोग पावरफूल हैं, मैं तो कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं ।

समय :
12:44 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में तीन लोग पावरफूल होते हैं । देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और जिला में कलेक्टर । मेरे ख्याल से ये तीन लोग पावरफूल होते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी क्षेत्र में मंत्री जी कलेक्टर थे । वे आदिवासियों की जमीन को पलटकर गैर आदिवासी को देते रहे, अलटी-पलटी करते रहे । वह मामला अभी हाईकोर्ट तक चल रहा है । ऐसे व्यक्ति ने बजट पेश किया है। वे सिर्फ बजट ही पेश नहीं कर रहे थे, मोबाईल देख रहे थे, उसके बाद क्या-क्या बता रहे थे ? वे बजट के बारे में कम बता रहे थे, शायरी ज्यादा सुना रहे थे । यहां शायरी सुनने वाले लोग नहीं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं । ये कहां समझेंगे ? हमारे प्रदेश में पहली बार आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोग उनको बधाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक घंटा नहीं हुआ है ।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य लखमा जी बोल रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- मैंने अभी शुरूआत की है, थोड़ा बोलने दो ।

श्री केदार कश्यप :- एक मिनट, सुन लीजिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लखमा जी की सेवा करते नहीं हो, सुनाते बस हो। वे आबकारी मंत्री थे, पांच साल से उनकी आदत हो गई है ।

श्री केदार कश्यप :- उन्होंने बस्तर की जितनी सेवा की है, इस पूरे पॉच सालों में सभी ने देखा है ।

श्री रामकुमार यादव :- उस जगह में जाकर देखना अभी का स्थिति हे ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय लखमा जी तेन्दूपत्ता के सन्दर्भ में कह रहे थे। तेन्दूपत्ता के लिए धरना हुआ था, आपको याद है ? हम लोग गये थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- भईया, उनको सिर्फ एक ही चीज याद है। ई.डी., ई.डी.।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- दूसरा, अभी आपने कहा कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी हैं, लेकिन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। (मेजों की थपथपाहट) आप लोगों जैसा नहीं जो नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाओ। हम लोग असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- असली बने हे तो रूख राई ला चुनत हा हो।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, केदार कश्यप जी के दिल में कितना दर्द हुआ होगा, मैं इधर मुख्यमंत्री बनने वाला था, वह कैसे बन गया। मैं तो बस्तर से बहुत बार जीता हूं, चार-चार बार जीता हूं। जिस दिन साय साहब मुख्यमंत्री बने, उस दिन से आपका चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई हैं।

श्री कवासी लखमा :- हमारा क्या लगेगा ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके लिए तो पूर्व मुख्यमंत्री कसाई हो गये थे।

श्री केदार कश्यप :- आप लोग जिस तरीके से कभी बाबा की ओर, कभी ढाबा की ओर, कभी उनकी ओर चलते थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, अभी आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, आपको बजट में बोलना है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, यह प्रैक्टिस आपके यहां भी है, चन्द्राकर जी से पूछिये।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये। लखमा जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। उनको बोलने दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय केदार साहब, आदिवासियों का भला करना छोड़कर इधर टोकना चालू कर दिए, फिर बस्तर की जनता देखेगी। सभापति महोदय, मैं बजट नहीं पढ़ता। लेकिन एक लाईन पढ़ा हूं, एक लाईन पढ़ा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आया।

श्री सुशांत शुक्ला :- दादी, आपको तो पढ़ना आता ही नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे, यह तो बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, एक मिनट। दादी को पढ़ना आता है या नहीं आता है, बाद की बात है, लेकिन उस दिन अंग्रेजी में समझ गये थे कि पी.एस.सी.की सी.बी.आई. जांच होगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- वह तो आपने पहले ही बता दिया था। (हंसी) सभापति महोदय, एक तो आदिवासी मंत्री नाराज हैं, इधर के सीनियर विधायकों का दिल धधक रहा होगा, इतना विद्वान पूर्व मंत्री सामने कैसे बोल रहे हैं, बोलना है तो बाहर बोलो। आप लोग बोलते हो कि बी.जे.पी. संगठन बहुत मजबूत है, यह कैसा संगठन है ? मोदी जी ने बना दिया, क्या करोगे ? बोलना है, वहीं जाकर बोलो,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप बदल नहीं सकोगे। हम आपको कितना भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको मंत्री नहीं बनायेंगे। अगर उधर से कुछ तोड़कर ले आओ तो हम मदद करेंगे, आपको मंत्री जरूर बनायेंगे।

श्री राकुमार यादव :- बाबू जी, चन्द्राकर जी हा एक दिन बोलत रहिस हे कि मेहनत करे मुर्गी, अण्डा खाय फकीर।

श्री सुशांत शुक्ला :- यादव जी, तै इतना जहरीला हो गय हस कि तै दूध पी के जहर बोलत हस।

सभापति महोदय :- लखमा जी, एक मिनट। देखिये, लखमा जी विपक्ष के इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। अगर आप लोग बार-बार टोकेंगे तो बोलने वाले के बहुत नाम हैं। टोकने से भाषण का फ्लो भी बिगड़ता है और आप पूरी बात भी नहीं सुन पायेंगे। इसलिए निवेदन है कि उनको फ्लोइन्टली बोलने दीजिये, चलिये बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, आपका ख्याल रखेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री सरगुजा क्षेत्र से बने हैं, वित्त मंत्री रायगढ़ से बने हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे गांव से, सुकमा से बने हैं। आज वह जगदलपुर से विधायक हैं, लेकिन उनकी पैदाइशी, रहने वाले हमारे सुकमा के हैं। लेकिन इस बजट में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर को कुछ दिया है क्या ? स्कूल, आश्रम, कुछ दिये ? सरगुजा में 16 सीट जीते हो, सिर्फ सरगुजा ही सरगुजा चल रहा है, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, आप लोग ही पढ़ कर बतायें ? रायगढ़ और सरगुजा के अलावा बजट में क्या है ? बस्तर में सिर्फ नारायणपुर को ही जगह मिली है । वहां कोई नया स्कूल खोले हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना देना चाहिये वह दिये हैं, वह तो खुद वहां के विकास में धरने में बैठते हैं । अभी सुकमा टू झीरम सड़क हो रही है, उसके शुरू होने पर धरना में बैठने वाले हैं ? हम लोग गये थे तो उस बात को बतायें ? वहां कुछ होता है तो धरने में बैठते हैं ?

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, धरना में बैठ-बैठ के, चन्द्राकर जी मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, बता देता हूँ । वहां लाईट जल रहा है ना, गोलापल्ली, क्स्टिाराम, मराईगुड़ा में लाईट जल रहा है ना, उसे वित्त मंत्री जानते हैं, वह कलेक्टर रहे हैं । मैंने तेलंगाना सरकार वाई.शेखर रेड्डी जी, जब आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहां से लाईट लाया हूँ । (मेजों की थपथपाहट) गोलापल्ली हो, किस्टाराम हो, उस समय के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, एग्रीमेंट में दर्शन कर दिया कि जितना लाईट जलेगा, पैसा हम देंगे । मैं उस लेटर को लेकर हैदराबाद गया हूँ । वाई.शेखर रेड्डी जी लाईट दिये हैं, आपका लाईट वहां नहीं जल रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांच साल में बिजली क्यों नहीं ला सके हो, यह बताओ ना ? तेलंगाना से पैसा क्यों नहीं ला सके हो ? समझे ।

श्री कवासी लखमा :- कौन दिया है बताओ ? आप दोगे या मैं लाऊँगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एग्रीमेंट लिये हो, उसका श्रेय आप लोगे ? चिट्ठी भर ले गये, उसका श्रेय आप लोगे ?

श्री कवासी लखमा :- लड़ाई मैं किया हूँ । आपको तो अभी तक पता नहीं है ? अध्यक्ष जी, तेलंगाना से जोड़ने वाले, आन्ध्रप्रदेश से जोड़ने वाले, उड़ीसा से जोड़ने वाले, महाराष्ट्र से जोड़ने वाले को इस बजट में क्या मिला ? हम यह बोलना चाहते हैं कि क्यों नहीं दिये भई ? माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है, यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो हम सबसे ज्यादा खुश है । हम लोग सबसे ज्यादा बधाई दिये हैं । इस बजट में बस्तर क्यों नहीं है ? आपको बजट देने का क्या मतलब है ? सरगुजा के लिये पैसा देने का क्या मतलब है ? बिलासपुर से इधर जशपुर के लिये, रायपुर के लिये कुछ नहीं रहेगा तो चलेगा ? हम लोग राजधानी में बैठते हैं, बिजली नहीं रहेगा तो चलेगा ? दक्षिण बस्तर को क्यों नहीं मिला ? पुलिस कैंप क्यों नहीं खुला ? वहां रोड क्यों नहीं है ? भारत सरकार के सेना और सी.आर.पी.एफ. कैसे रह रहे हैं ? पिछले 15 सालों में बस्तर को नर्क बना दिये थे । 700 गांव खाली हो गये और वे तेलंगाना में पलायन किये हैं । जगरगुण्डा स्कूल बंद थे, गोलापल्ली स्कूल बंद थे, हम लोगों ने उस स्कूल को 15 साल में खोलने का काम किया है, लेकिन वहां बिल्डिंग नहीं है, पैसा सरगुजा को दिये हैं । हमारा बिल्डिंग खाली है, वहां जंगल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ? किस हिसाब का बजट है ? क्या बस्तर छत्तीसगढ़ में नहीं है, बस्तर अलग राज्य होना चाहिये । इस तरह का व्यवहार होगा तो आगे जाकर यह मांग भी उठेगा ।

श्री राजेश मूणत :- दादी, पांच साल तक मंत्री रहे हो । पांच साल एकतरफा मंत्री रहे हो, बस्तर में अपनी तरफ से क्या काम करवाया है वह तो गिना दो ? जगदलपुर में शहीद के नाम पर जो बना है, वह भी भ्रष्ट्राचार का भेंट चढ़ गया है । आपके नेताओं के नाम पर ढ़ाई करोड़ रूपया खर्च करके जो बनाया था, वह भी भ्रष्ट्राचार की भेंट चढ़ गया । आप उसके बारे में कुछ बोलो ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये ।

श्री रामकुमार :- आदिवासी समाज के बेटा के विकास करे हे, का बात करथव...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यादव जी । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, मैं कोई ऐसी चीज का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ । मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पूरी राजनीति करने वाले बस्तर के सबसे बड़े नेता महेन्द्र कर्मा के बाद में आप बने घूम रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- मैं नहीं घूम रहा हूँ । लोग वोट दे रहे हैं, तब बना हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संतराम जी निपट गये । मोहन मरकाम निपट गये । इनके प्रकोप से ....। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- दादी आप रहोगे, मैं आपके साथ हूँ । (व्यवधान) मेरी बात को आप सुन लो ।

श्री कवासी लखमा :- क्या हम लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा है ? (व्यवधान) यदि यहां लगातार चुनाव जीतने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वह बृजमोहन अग्रवाल और कवासी लखमा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, जब हमारा शासनकाल था तब वहां पर नक्सली घटनाएं नहीं हुई थी।

सभापति महोदय :- आप लोग सुनिये। उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) कवासी लखमा जी, आप बोलिये। संगीता जी, आप भी बैठिये ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, लखमा जी को बोलने का मौका दीजिये। वे लोग भी टोका-टाकी करते हैं।

सभापति महोदय :- लखमा जी बोल लेंगे, वह सक्षम हैं। आप लोग खड़े मत होईये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, दादी को आज तक कोई नहीं रोक पाया। आप जबर्दस्ती परेशान हो रही है।

सभापति महोदय :- मूणत साहब। आप बैठ जाईये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, हम लोग सोचते थे कि नई सरकार आयेगी, मोदी जी की गारण्टी आयेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, मैं आपके शोषण के खिलाफ बोलूंगा। आपका जो 05 सालों तक शोषण हुआ, [xx]। मैं उस पर बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी आपका जो शोषण हो रहा है। हम लोग भी उसके खिलाफ बोलेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी चंद्राकर जी का शोषण हो रहा है, हम लोग भी उसके बारे में बोलना चाहेंगे। वे कितने दु:खी हैं, यह हम लोग जानते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- चंद्राकर जी, इतने वरिष्ठ होने के बाद भी आपको मंत्री नहीं बनाया गया। यह आपका शोषण हो रहा है। हम लोग इसके खिलाफ बोलेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- आपकी सरकार में ..। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम तो चंद्राकर जी को ऑफर दे रहे हैं कि वह दो-चार लोगों को लेकर आ जाये। हम उनको मंत्री बना देंगे।

सभापति महोदय :- मुझे ऐसा लगने लगा है कि दादी जी इतना बढ़िया भाषण दे रहे हैं। आप लोग उनको बोलने दीजिये, उनको इंटरप्ट मत करिये। प्लीज। उनकी बात सुनिये। वह बहुत अनुभव की बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यह लोग हमारे नेता जी से घबरा गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- हम उनसे नहीं घबरा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग घबरा गये हैं इसलिये बार-बार टोक रहे हैं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- (व्यवधान) इसलिये पूरी कांग्रेस पार्टी इधर-उधर घूम रही है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, हम लोग कहां खड़े हो रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मैं उनको भी बैठा रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आप हम लोगों को ही बैठने को कहते हैं।

श्री राजेश मूणत :- यादव जी, आपको कोई नहीं बैठाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, [xx]। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उधर भी ईशारा कीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आप उधर देखिये।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, एक कहावत है। तेल न तेलई, बरर-बरर नरियई।

श्री कवासी लखमा :- अनुज शर्मा जी, मैं आपकी शादी में नाचने आया था या नहीं ? आप बताईये।

श्री अनुज शर्मा :- दादी, आप नाचे थे।

सभापति महोदय :- लखमा साहब, आप बोलिये। आप इधर-उधर अपना ध्यान मत भटकाईये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, आप इस बजट को पहले पढ़ लिये होंगे क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा चलता है। भले ही आपके दिमाग में राहुल गांधी, राहुल गांधी चलते रहता है लेकिन आपका दिमाग ज्यादा चलता है।

श्री राजेश मूणत :- कहां राहुल गांधी चलता है ?

श्री कवासी लखमा :- मैं सभापति महोदय से बात कर रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- दादी, मैं आपको फिर बता रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- चलेगा।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं कल और परसो जांजगीर में था।

श्री कवासी लखमा :- क्यों गये थे ? राहुल गांधी जी को देखने गये थे ?

श्री राजेश मूणत :- दीवारों के ऊपर माननीय भूपेश बघेल जी का नाम लिखा था। उसे पूरा मिटा दिया गया और उसकी जगह उमेश पटेल जी का नाम लिख दिया गया। अब मैं उससे ज्यादा और क्या बताऊं ?

सभापति महोदय :- चलिये, यह उनका मामला है। आप बोलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, आप सब लोगों ने बजट को पढ़ा है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। हम सब लोग यह सुन रहे थे कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, आपके प्रभारी, आपके विधायक और आपके उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी तो बाद में बने है, पहले उप मुख्यमंत्री, अरूण साव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आप लोगों का एक ही नारा था कि कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी 04 किश्तों में राशि देते हैं, हम एक किश्त में देंगे। यह मोदी की गारण्टी है। कहां है मोदी जी की गारण्टी ? कहां आप लोगों ने एक किश्त में राशि दी ? आप लोगों ने कहा कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल में 21 क्विंटल धान खरीदी की जायेगी। कहां आप लोगों ने 3100 रूपये दिया ? यही मोदी जी की गारण्टी है ?

श्री रामकुमार यादव :- गांव मे कहाथे कि आओ मे हा देबो, मे हा देबो।

श्री कवासी लखमा :- आपने कहा कि 3100 रूपये में एक मुश्त राशि देंगे। पूरी दुनिया देख रही है कि आपने 3100 रूपये प्रति क्विंटल राशि एक मुश्त दी या नहीं दी। आप बड़ी-बड़ी टी.व्ही. में मोदी जी की गारण्टी का नारा दे रहे थे।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, अभी बोनस में कितना पैसा मिला ? आप सही-सही बताईयेगा।

श्री कवासी लखमा :- कितना भी मिला हो। लेकिन क्या एक मुश्त मिला ? (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, आप लोगों ने वर्ष 2016 एवं 2017 का बोनस देने की बात कही थी और वर्ष 2015 एवं 2016 का बोनस दे दिये। वहां भी किसानों के साथ धोखा हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- आप सही-सही बताईये कि कितना बोनस मिला ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, हमारे लखमा जी कुछ और बात कर रहे हैं और मूणत जी कुछ और बोल रहे हैं। यह एकमुश्त राशि देने की बात कर रहे हैं। आपने जो एकमुश्त राशि देने की बात कही थी, जिसका वादा किया था, आपने वह क्यों नहीं दिया ?

सभापति महोदय :- देखिये, एक मिनट।

श्री रामकुमार यादव :- यह लोग महतारी वंदन योजना में भी घलोक ठग डाले हे।

श्री कवासी लखमा :- यह लोग मोदी की गारण्टी के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान से झूठ बोले। इनकी मोदी की गारण्टी भी फेल हो गयी।

सभापति महोदय :- लखमा साहब, एक मिनट। यहां पर इतने लोगों का नाम है। अगर इस तरीके से चलेगा तो शायद कल तक भी पूरी चर्चा नहीं हो पायेगी। इसलिये मैं आप सब से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि कृपया उनकी बात को धैर्य से सुने। आप सब एक दूसरे की बात को धैर्य से सुने। एकात बार बीच में बोलना समझ में आता है लेकिन यदि तीन सदस्य इधर से और दो सदस्य उधर से बोलेंगे, यह तो ठीक नहीं है। लखमा जी, आप बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैं एक ही बात दु:ख के साथ कहता हूं। आप लोग भी चुनाव जीतकर आये हैं और उधर बैठे हैं। आपको भी जनता ने ही वोट दिया। हमको 35 सीटें मिली और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपको ज्यादा सीटें मिली तो आप लोग सरकार में आये। लेकिन आपको सरकार में आने के बाद बदलना नहीं है। आपको असत्य बोलने वाला काम नहीं करना है। छत्तीसगढ़ की जनता असत्य नहीं बोलती। सरकार बदलने के लिये 05 साल से ज्यादा समय नहीं लगता है। आप लोगों ने घूम-घूमकर पान ठेला में और सब जगहों पर बोला कि हम लोग धान की एकमुश्त राशि देंगे और कांग्रेस पार्टी 04 किश्तों में राशि देगी। जब इसी विधान सभा में माननीय भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी तो यहां उपस्थित विद्वान विधायक बोलते थे कि क्या यहां पर चोरी होगी ? यहां 20 क्विंटल धान कहां से पैदा होगा ?

समय

1.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में तो इतना धान नहीं होता। वहां आपकी सरकार मोदी गारण्टी में 20 क्विंटल से 21 क्विंटल कर दिया तो इनके मुंह बंद हो गए। यह असत्य बातें कहकर, आप लोग सरकार चलायेंगे। यहां के लोग अंधे हैं। इसलिए मैं हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने भाषण में कहें कि हम लोग किसानों को एक मुश्त कब देंगे, हम कल देंगे या परसों देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी जगह बात नहीं करूंगा, लेकिन यह नहीं करना चाहिए। तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधान सभा चुनाए हुए। तीन राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया। हमारे तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया। वहां कांग्रेस पार्टी के Revanth reddy मुख्यमंत्री बने हैं। वहां 4000 रूपये पेंशन देंगे। वहां बस का सफर महिलाएं फ्री में करेंगीं, वह बेरोजगार युवकों को 3000 रूपये देंगे। वहां महिलाओं को 2000 रूपये देंगे। जैसे ही उन्होंने राज्यपाल महोदय के सामने शपथ लिया और माननीय राज्यपाल को विदा कर दिया। उन्होंने मीडिया को दूसरे रास्ते से बुलाया। वहां उसी दिन एक घण्टे के अंदर बस का सफर महिलाओं के लिए फ्री हो गया। वहां पेंशन का पैसा फ्री मिल रहा है। तेलंगाना राज्य हमारे बस्तर क्षेत्र से समीप में है, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? इन्होंने कहा था कि किसानों को एक मुश्त राशि मिलेगी, लेकिन यहां एक मुश्त राशि कहां मिल रही है? इंदिरा आवास तो 5 साल चलने वाली योजना है। आपने पहले किश्त की घोषणा कर दी होगी। आने वाले 5 सालों में बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। लेकिन इन्हें एक तो काम करना चाहिए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम महिला बहनों को 12000 रूपये देंगे। गांवों में महिलाएं परेशान हो रही हैं वहां लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महतारी वंदन योजना का फार्म भरिए। उन्होंने चुनाव के पहले फार्म भरा। अभी फिर महतारी वंदन योजना का फार्म भरा रहे हैं। उसमें बोल हैं कि उस योजना में कोई आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी को पेंशन मिलेगा तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई

तेन्दूपत्ता तोड़ाई में कार्यरत हैं, उसे बोनस मिलता हो तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी का महिला समूह में नाम हैं उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी को वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन मिलता हैं तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर इस प्रदेश में आपको खाली महिलाएं कहां से मिलेंगी। यहां की कोई न कोई महिला का नाम पेंशन में जुड़ा है। यहां की महिलाएं कोई न कोई सोसाइटी चला रही हैं। वह आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। इस योजना का लाभ कब मिलने वाला है। होली के आसपास लोकसभा चुनाव के पहले मिलेगा। यदि अभी लोकसभा चुनाव नहीं होता तो वह भी उनको नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वह राशि मिलेगी, उसकी भी गारण्टी नहीं है। फिर इस बजट सत्र का क्या मतलब है। हम लोग यहां 8 दिनों से पानी पीकर चिल्ला रहे हैं। वहां गांव वालों को कोई सुविधाएं नहीं हैं।

मानननीय सभापति महोदय, यहां पर एक भी स्कूलों का उन्नयन नहीं हो रहा है। इन 5 सालों में स्कूलों का उन्ननयन नहीं होगा तो भाई, कैसे होगा । पहले हम लोग हर बजट में देखते थे कि मीडिल स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होता था, प्रायमरी स्कूल का मीडिल स्कूल में उन्नयन होता था। माननीय वित्त मंत्री जी, यदि इस बजट में इस प्रदेश के एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं होगा तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। इस प्रदेश में जब स्कूलों के उन्नयन की संख्या बढ़ेगी तब तो स्कूलों में शिक्षक बढ़ेंगे। आपकी क्या योजनाएं हैं, यह किस प्रकार का बजट है। पहली बात तो यह है कि यदि आपने यह बजट बनाया होता तो आप भी सोचते। यह बजट तो नागपुर से बना है। यह मोदी जी की गारण्टी से बना है। अगर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे पुलिस मंत्री हो, मैं इस बात की चुनौती देता हूँ। यह लोग अपनी मर्जी से एक भी काम करके दिखाए। अगर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव होगा ता हम लोग 100 साल पीछे होंगे। यहां पर सड़कें, पुलिया नहीं हैं। हम लोगों ने बीजापुर, भोपाल पट्टनम् जाने के लिए इंद्रावती में 10 पुलिया बना दी। हमारे वित्त मंत्री कलेक्टर साहब थे उन्होंने उधर देखा है कि हमारी शबरी नदी में कितनी पुलिया बनी हैं। अब क्यों नहीं बन रहीं हैं। मैं इस बात से खुश हूँ। मैं कल दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी जी के दर्शन करने गया था। मैंने पुलिस वाले से कहा कि मैं दंतेवाड़ा से बारासूर होकर निकलूंगा। वहां 5 सालों में हम लोगों ने इतनी सुंदर सड़कें बनवायीं हैं। दंतेवाड़ा से छोटे डोंगर जाने में केवल आधे घण्टे का समय लगता है। हमने वहां चमचमाती सड़कें बनवायीं हैं। उसके बाद, माननीय मंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र छोटे डोंगर से लगा है। वहां पर धूल ही धूल है। वहां गड्ढे और सड़कें कहां हैं, पता ही नहीं है। माननीय मंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । आप अपने नारायणपुर की रोड को तो सुधारिये बाद में दूसरी बात करेंगे। वह रोड को 05 साल में गायब कर दिये थे। यह 15 साल मंत्री थे, अभी फिर मंत्री हैं। इनके विधानसभा नारायणपुर में एक तहसील नहीं खोली। बलीराम कश्यप जी इनके पिता जी बस्तर के बड़े नेता थे। हम दिल से उनको मानते हैं। चाहे दिल्ली में या भोपाल में हो, वह बस्तर के बारे में बड़ी-बड़ी बात उठाते थे। मैं बलीराम कश्यप जी को बधाई देता हूं। भानपुरी से

चुनाव लड़ते थे, उसको हम लोग तहसील बनाये। हम लोग मरदापाल को तहसील बनाये, मरदापाल में, छोटेडोंगर में कॉलेज खोले।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपके सुकमा जिला कौन बनाया ? भारतीय जनता पार्टी ने, डॉ. रमन सिंह जी ने बनाया था। आप उसके लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- मैं मरदापाल की बात कर रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- अभी जगदलपुर से सुकमा तक की सड़क को पहले देख लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- आपके यहां पुराने पुल को 40 करोड़ रुपये दिये हैं। इन्द्रावती में फिर पुल बन रहा है। आप मरदापाल की तो 30-40 किलोमीटर दूर की रोड़ नहीं बना पाये। आप बडी-बडी बात करते हैं। मैं तेंदूपत्ता की दर देने गया था। मुझे मालूम है, आप राजनीति करने गये थे और राजनीति करना भी चाहिए। वहां नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, आप वहां 15 तक बोरिया-बिस्तर लेकर के रहे थे, क्या आपको वोट मिला ? आपके बाद मैं रेगरगट्टा गया था। रेगरगट्टा में मैं रोड बनाकर आया हूं।

श्री केदार कश्यप :- रेगरगट्टा में जितनी मौत हुई है न, उसके बाद तो आप गये। हम लोग जाने वाले थे, आप लोग मना कर दिये।

श्री कवासी लखमा :- कौन मना किया ?

श्री केदार कश्यप :- आप लोग मना दिये थे, उस समय आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा कि वहां जाना नहीं है। आप चोरी-छिपे वहां पर निकल गये, आपकी क्या सेटिंग थी ?

श्री कवासी लखमा :- आपने मेरे को फोन क्यों नहीं किया ?

श्री विक्रम मंडावी :- केदार भैया, अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो आप जाईये, आपको अभी कौन मना करेगा ?

श्री कवासी लखमा :- आप जाईये।

श्री केदार कश्यप :- हम जायेंगे, बिल्कुल जायेंगे। यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है।

श्री कवासी लखमा :- वहां एक कॉलेज तो खोलिये। हमारे आदिवासी मंत्री हैं। हम लोग सोच रहे है कि वहां कोई कॉलेज खोलेंगे, वहां पर एक कॉलेज, स्कूल खोलने के लिए बजट में प्रावधान नहीं है। आपसे छत्तीसगढ़ की, बस्तर की जनता पूछेगी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। आप उनकी ओर देखकर बात करिये।

सभापति महोदय :- मैं वही बोलने वाला हूं। लखमा जी, आप किसी से व्यक्तिगत बात मत करिये। आप भाषण दीजिये न। आप बजट में जो बोलना है, बोलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, वह हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, अगर वह उठते नहीं तो मैं भी नहीं बोलता। मैं इधर देखकर बोलता हूं। अजय चन्द्राकर जी, चुपचाप निकल दिये।

सभापति महोदय :- आप बोलिये, लेकिन बजट की चर्चा में आईये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, यह बजट देखकर ऐसा लग रहा है कि इस सरकार का न कोई विजन है, इस बजट से न किसी को कोई आशा है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपये मिलना है, वह राशि कब मिलेगी, लोग पूछ रहे हैं ? वित्त मंत्री धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देना है या नहीं देना है ? आप अपने भाषण में घोषणा कर देना कि इस तारीख से देंगे और यदि नहीं देना है तो अगले चुनाव के बाद देंगे। केन्द्र सरकार के 15 साल हो गये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देश में काला धन वापिस लायेंगे और हर नागरिक के खाते में 15 लाख देंगे। बाद में अमित शाह जी बोलते हैं कि यह जुमला है। आप लोग जुमला मत बताईये। हमको यह कहने में डर नहीं है कि हमने कहा कि हम 6000 रुपये देंगे और आप लोगों ने तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने की बात कही है। आप लोग देंगे या नहीं देंगे, वह आने वाला समय बतायेगा। लेकिन वह जो धान के समर्थन मूल्य का पैसा है, उस धान के समर्थन मूल्य की घोषणा के कारण लोग खरीददारी किये, कोई शादी कर रहा है, मडई, मेला लग रहे हैं, हमारे बस्तर में 20 तारीख से रामाराम का मेला चालू हो गया है। नारायणपुर में घोटूल मेला चालू हो गया है, पैसा ही नहीं मिल रहा है। शादियॉं चालू हो गई हैं, लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि पैसा कब मिलेगा ? माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि अगर छत्तीसगढ़ में जाति-पात नहीं हो, मैं पहले भी बोला कि मुख्यमंत्री जशपुर से हैं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो सुकमा से हैं। वह क्या गलती किये हैं, उनको बजट में कहीं 1 रुपये नहीं दिये हैं। न जगदलपुर, न सुकमा के लिये बजट में कुछ मिला, इसका क्या मतलब है ? इन्द्रावती में पुल बनायेंगे, बोधघाट को क्यों नहीं जोड़े ? हमारे बस्तर में सिंचाई की योजना नहीं है, बिजली नहीं है, तहसील नहीं है। जगरगुंडा में तहसील ऑफिस दे देते, क्या आवापल्ली, भोपालपट्नम, उसूर में तहसील ऑफिस है ? पिछड़ा क्षेत्र की सड़क का, स्कूल का पैसा देना चाहिए। आप लोग तो पिछडे क्षेत्र के स्कूल, आश्रम तो नहीं खोले थे, लेकिन हम हम लोग 05 साल में जो स्कूल, आश्रम स्वीकृत किये थे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, उन आश्रम, स्कूलों के लिए लिए बजट में 1 रुपये भी दिये गये हैं, वह बस्तर के लोग कैसे पढ़ेंगे ? वह लोग क्या बनेंगे ? वह नक्सलाईट बनेंगे। यदि उनको मुख्यधारा में जोड़ना है तो वहां स्कूल, कॉलेज, रोड, पीने का पानी, बिजली, पानी, टी.व्ही. आदि सुविधाएं होनी चाहिए। वहां लाईट नहीं रहेगी तो टी.व्ही. कैसे चलेगा? हम लोग सुनते हैं कि अबूझमाड़ को आगे नहीं बढ़ायेंगे। हम सरकार से बदलाव चाहते हैं। शर्मा साहब हमारे नये उप मुख्यमंत्री बन गए। हमारे भी बहुत सारे नये आदमी बने हैं। हम भी ताकत से लड़ेंगे। हम आर-पार लड़ेंगे या बात करेंगे। हमने तो साथ में बात नहीं

की। हमने टी.व्ही. में देखा। अच्छा होगा, लेकिन वहां के लोग इधर-उधर हो रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो वे भयभीत नहीं थे। अभी उनको बांध कर ले जा रहे हैं। कभी आदिवासी को मरवा रहे हैं। भैरमगढ़ के मामले में एक बच्चे को गोली लग गया। अबूझमाड़ में फिर एक आदिवासी पीर मर गया। पहले जैसे ही फिर बस्तर के लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। भाई, वहां पर शांति स्थापित करिए। वहां नक्सलाईड को खत्म करिए। वह किसी के हाथ में नहीं है। वह लोग क्यों सह रहे हैं? हम लोग क्यों सहते हैं? उस समय खासकर हम लोग लोग जितना झेले हैं। परिवार से लेकर, ग्राम से लेकर रिश्तेदार को हम लोगों ने खोया है। तेलंगाना खत्म हो गया, उड़ीसा राज्य भी खतम हो गया । यह बस्तर में क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार। उस समय ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, सुनिए। आपका यह जो भाषण बोल रहे हैं, आपका जो यह अनुभव बोल रहा है, वह विनियोग का है। बजट में कुछ सुन कर एकाध लाईन बोलिए न।

श्री कवासी लखमा :- बजट में वहां रोड बनेगा, पैसा मिलेगा, बिजली लगेगी, स्कूल खेलेंगे, तब तो नक्सलाईड खतम होगा। क्या ऐसे ही नक्सलाईट खतम हो जाएगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोगों ने पांच साल में कुछ किया नहीं, अभी आप रोने लग गये।

श्री कवासी लखमा :- आप मंत्री नहीं बने। इसलिए आप चुपचाप बैठिए। वहां तालाब लगेगा, बिजली लगेगा, खेती होगा, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। आप लोगों ने सरगुजा में कितने कॉलेज खोला है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- आपकी सरकार ने पिछले पांच साल में क्या किया, यह तो बताओ? आप लोगों ने बस्तर, सरगुजा के लिए क्या किया?

श्री कवासी लखमा :- हमने पांच साल में किए हैं। हमने आत्मानंद स्कूल खोला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, वसूली किए हैं बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- आत्मानंद स्कूल खोला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको वसूली भी कम मिला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी का शोषण हुआ है। उनका पैसा लेकर फारार हो गया।

श्री कवासी लखमा :- मेरा (व्यवधान) इधर ही मिलता था। अब ई.डी. वाला आयेगा तो इधर ही बता देता हूं कि मेरा पूरा पैसा चन्द्राकर रखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी का पूरा हिस्सा लेकर फरार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, उसको तो वसूल कर लीजिए, जो आपको नहीं मिला है।

श्री रामकुमार यादव :- तू हर बृजमोहन अग्रवाल जी के चक्कर म मत रइहा। अपन मंत्री बन के तुंहला छोड़ दिस।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आपने अभी कहा कि आप लोगों ने बस्तर, सरगुजा के लिए पांच साल में क्या किया? हम लोगों ने मर्दापाल में कॉलेज खोला, मर्दापाल में तहसील खोला, मर्दापाल में आत्मानंद स्कूल खोला। मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूं। हमने भानपुरी, छोटे डोंगर, जगरगोण्डा, आवापल्ली में तहसील खोला। अभी आप तहसील ऑफिस के लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे? वहां पोस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? तभी तो वहां का विकास होगा। इसलिए इस बजट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सबका समान, भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी। यहां वित्त मंत्री जी ने भाषण में जनता के बारे में नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ मोदी के बारे में ज्यादा बताया। उन्होंने शायरी ज्यादा सुनाया। सभापति महोदय, इसलिए हमारा अपील है कि छत्तीसगढ़ के बीच में तेलंगाना से नक्सलाईड आए हैं। उड़ीसा के नक्सली हमारे सुकमा कलेक्टर को ले गये थे। वहां शांति हुआ। यहां शांति क्यों नहीं होगा? सभापति महोदय, मैं जयादा नहीं कहूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करूंगा कि आप वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी के चक्कर में मत फंसना। यह बड़े लोग हैं, साहब लोग हैं। लेकिन आप ईमानदार मुख्यमंत्री बदनाम हो जायेंगे। यहां सरकार नहीं बनी। वह बोल रहे थे कि 7 दिन के आदमी की मृत्यु हो गई। उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इधर सरकार नहीं बनी तो आदिवासी का जंगल कट रहा है। लाखों पेड़ कट रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा यही निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में रोड बनवाईये या ना बनवाईये, लेकिन नगरनार को मत बेचिए। बैलाडीला को मत काटिए। वहां हमारा आस्था है। वहां आदिवासी लोग पूजा करते हैं। हम जंगल के साथ ज्यादा जीते हैं। धान जितना बेच देंगे। चाहे दुर्ग हो, रायपुर हो या चाहे महासमुंद हो, वहां का किसान एक एकड़ में 25-30 क्विंटल धान पैदा करता है। हमारा बस्तर का किसान 2-3 क्विंटल धान पैदा करता है। बस्तर का किसान तेंदूपत्ता में, महुआ में, इमली में करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी जो प्रश्न उठाया था कि पूरा काम प्रतिबंध हो गया। चाहे सरकारी काम हो, चाहे राजीव गांधी मिशन का काम हो, पंचायत शिक्षाकर्मी हो, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं । बस्तर में एक भी नौजवान नहीं है । तमिलनाडू, आंध्र, हैदराबाद में सब रोज बस में कुली का काम कर रहे हैं, गिरकर मर रहे हैं । पोकलेन गाड़ी (Poclain Vehicle), बड़ी गाड़ी को कभी नहीं चलाने वाला आदमी उसे चला रहा है तो उसमें उसका पैर टूट रहा है । बस्तर में सब काम बंद हो चुका है । 6 महीने आचार-संहिता लगी उसके बाद सरकार बनी लेकिन किसी को भी नया काम या रोजगार नहीं मिला । मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । पंचायत का काम भी चाहे वह महात्मा गांधी गारंटी योजना का काम हो, वह सब काम बंद हो गया है । पूरे छत्तीसगढ़ का यही हाल है । आप लोग बोलते थे कि हम दारू बेच रहे हैं तो यहां पर चक्कूबाजी होगी । आप लोगों ने कहा कि हम यहां की कानून व्यवस्था ठीक करेंगे । अभी घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है । एक-साथ 4-4 लोगों का मर्डर हो रहा है । कानून-व्यवस्था कहां है ? जब हमारी सरकार थी, रायपुर में थोड़ी बहुत चक्कूबाजी हो रही थी तो हम लोग दुख जाहिर करते थे । बस्तर में उन 5 सालों में शांति थी । कहीं पर चक्कूबाजी नहीं होती

थी, कहीं पर गोलीबारी नहीं होती थी लेकिन अब कोई सुरक्षित नहीं है । इसका जिम्मेदार कौन है ? एक सरकार आयेगी, 5 साल तक वह रहेगी, ऊपर-ऊपर घूमेंगे फिर छोड़ देंगे फिर दूसरी सरकार आयेगी वह जाने । हम लोग इस मामले को चाहे वह नक्सलाईट का मामला हो, बस्तर के विकास का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, स्कूल या आश्रम का मामला हो इसे दुरूस्त करना चाहिए । हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा लोगों ने सोचा था कि छत्तीसगढ़ बनेगा तो यहां का विकास होगा । उस समय मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी । दिल्ली में अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी । हम लोग मध्यप्रदेश में विधायक थे, हम लोग प्रस्ताव लाये कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए । बृजमोहन अग्रवाल जी भी थे, चंद्राकर जी भी थे, उस समय यहां के बहुत से लोग नहीं थे । उस समय हम लोग एक तरफा प्रस्ताव पास करके भेजे कि छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए । विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया । अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया । हमें उनकी मंशा को पूरा करना है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को धाराप्रवाह बोलते हुए 30 मिनट हो गये हैं । इतना बता देना कि कारवां कैसे लूटा ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अभी तो ओकर शुरू होइस हे गा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ये पहले वक्ता हैं । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- सुन ते ले भाई । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओ हा पहला वक्ता हे । अभी तो शुरू होइस हे । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- अभी तो ट्रेलर हे, पिक्चर अभी बाकी है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये पहले वक्ता हैं, चन्द्राकर जी डेढ़-डेढ़ घंटे तक बोलते हैं । सभापति महोदय, उनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये । (व्यवधान) उनको बोलने दीजिये न, वे बढ़िया बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग बोले कि महिलाओं को 12-12,000 रूपये देंगे । 12,000 रूपये कब मिलेंगे ? आप केवल कागज में लिखते रहेंगे । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- दादी, यह बता दें कि कारवां लूटा क्यों ? आप केवल इतना बता दें ? मैंने तो और कुछ पूछा ही नहीं है ।

सभापति महोदय :- वह बता देंगे । बैठिए ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसीलिये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने इतना तो बोला कि कांग्रेस पार्टी 4 किस्तों में बोनस दे रही है । हम लोग भी पहले साल वर्ष 2019 में एक-बार 2500 रूपये दिये थे । हमारे राहुल गांधी जी ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, वे ही यहां से घोषणा करके गये थे कि यहां के किसानों को 2500 रूपये देंगे । लोग बोल रहे थे कि 2500 रूपये कहां से

होगा ? रमन सिंह तो 1300, 1600, 1700 रूपये देते हैं, यह 2500 रूपये कैसे मिलेगा ? माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, पूरे हिंदुस्तान में एक घंटे में 10,000 करोड़ रूपये का कर्जा माफ करने वाली पहली सरकार है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- इसीलिये 50,000 करोड़ रूपये का कर्जा लिये हो । (व्यवधान) कौन सा 50,000 दे दिये हो ? छत्तीसगढ़ के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिये । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- किसानों को दिया न । (व्यवधान) अडानी को नहीं दिया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- छत्तीसगढ़ के किसानों को पैसा दिया है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन ला दे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए न । लखमा जी स्वयं ईशारा कर रहे हैं कि बैठिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, दिल्ली से भारत सरकार की चिट्ठी आयी कि छत्तीसगढ़ सरकार इतना बड़ा काम कर रही है, उसको पढ़िए । साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूं । इतनी बड़ी चिट्ठी आयी । 2500 रूपये देंगे तो तुम्हारी धान खरीदी नहीं होगी । तुम्हें एक रूपये नहीं देंगे । मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं कि वे दिल्ली की मीटिंग में गये। वहां कहा गया कि आप केवल 1800 रूपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी करो । 2500 रूपये मत दो, आपको पैसा नहीं देंगे । भूपेश बघेल जी दिल्ली में जाकर बोलकर आये कि तुम पैसा दो, नहीं दो, धान खरीदी करो, सामान खरीदी करो, नहीं करो, छत्तीसगढ़ की जनता को 2500 रूपये दूंगा। (मेजों की थपथपाहट) और राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाये।

श्री राजेश मूणत :- दादी, वो 4 सिलेंडर नहीं मिले, 1 हजार रूपये महिला को नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 2 साल का बोनस नहीं मिला। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अनावश्यक रूप से खड़े मत होइए न। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, आज भी बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। (व्यवधान) आपने 500 रूपये सिलेण्डर देने का वादा किया है, बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 20 रूपया के डीजल ला 70 रूपया। ए तोर मोदी जी करे हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिए। आप भी आदरणीय बैठिए।

श्री कवासी लखमा :- हमारे देश में हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन केवल गुमराह करना है। एक ठोक राम मंदिर बना दिये। राम मंदिर में हम लोग भी पूजा करते हैं।

सभापति महोदय :- लखमा जी, समाप्त करिए। 45 मिनट हो गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- थोड़ी देर, सर, 10 मिनट। सभापति महोदय, जी, हम राम मंदिर को पहले से पूजते हैं। राम मंदिर के ताले को यदि किसी ने तोड़ा है तो श्री राजीव गांधी जी ने तोड़ा है। उसके ढांचे को किसी ने गिराया है तो श्री पी.वी. नरसिंह राव ने गिराया है अभी मंदिर बनाये हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चन्द्रचूड़ बना रहे हैं। असम का क्या नाम है, उन्हें आपके मोदी जी ने राज्यसभा में बना दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ढोल बजा रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- अचछा किये। आप तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के नेता हो, दोनों राज्यसभा में बाहर के आदमी को भेजे हो। क्या आपको छत्तीसगढ़ का कोई आदमी नहीं मिला था? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हम लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी जायेगा, पाकिस्तान को छोड़कर। हम लोग हिन्दुस्तान के आदमी को बनायेंगे। (हंसी)

सभापति महोदय :- लखमा जी, आप विषय में आइए न। उधर मत देखिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, ज्यादा नहीं बोलकर मैंने आपको इस कागज (बजट भाषण) को दिखाया, मेरे को माननीय वित्त मंत्री पर, माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है। वित्त मंत्री जी को तो भरोसा नहीं है, लेकिन आगे जब सेकण्ड बजट आयेगा तो बस्तर को प्राथमिकता मिले।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, उसमें क्या लिखा है? (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आपको अलग से बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या लिखा है, यह तो पढ़कर बता दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, डॉ. रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री बन गये। अभी विधान सभा अध्यक्ष हैं। राजनांदगांव को कुछ नहीं मिला। बस्तर को तो मिला ही नहीं। आपको थोड़ा फायदा है। बिलासपुर तरफ थोड़ा-थोड़ा मिला है।

सभापति महोदय :- लखमा जी, अब समाप्त करें।

श्री कवासी लखमा :- श्री अजय चन्द्राकर जी ये बताने के लिए मेरे पास आये हैं, देखिए। (हंसी) इसलिए माननीय सभापति जी, यह बजट दिशाहीन बजट, आदिवासी विरोधी बजट, किसानों का विरोधी बजट, बच्चे लोगों का विरोधी बजट, कानून व्यवस्था का विरोधी बजट, कर्मचारी विरोधी बजट, बेरोजगारी भत्ता विरोधी बजट और बस्तर का आदिवासी विरोधी बजट है और कितनी भी निंदा करें, वह कम है।

श्री सुशांत शुक्ला :- और कांग्रेसी विरोधी बजट भी है।

श्री कवासी लखमा :- आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और आप जिन्होंने बीच-बीच में हमारे बारे में बोलते हुए समय-समय पर बहुत टोका है, श्री अजय चन्द्राकर और श्री राजेश मूणत जी को बधाई देता हूं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमें वोट नहीं मिला, हम प्रतिपक्ष में बैठ गये। हमको जनता की आवाज उठानी है। आपके माध्यम से उठाते हैं। आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलना

चाहिए, लेकिन तीनों को कैसे बैठाना है, इधर उठाते हैं और उधर भागते हैं, आप लोग इधर-उधर मत भागो, अभी जुगाड़ में भीड़ो। जुगाड़ में भीड़ोगे तो हम लोग साथ देंगे, आपका भला होगा। नहीं तो ऐसे ही पुचुर-पुचुर करने से 5 साल ही खत्म होंगे और कुछ नहीं होने वाला।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री कवासी लखमा :- धन्यवाद।

सभापति महोदय :- जी, धन्यवाद, लखमा साहब। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि समय 1:24 हो गये हैं, लंच के बाद अब शुरू करते हैं।

सभापति महोदय :- आप शुरू करिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- लंच के बाद शुरू करते हैं।

सभापति महोदय :- आपने भाषण शुरू कर दिया। अब मैं आपको रोक रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी।

सभापति महोदय :- आपका भाषण लंच के बाद शुरू होगा। सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.25 बजे से 3:00 बजे तक अंतराल)

समय :
3.00 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी सदन में नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष जी भी सदन में नहीं हैं । वे लोग छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते थे । नैतिक रूप से वे इस सदन का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं । राहुल गांधी जी का आगमन तो दो दिन पहले हुआ था, वे दिन भर के लिए क्यों गायब थे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, बजट पर चर्चा शुरू हो रही है और केवल एक मंत्री को छोड़कर, मंत्रिमंडल का कोई भी सदन उपस्थित नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शुरू ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- वे कहां गए हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पर्यटन में गए हैं ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मोदी जी और शाह जी के पास ?

श्रीमती गोमती साय :- सौ पर एक ही भारी है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बात हुई थी 5 लोग उपस्थित है ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- मैं उपस्थित हूं और नोट कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- शुरूआत में ही 2 दिन गायब हो गए, दिन भर के लिए। नेता प्रतिपक्ष जी गायब हो गए, इनकी उपस्थिति क्या बताती है कि नैतिक रूप से इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि प्रतिदिन या तो जांच बैठ रही है या किसी न किसी तथ्यों से उनकी करनी उद्घाटित हो रही है । इसलिए सबसे अच्छा है कि पलायन करो और झेलने के लिए इनको रख दो । मुस्कुराते हुए लखेश्वर बघेल जी को या खड़े होने के लिए संगीता जी को रख दो ।

श्री लखेश्वर बघेल :- पीठ पीछे बोलना उचित नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, विष्णु जी का 10 अवतार क्यों हुआ था, किसी न किसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए । वेदों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, कभी पृथवी को बचाने के लिए वराह का अवतार हुआ, अलग-अलग विषय थे, वह कथा कहने का समय नहीं है । लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णु का राज क्यों आया, विष्णु का अवतरण क्यों हुआ, राज्य का अवतरण क्यों हुआ । छत्तीसगढ़ की जनता वसूली से, एक्सटार्शन से, करप्शन से, लेव्ही से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा । राम भगवान की मूर्ति, गौ-माता, सॉफ्ट हिंदुत्व भाजपा का एजेंडा हमने छीन लिया, इनके पास कोई विषय बाकी नहीं रहा । अरे, जिसको भी आप अपने विषय के रूप में अपनाते थे, सट्टा खेलाने के लिए अपनाते थे, पैसा उगाही के लिए अपनाते थे, जो विषय पांच साल के बजट की एक उपलब्धि बता दे कि छत्तीसगढ़ के जन जीवन के किसी क्षेत्र में परिवर्तन आया हो तो । कैसे फ्लैगशिप की योजना बनती थी ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आज आप किसानों को 3100 रूपए दे रहे हैं, वे भूपेश बघेल के कारण ही दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक काम गिना दो ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- छत्तीसगढ़ के अलावा जिस भी राज्य में आपकी सरकार है, क्या वहां आपने इतना पैसा दिया ? किसी और राज्य में आपने किसानों को 3100 रूपया दिया । छत्तीसगढ़ में यदि आपने दिया है तो भूपेश बघेल जी के कारण दिया । आपकी मजबूरी थी किसानों के लिए बात करना, किसानों के हक़ की बात करना (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ज्यादा नहीं बोलता पांच लाख करोड़ ही बोल देता हूं, शायद आप लोगों ने 86 हजार करोड़ से शुरू किया था । एक ऐसा काम बता जो छत्तीसगढ़ के जन जीवन में भविष्य में प्रभाव डालता हो । मंत्री जी को लोगों ने टोका, कहा कि अपने पांच साल की उपलब्धि तो बता दो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आत्मानंद स्कूल भविष्य के लिए बनाए गए थे ।

सभापति महोदय :- सुनिये ना, उनको बोलने दीजिए । आप लोग हर बात का जवाब देते रहेंगे । वे एक-एक प्रश्न उठाएंगे । आप बैठिये, अभी आपका नाम है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इस बजट में बड़ी-बड़ी बातें हैं लेकिन एक भी स्कूल के उन्नयन का प्रावधान नहीं है । सब भवन की स्थापना आपने कर दी लेकिन एक भी स्कूल का उन्नयन तो करना था । हमारे शासनकाल में तो गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोले थे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपका नाम भी है । आपका नाम आने वाला है । आप लोग बैठिये ना । देखिए, मैंने लखमा जी के समय भी सबको रोका, इनके समय भी बोल रहा हूं, टोकाटाकी मत कीजिए, बोलने दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- खुद चंद्राकर जी के उन्नयन नइ होए तो आने के का होही ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तो विष्णु का अवतार हुआ, इस राज्य में जो विष्णु सरकार बनी । यह उसी लूट एक्सटार्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार और गौ-माता के नाम पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है । मैं तो बोलता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण भी सर्वे घोटाला है। एक महीने में आपने सर्वे करवा दिया, 14 करोड़ रूपए फूंक दिये लेकिन उसमें निकला क्या । कोई भी क्षेत्र, अभी मेरा एक प्रश्न है । यादव जी, बहुत खड़े होथस । पैसा ढुलाई में 67 करोड़ रूपए खर्च किया गया। राम भगवान की मूर्ति में राजस्व आपदा मद का 24 करोड़, 25 करोड़ रूपए लगा दिया गया। आप पूछकर, खोदकर, पढ़कर तो देखिए, राजस्व मद का पैसा मूर्ति बनाने के लिए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। जो भूपेश बघेल का कानून...। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- केन्द्र की सरकार ने राम मंदिर का उद्घाटन किया तो क्या हम लोग राम की मूर्ति नहीं बना सकते ? जब केन्द्र सरकार राम मंदिर बना सकती है तो हम राम की मूर्ति नहीं बना सकते। इस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराईए कि राम की मूर्ति हटाई जाए।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, एक मिनट, आप क्या बोल रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में भा.ज.पा. ने राशन घोटाले में 13 हजार करोड़ घोटाला किया है।

सभापति महोदय :- आपको भी कुछ कहना है। आप पूछ लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने राम भगवान की मूर्ति पर आपत्ति आज तक नहीं लगाई। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि चंपारण में नहीं गए हैं, कोई वन गमन पथ में नहीं हैं, मैंने तो चैलेंज के साथ कहा है कि आप दोनों किताब टेबल कर दीजिए, सब कोई जान लेंगे। आप मंत्री थे, आप बताईए, राजस्व आपदा मद का 24 करोड़ रूपए मूर्ति बनाने के लिए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। मैंने तो हाथ नहीं उठाया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, 3600 करोड़ नॉन घोटाला में आपके अधिकारी अंदर थे। आप उसका भी तो जांच करवा दीजिए। घोटाले की बात करते हैं, राशन कार्ड में घोटाला हुआ था, आपका नॉन घोटाला हुआ...।

श्री अजय चंद्राकर :- पांच साल में मना किया था। आपके कलम चलाने के लिए क्या हाथ कांप रहे थे ? मेहंदी लगाकर बैठे थे क्या ? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में जांच करवाने के लिए मेहंदी लगी थी क्या ? कलम पकड़ने के लिए मेहंदी लगी थी क्या ? मेहंदी का रंग उड़ जाता क्या ? मेरा प्रश्न एक लाईन का है, राजस्व आपदा का पैसा मूर्ति लगाने के लिए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। माननीय विष्णु अवतार इसके लिए हुआ कि एक आदमी की स्वेच्छाचारिता, एक आदमी का कथन इस राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का पर्याय मानी जाती थी,वह कानून माना जाता था। विष्णु अवतार के बाद वह परिस्थिति बदली।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय सुनिए ना, ओ विष्णु अवतार के त्रिशूल हा, ओखर चक्र ला पेड़ काटे में लगा दे हव। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, अब थोड़ी देर मैं इनकी ओर आ जाता हूं, फिर मैं बजट में चर्चा शुरू करता हूं। मैं दूसरा शब्द बोल रहा हूं। कवासी लखमा जी दादी बैठे थे, तब इन्होंने शुरू किया। वह कौन आदमी उनका हिस्सा लेकर फरार हुआ है तो अभी तक बरामद नहीं हो रहा है। पूरा कांग्रेस का कोष फरार है। अब पेपर में छपा है तो उस दिन बोल दिया कितना पैसा जाता था तो नाराज हो रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, एक सेकंड। वन कटाई की बात आ रही है, कवर्धा के रेंगाखार जंगलों में पिछले 5 सालों में कितने वन कटे हैं और कितने पेड़ लगाए गये हैं, जरा उसका भी हिसाब ले ले भाई।

श्री रामकुमार यादव :- एके साथ जांच करवा दिहा।

श्रीमती भावना बोहरा :- जांच करवा लेबो ना। चिंता मर करव, जांच सबो चीज के होही।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, जब पिछले बाद स्मृति ईरानी वहां चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी। (व्यवधान) तो उसके दामाद की जांच। (व्यवधान) मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज स्मृति ईरानी कहां गयी ?

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर भैया एक मिनट, सभापति ओ समय डायलाग मारे, हमन सुने हन। हमर धर्मजीत सिंह हा, अतका अच्छा वक्ता रहय, हमन ओखर गोठ ला सुनन त हंसी लागय, शेर की कोई सीमा रहेगी क्या ? कोई शेर कहां मर रहा है उसको कोई जानेगा क्या ? जइसे ही ऐती ले ओती गे हे, हमर सभापति जी हा चुप बइठे हे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति के आसन में हैं, उस समय वहां टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब वे आसंदी के नीचे आएं तब आप टिप्पणी करिए। बहुत खड़े हो रहे हैं, अब दूसरी बात पर आ जाता हूं। कवासी लखमा जी का तो ले के फरार हैं, अभी पूरे कांग्रेस का कोष फरार है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपकी तरफ भी अभी यहां पर पूरी मंत्रिमंडल नहीं बैठी है।

श्री अजय चंद्राकर :- ओमे के बार आपत्ति लेबे। एक बार आपत्ति हो गयी।

सभापति महोदय :- देखिए, मंत्रिमंडल में 5-6 मंत्री हैं, इससे काम चलाईए। अभी बाद में आ जाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, दूसरी बात, रामकुमार जी बहुत बार खड़े होते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनका चेकअप कराएं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- जो अभी बोल रहे हैं उनका मत्रिमंडल में 13वें नंबर पर संभावना है क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- मे बरदी चरायेव, में पानी भरेंव, मे फलाना करेंव, ये कहानी बहुत हो गया। एक बार इतना ऊंचा बंडल देखकर बेहोश हो गये थे, फोटो में जो वायरल हुआ। (हंसी) उसको कोई अटैक वगैरह तो नहीं आ गया। उसकी जांच करवाईए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखकर आए हैं, कभी चाय बना रहा हूं कइथे, कभी कुछ कइथे।

श्री रामकुमार यादव :- अभी 15 लाख मोरे खाता में आवत रिहिस हे, ओ 15-15 के इहती तोए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ब्रम्हाण्ड का पहला शब्द ओम है। यह बजट बुक ओम का प्रकाश है। इस बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि शब्दों में मैं ओंकार हूं। मैं उस नौजवान मंत्री को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं उनको इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ बजट नहीं, विजन दस्तावेज के लिए नहीं वरन् एक विजन देने की शुरूआत की गई, नहीं तो विजन क्या था ? फ्लैगशिप योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी थी। अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी अभी भी उसका सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वह 5 साल तक चली और बजट से 5 रूपये नहीं मिला। वह वैसे ही खर्च हुआ, जैसे राजस्व आपदा का 24 करोड़ रूपये मूर्ति बनाने के लिए खर्च किया गया। मालूम नहीं कि कौन-कौन से पैसे को लूटकर अरबों रूपये उसमें बर्बाद किये गये। यदि पूर्व मंत्री जी यहां उपस्थित होते तो मैं बताता। आप एक भी गौठान बता दें। जो पाटन में बना होगा, कुरूदडीह में बना होगा और जिसको आप मॉडल, आदर्श, सक्रिय, निश्क्रिय और कितने प्रकार के शब्द बोलते थे। एक आदर्श गौठान के उद्घाटन में कवासी लखमा जी गये थे और बाकायदा वहां पर डांस किये थे। मैं कांग्रेस विधायक दल को आमंत्रित करता हूं कि वह कुरूद विधान सभा क्षेत्र के अरउद गांव में

चले। सबसे पहले हैलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जी कुरूद के हंचलपुर में गौठान का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और उसी गांव में रीपा का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे।

श्री भोलाराम साहू :- आप गौठान ला जेठ-बैशाख में खोजे बर गे रहे हो का ?

श्री अजय चंद्राकर :- तभे तो ते हा एती आए हस।

श्री भोलाराम साहू :- मैं तो एती बइठेच हो। तैं हा ओ डहार ले ए डहार आ गे हस। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं हा तो हो ना। एती ला ट्रेजरी बेंच कथे कि नहीं कहाए?

श्री भोलाराम साहू :- ठीक हे। ओ बात ट्रेजरी बेंच के हे।

श्री अजय चंद्राकर :- तोला जे दिन ट्रेजरी बेंच में बइठना रीहिस न, ते दिन एक झन बाइ तोर टिकट कटवा दीस। तैं अऊ तोर योग्यता हा माइ लोगन के पूर्तन नहीं होइस।

श्री भोलाराम साहू :- कोई बात नहीं, सुक्खा ट्रेजरी बेंच हे न। मैं अच्छा तगड़ा वोटा से जीत के ए डहार दूसर बार आ गेओ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह ओम प्रकाश है। मैंने कहा कि शब्दों का प्रकाश अर्थात् ओम प्रकाश।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी शब्दों के प्रकाश की बात करते हैं और अपने शब्दों में हमारे साहू जी को कभी महिला, कभी मेंहदी लगा लिये बोलते हैं तो कभी ओ.पी. चौधरी जी मछली बाजार बोलते थे तो आप इस तरह सभा का अपमान मत कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं सभा का अपमान तो अपने जीवन में नहीं करता। मेंहदी लगी थी एक उपमा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अच्छे शब्दों का चयन कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- हाथ में मेंहदी लगी थी और क्या दस्तखत करने से मेंहदी मिट जाती ? वह 36 करोड़ कितने रूपये का घोटाला बता रही थीं। यदि आप ज्यादा कहेंगी तो मैं 5 साल और आगे का बोल दूंगा। फिर खतरा हो जाएगा और आप बहिर्गमन कर देंगी। गड़बड़ हो जाएगा।

सभापति महोदय :- आप चंद्राकर जी को बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह 1 लाख, 47 हजार करोड़ रूपये का बजट है। यह 22 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि यहां से मिलेगा या वहां से मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने दृढ़ता दिखाई कि हम इस बजट को अपने राजस्व से 22 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। एक अर्थशास्त्री की समीक्षा है कि वित्त मंत्री जी ने राजस्व में होने वाले लिकेज को रोककर राज्य के स्वयं के राजस्व में 22 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह छत्तीसगढ़ और देश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री का बयान है। वह लिकेज क्या था ? मैंने बताया कि नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी, छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए मैदान बने हैं। तैं बता सकथस कि तोर विधान सभा क्षेत्र में के ठन मैदान बने हें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अटल श्रीवास्तव :- नहीं, मैदान नहीं बना है। ओलम्पिक का खेल हुआ है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए मैदान नहीं बना है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के खेल का आयोजन हुआ है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- ओलम्पिक का खेल हुआ है लेकिन मैदान कहीं नहीं बना है।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, आप कभू कबड्डी खेले हो ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं हा पानी भरे हो अऊ 500-500 के अतका ऊंच के गड्डी देखे हव।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, ओला ता देखेच हों। खाता में 15-15 लाख रूपये आए रीहिस। छत्तीसगढ़ में राज करे रहे हो ता का कभू कबड्डी खेले हो ? बांटी, भांवरा जानथों ?

सभापति महोदय :- एक मिनट। यादव जी, आप बहुत ज्यादा खड़े मत होइये। आप बैठिये और इनको थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं इनको माननीय खेल मंत्री जी का परसों-नरसों का उत्तर दिखा देता हूं। मेरा छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में प्रश्न है कि 46 करोड़ रूपये किसमें खर्च हुआ ? तो उन्होंने बताया है कि खेल मैदान बनाने और खेल सामग्री खरीदने में खर्चा हुआ है। सुन लीजिए, अटल श्रीवास्तव जी। मैं लिकेज का उदाहरण बता रहा हूं और उसको साबित कर रहा हूं। मैं पुन: बोल देता हूं। 67 करोड़ रूपए का पैरा ढुलाया है, 24 करोड़ रूपए की मूर्ति लगाई है । यह छोटा-छोटा उदाहरण है । आगे कभी बहुत अवसर आएंगे तो बड़े उदाहरण में आएंगे । क्योंकि सत्र के पहले सप्ताह में तीन दिन दोनों भाग गए हैं ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, उनके समय में स्कूटर में धान ढुलाई होती थी । यहीं पर जवाब दिया गया था ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- रतनजोत का साढ़े पॉच सौ करोड़ का क्या हिसाब है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, रतनजोत हो चाहे दुनिया का जोत हो। जब ये असहमत थे और चार महीने पहले तक सत्ता में थे तो किसने जांच कराने के लिए मना किया था ? हमने तो विपक्ष में बैठकर 10 बार बोला कि जिसमें आपको जांच करवाना है करवा लो । इसीलिए मैंने कहा कि जांच करवाने में हाथ में मेहंदी रची थी क्या ? आपको विपक्ष में इसीलिए बिठाया गया है कि 20 साल पहले की बात को गिनाते रहें, नई चीजें नहीं बता सकते ।

सभापति महोदय, अमृतकॉल का विजन और अमृतकाल के विजन में मैं इस नौजवान वित्त मंत्री के भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि 2037 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की परिकल्पना की है तो उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिकाएं क्या हो ? इन्होंने जो 10 पिलर्स तय किये हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- बुलेट ट्रेन चलाबो, केहे हव त ट्रेन ला बंद कर दे हवव। रायपुर बिलासपुर ट्रेन नहीं चल पावथे । यही तुहर विजन हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ज्ञान । उन्होंने ज्ञान को आगे परिभाषित किया है । तकनीकी रिफार्म और सुशासन, तीव्र विकास । तकनीकी रिफार्म । दादी, रिफार्म मतलब समझ गे हस न, किताब धरे हस या तैं ह सी.बी.आई. जांच भर ला समझे हस । तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करना, पूंजीगत व्यय में 22.5 हजार मतलब साढ़े बाईस हजार पूंजीगत व्यय में रखा गया है, जो 20 प्रतिशत वृद्धि है । आपके समय में 5 सालों में कभी भी किसी भी साल में 8 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं हुई । उन्होंने एक साल में 20 प्रतिशत की वृद्धि की, विष्णु अवतार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । दादी, अब पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मतलब क्या है ? अभी आपने भाषण दिया है तो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से बाहर तो निकल नहीं सके । दंतेवाड़ा में छविन्द्र कर्मा को निपटाने वाला यही, महेन्द्र कर्मा को निपटाने वाला यही सॉरी मोहन मरकाम को निपटाने वाला यही, संतराम नेताम को निपटाने वाला यही, दीपक बैज को निपटाने वाला यही ।

श्री लखेश्वर बघेल :- महेन्द्र कर्मा को निपटाने वाला यही, ये कोई बात थोड़ी हुई । महेन्द्र कर्मा को निपटाने वाली बात आप मत बोलिए ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झीरम की घटना की जांच होनी चाहिए। आपने जो आयोग बनाया था, उसकी भी रिपोर्ट अधूरी है । आप जांच कराईए कि झीरम की घटना में कौन जिम्मेदार था, जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

श्री लखेश्वर बघेल :- आपने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया कि महेन्द्र कर्मा को निपटाने वाला यही । ऐसी बात मत करिए । श्री रामकुमार यादव :- ये गलत बात हे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- झीरम के सच को जेब में लेकर चलने वाले उस सच को तो पहले निकालिए ।

सभापति महोदय :- हो गया, अब आप लोग बैठिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बस्तर में एक आदमी बचा है । अब इनके पुत्र का नाम मैं नहीं ले सकता, वह हमारा भतीजा है । कवासी लखमा और पुत्र, बाकी बस्तर से कांग्रेस साफ होना चाहिए । दीपक बैज जी भी हारे, भले वह पी.सी.सी. के अध्यक्ष रहे हों । माननीय लखमा जी, आपने हमारे लिए जो योगदान दिया, उसको हम शताब्दियों तक याद रखेंगे, उसे हम सदैव याद रखेंगे । (मेजों की थपथपाहट) आप निपटाईए ।

सभापति महोदय, अर्थ व्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल । प्राकृतिक संसाधन में मैंने पूरे पांच साल में सिर्फ एक शब्द सुना कि जंगल का दोहन, खनिज का दोहन कैसे होगा ? आरीडोंगरी को ऑनलाईन किया गया, सिर्फ यही बात मैंने सुनी, जिसको ऑन लाईन करने की घोषणा

हुई । जंगल की बात हुई, जंगल फैला-फैला बोलते हैं, लेकिन मैंने पूरे ध्यान से सुना कि लेंटाना उन्मूलन में दो-तीन साल मिलाकर पूरे 700 करोड़ रूपए व्यय हुए और वह ऐसा व्यय है, जिसको कोई नहीं देखता । क्या लेंटाना है, उसको जंगल में रहने वाले नहीं जानते । रामकुमार जी, आप जंगल में रहते हो, लेंटाना उन्मूलन क्या है, जानते हो क्या ? उसके उन्मूलन में 700 करोड़ रूपए व्यय हो गए । अनिला जी, तैं तो थोड़ बहुत जानत होबे कि लेंटाना ला कब निकालथे तेला, सहसपुर लोहारा में तको जंगल हे । आपके लिए अवसर ही अवसर है । वही पैसे बचाकर चौधरी साहब 20-22 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर । सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है ? 40 हजार करोड़ रूपए के स्थानीय एम.ओ.यू. हुए, मैंने उस दिन कहा था कि स्थानीय उद्योगपतियों से एम.ओ.यू. हुए, लेकिन आज तक एक नारियल नहीं फूटा। इन्टीग्रेटेड इस्पात संयंत्र बनेगा और प्रति मिट्रिक टन इतना पैसा एम.ओ.यू. में देना पड़ेगा = यह छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश है। पिछले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला ? दो पूर्व मंत्री बैठे हैं, मैं जब रोजगार विषय पर आऊंगा, तो उस पर बात करूंगा। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना है।

श्री रामकुमार यादव :- आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे हावा, लेकिन हमरे कार्यकाल मा प्रोफेसर मन के भर्ती होय हे। का बात करथा ? आप मन जो 10 साल मा नइ कर सका, तेला हमन 5 साल मा प्रोफेसर के भर्ती करके दिखाय रहेन।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, 5 साल में पद बढ़ते गये, वह पद 900 से शुरू होकर 2100 तक पहुंचा, लेकिन भर्ती नहीं हुई। खाली हर साल पी.एस.सी. में पदों की संख्या बढ़ती गई। तोर दिमाग हा पांच सौ के अतेक उच के देख के चल गय हे।

श्री रामकुमार यादव :- मोर दिमाग हा चलही तो तमन सब साफ हो जाहा।

श्री सुशांत शुक्ला :- यादव जी, थोड़ा पढ़ भी लिया करो।

श्री रामकुमार यादव :- शुक्ला जी, मैं पढ़े नइ हव, लेकिन कढ़े हव। तुमन इहा जो करथ हा, ओ मन सब दूरबीन लगाके देखत हावय।

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल मा पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ओती बैठा देइस।

श्री रामकुमार यादव :- प्रोफेसर भर्ती हमर कार्यकाल मा होय हावय। हमर सरकार हा भर्ती करे रहिस हे। हमन पुलिस के भर्ती करे हवन।

श्री सुशांत शुक्ला :- छत्तीसगढ़ ला कैसे करे हा कि जनता उहां बैठा देइस हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओखर काम ही हावय। वैसन-वैसन दस झन मोला डिस्टर्ब नइ कर सकय। ease of doing क्या होता है, उसको एक भी पूर्व मंत्री नहीं जानते और ना एक भी कांग्रेसी जानते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- ये हा दूसरा बृहस्पति सिंह हे, याद रखबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओ हा मोरे मर्डर करा देही का ? सभापति महोदय, निवेश मतलब निजी होगा, कोई आयेगा, हमको इससे मतलब नहीं है। जो भी छत्तीसगढ़ आयेगा, वह नकदी क्या देकर जायेगा, वह बात करो, कितने को रोजगार मिलेगा, कितने को रोजगार नहीं मिलेगा, मतलब नहीं था। कई अच्छे लोग आना चाह रहे थे, यह प्रदेश संसाधनों से भरपूर है। परन्तु इतनी एन्ट्री मांगी गई, वह सुनकर ही वापस हो गये, उधर दक्षिण वाले सुकमा से वापस हो गये, उत्तर वाले ईब नदी के पार से अंदर नहीं घुसे, जो उड़ीसा तरफ से आ रहे थे, वह सिंघोड़ा के पास ही रूक गये। हम कहां-कहां एन्ट्री देंगे, समझ में नहीं आता, कहते थे। यहां हमारे वित्तमंत्री जी ने कहा कि यहां ऐसा वातावरण बनायेंगे और ऐसा काउन्टर होगा जिससे उसकी तुरन्त स्वीकृति मिले, उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, यह भाषण में कहा है, आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं नहीं जानता हूं।

सभापति महोदय, हमारे साथी बस्तर-बस्तर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि look east. जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, हम उसको मुख्य धारा में शामिल करेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी मणीपुर का क्या हाल है ? पहले मणीपुर को तो सुधार लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन लीजिये। आज जी छपा है। उन्होंने वायब्रेंट विलेज बनाया है, देश का पहला गांव जिसके आखिरी सीमा तक इस साल रेल्वे लाईन पहुंच जायेगी, आप दिल्ली से श्रीनगर तक रेल्वे लाईन से जायेंगे। आप गांव पहुंच जायेंगे, आज ही पेपर में छपा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- क्या वंदेभारत के जैसे रहेगा ? ट्रेन वंदेभारत जैसे होगा क्या, जिसमें आदमी बैठ ही ना सके, आम आदमी बैठ ही ना पाये ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- रेल लाईन बिछेगी, यह अच्छी बात है। लेकिन वह यात्रियों के लिए रहेगा या अडानी का माल ढुलाई के लिए चलेगी ? आप इसको भी बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, वह परिकल्पना है, ताकि मुख्य धारा में सरगुजा, बस्तर की ओर देखो। सरगुजा बस्तर की ओर देखो का मतलब क्या ? आप जिस स्कूल को खोलने की बात करते हैं, मैं अभी सुकमा गया था, उस स्कूल में कितने मास्टर थे, ये लोग कभी नहीं बताये। यह कहते हैं कि हमने इतना स्कूल शुरू कर दिया, उसमें कितने मास्टर थे, वह भी तो बताओ ?

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर सरकार मा 3 हजार स्कूल बंद कराय रेहा। 3 हजार स्कूल ला ताला लगा के बंद करा दे रहा। आप मन का बात करथा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, ये स्कूल की बात करते हैं, रिक्त पद की बात करते हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न। एक मिनट चन्द्राकर जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, स्कूल के रिक्त पदों की बात कर रहे हैं तो इतना तो ख्याल रखते कि एक स्कूल को उन्नयन कर देते।

सभापति महोदय :- आप मेरी भी बात तो सुनिये। आप तो दो-तीन बार बोल चुकी हैं। मेरी बात सुन लीजिये। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह प्रक्रिया बिल्कुल उचित नहीं है कि प्रत्येक सदस्य के भाषण में पक्ष अथवा प्रतिपक्ष से सदस्य टोकाटाकी करें, इससे माहौल ठीक नहीं रहता है, कृपया माननीय सदस्य के भाषण में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें । जब आप भी भाषण करें तो उसमें भी कोई हस्तक्षेप न हो, यह सबसे आग्रह है ।

श्री कवासी लखमा :- उसको देखकर बोलों कि उधर देखकर बोले ।

सभापति महोदय :- मैं वह सब बोल देता हूँ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे कवासी लखमा जी पहले वक्ता थे, उनके पहले टोकाटाकी कितना हुआ है ?

सभापति महोदय :- मैं आपकी बात समझ गया । क्या है, बहुत से लोग हैं । 14 लोग आपकी तरफ से हैं, सब को बुलवाना है । एक-एक बात में, एक-एक लोग रोकेंगे तो ? मैं आपकी बात की तरफ सब का ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी माननीय सदस्य भाषण दें और जिसके बारे में भी जो भी कहना है, कृपया मुझे देखकर बोलें । मैं आपको पूरी तरह से देख रहा हूँ, ध्यानमग्न होकर देख रहा हूँ । आप मेरी तरफ देखकर जो बोलना है, बोल लीजिए ।

एक माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, भड़काय भर मत ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दादी को देख रहा हूँ और पुन्नूलाल मोहिले जी को देख रहा हूँ तो पुन्नूलाल जी को देखना पसंद करूंगा, उसमें देखने लायक है क्या कि मैं उसकी ओर देख के बात करूंगा ?

सभापति महोदय :- चलिये । अब आप बोलिये । अब बोलिये, भाषण दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- Decentralize Development Pockets, माननीय सभापति महोदय, कितनी बड़ी परिकल्पना है । यदि Development Pockets छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय असंतुलन किसी भी तरह से दूर होता है और उसके लिये कमिटमेंट आता है और यह दसों पिलर से एक परिकल्पना नहीं है, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास यानी सांकड़ लेंगे, पुन्नी नहाने के लिये कुदेंगे, जहां मर्जी आये राम भगवान की प्रतिमा लगाने घोषणा कर देंगे । मैंने उनसे पूछा था कि कभी बांडिंग की है कि दंतेवाड़ा की होली कैसे होती है, प्राकृतिक रंगों से खेली जाती है, 14 दिनों तक चलती है । चंपारन में मूर्ति लगाने गये, चंपारन में भारत का विशुद्ध द्वैतवाद दर्शन पैदा हुआ । वल्लभाचार्य जी आये । सनातन धर्म के पांच आचार्य, शंकराचार्य जी के बाद प्रमुख थे, छत्तीसगढ़ की धरती पर पैदा हुये । 84 बैठकों के प्रमुख बैठक नागार्जुन यहां पैदा हुये । बुद्ध यहां आये । विवेकानंद यहां रहे हैं । भूपेश बघेल जी ने सांकड़ लिया, यह संस्कृति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । केन्द्रीयकरण कैसा, सांस्कृतिक परिषद बनायेंगे, अमरजीत भगत जिधर बैठते थे, उनको दन्तविहीन, पंजाविहीन कर देंगे, सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी बनेंगे, आज तक उसकी कोई बैठक नहीं हो पाई है । यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधताओं पर दृष्टिकोंण था, यह बड़ा इश्यू था । शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका से ही कहा था कि नाम में क्या रखा है, प्रसिद्ध इंग्लिश नाटक हेमलेट में नाम में क्या रखा है, एक डायलॉग है । बृजमोहन जी के राजिम कुंभ नाम में ही आपत्ति थी, उसको पुन्नी मेला करेंगे । अब आप यह बताईये, देश विदेश के लोग उनको जाकर देखना चाहिये कि पांच साल में कितने विदेशी आये, कितने परप्रान्तीय आये, उसके पांच साल पहले कितने विदेशी, कितने परप्रान्तीय और कितने राष्ट्र और विदेश के सन्त आते थे और छत्तीसगढ़ की बात हर जगह कहते थे कि हमने एक कुंभ को उभरते देखा है । एक परम्परा को स्थापित होते देखा है...।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, नाम बदले के शुरूआत तो आप करे हव। प्रधानमंत्री आवास ला पी.एम.आवास, पैसा ला तुमन देवव । नाम ला तुमन बदलथव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भूमिहीन किसान योजना को इन लोग नाम चेंज किये हैं । नियम अनुसार आपको तो चेंज करना ही नहीं चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब असकट लाग ही ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी तीन ठन चेंज कर दे हे । शायद तुमन नई बैठे रहेव । मंत्री मन रिहीन होही ।

सभापति महोदय :- हो गया, बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्रियान्वयन पर जोर, यह सिर्फ पता नहीं है । सिर्फ लिखने की बात नहीं है, हम आर्थिक सलाहकार परिषद लायेंगे । यदि पांच लाख के जीडीपी को दस लाख ले जाना है, यह रोड मैप है, यह देवराय जी हो सकते हैं । कोई और आर्थिक सलाहकार परिषद बनेगी, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोग, एशियाई बैंक में यहीं के अफसर लोग हैं । आयेंगे, छत्तीसगढ़ को सलाह देंगे तो उस नवजवान मंत्री ने यह परिकल्पना की है । कभी एक दस्तावेज, कभी छत्तीसगढ़ के लिये कल्पना नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी से बाहर निकलें हों, आज प्रयास स्कूल का उल्लेख हुआ । पांच साल में उसके रिजल्ट गिर गये।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। उन्होंने परिभाषित किया था और मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का वाक्य किया था । यह एक सदी के लिये महत्वपूर्ण वाक्य हो सकता है। दूसरा, इस बजट में प्रिंट है। मैं बधाई देता हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं विषयांतर हो जाऊंगा। अभी श्वेत पत्र जारी हुआ, वह यूट्यूब में है। उस श्वेत पत्र की चर्चा को पूरे कांग्रेसजनों को सुनना चाहिए (मेजों की थपथपाहट) और अपनी क्षमता को देखना चाहिए कि 10 साल में एक मामला उद्घाटित नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में यू.पी.ए. सरकार के दौरान हर 10 दिन में, 10 सालों तक होता था।

10 साल में एक नहीं हुआ और हर 10 दिन में एक होता था। यदि यह कमिटमेंट इस नौजवान मंत्री ने, इस विष्णु सरकार ने दिखाया है, तो मैं उस कमिटमेंट की प्रशंसा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, तमाम चुनौतियों का क्या मतलब है ? लिकेजेस, खजाना खाली, कर्जा, रेवड़ी कल्चर के लिये। क्या आप किसानों को रेवड़ी कल्चर बोलते हैं ? जब मैं विपक्ष में होता था तब उन्होंने एक दिन मुझ पर आपत्ति लगा दी। यह राजीव गांधी मितान क्लब क्या है ? अब उसके लिये कहां से पैसे आये ? आज ही आपने मुझे उत्तर दिया है। इनके स्टाम्प में उपकर लगा था, उस उपकर का पैसा राजीव गांधी मितान क्लब को दिया गया। मुझे यह बताईये कि मितान क्लब ने क्या किया ? कौन से संस्कार मिले ? क्या उनके पैसे का ऑडिट हुआ ? कौन से विचार या एक गोष्टी हुई हो ? चलिये किसी गांव से एक-आत को बुलाईये और पूछिये कि छत्तीसगढ़ में विवेकानंद जी कब से कब तक रहे, वह यह बता दे ? आचार्य रजनीश छत्तीसगढ़ में कब से कब तक रहे, यह बता दे ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, आपने 15 साल छत्तीसगढ़ में राज किया है। आप बता दीजिये कि विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में कौन जानता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप बहुत खड़े हो रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि वह कांग्रेस के संस्थापक थे। यदि वह राजीव गांधी मितान क्लब के बारे में जानते हैं ? ते मोला तोर कांग्रेस के संस्थापक का पूरा नाम बता दें, मैं अभी बैठ जाता हूं, आप बता दो।

श्री रामकुमार यादव :- आप गुरू घासीदास के बारे में बतावव।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आप बतायेंगे पूरा नाम ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये न जी।

श्री रामकुमार यादव :- आप बताईये ना गुरू घासीदास जी के बारे में। क्या गुरू घासीदास जी के लिये बजट में कुछ रखे हैं?

सभापति महोदय :- यह प्रश्नोत्तरी नहीं है। आप बैठिये। आप क्यों खड़े हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह लोग कांग्रेसी बने हैं। इन्हें एक मिनट में सांप सूंघ गया। ये चुनौतियां हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- परंतु मैं क्यों आपके सवालों का जवाब दूं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, यह बजट पर भाषण है या कांग्रेस पर भाषण है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग अपने आप को बहुत होशियार बता रहे हैं, इसलिये मैंने कहा कि आप लोग कांग्रेसी बन रहे हैं तो मुझे उसके संस्थापक का पूरा नाम बता दीजिये। या नहीं तो मुझसे पूछ लेना। मैं प्रशिक्षण में आकर कांग्रेस के इतिहास में पूरा भाषण दे दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, हमू मन अतका जानत हव कि तुमन के संस्थापक हाफ पेंट वाले मन हावय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के लिये मोदी की गारंटी।

सभापति महोदय :- (श्री कवासी लखमा की ओर देखते हुए) अभी तो वह मेरी तरफ ही देख रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, इनको इस साल के बजट पर भाषण देना है। किसको सुनना है ? या 6 साल 15 साल, उधर ही भाषण देना है। आप क्या करने वाले हैं ? कितना पैसा लाये हैं ? हमारा 12 लाख रूपये कब देंगे ? किसानों को एक मुश्त राशि कब देंगे ? स्कूल कहां खोल रहे हैं ? सड़क किधर बन रही है ? उसकी बात छोड़कर इधर-उधर की बातें कर रहे हैं कि संस्थापक का नाम बताओ। क्या यह बजट में है ?

सभापति महोदय :- लखमा जी, आपके आदेशानुसार मैं उनको अपनी तरफ देखने के लिये बोल चुका हूं और वह सुन रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि आपका चेहरा देखने लायक है। मोदी जी की गारंटी। अभी मात्र तीसरा महीना चल रहा है। अभी पूरे नौ महीने हो जाये, फिर बच्चा होगा, तब आप नाम रख लेना। कृषक उन्नति लागू करने के लिये 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोदी जी का गारंटी का मतलब क्या होता है ? आपको कितने उदाहरण दूं, बताइये ? मैंने इसीलिये कहा कि आप श्वेत पत्र पढ़ लेना, यूट्यूब में देख लेना। भारतीय जनता पार्टी ने जो व्हाईट पेपर जारी किया है, उस पर छुट्टी के दिन भी बहस हुई है, आप उसको पढ़ लेना। यह 10 हजार करोड़ रूपये रखा है, आपको मिल जायेगा। दादी, आपके साथ पूरी सहानुभूति है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, जब कोरोना आया था तो आपकी केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रूपये दिया था लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को कितनी राशि मिली ? बस्तर को कितनी मिली ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मोर टाईम होथे। मे अब ज्यादा देर नइ बोलव।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी ला कोरोना काल मा थाली बजा के, लोटा बजा के, सुरता करथन, तुमन एकरे बूता करवाये रिहीन । ओही मा कोरोना भागही। गांव-गांव में थारी फूंट गे हे।

सभापति महोदय :- देखिये, इतनी टोका-टाकी में तो कोई भी सदस्य भाषण नहीं दे पायेंगे। मैं आप सब से आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप टोका-टाकी करेंगे तो वह भी टोका टाकी करेंगे।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, क्या यहां लोक सभा का भाषण हो रहा है ? मोदी जी, मोदी जी, आदमी कितना सुनेगा ? यहां आदिवासी आदमी साय साहब मुख्यमंत्री बन गये हैं, उनका नाम एक बार भी नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह हर बात में जात-पात ठीक नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, वित्त मंत्री का नाम नहीं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं, यह सिर्फ मोदी जी, मोदी जी कर रहे हैं। यह क्या है ?

सभापति महोदय :- बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो किसी खानदान के सामने अपना विवेक गिरवी नहीं रखा है। अपने राष्ट्र के सामने रखा है। अपने राष्ट्र नायक के सामने रखा है। (मेजों की थपथपाहट) आप समझ रहे हैं जिन्होंने देश में कहा कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। अब मैं गिनाऊंगा, मैं शुरू करूंगा कि अभी से वर्ष 1958 या 1961 तक जीप खरीदी की बात करूंगा तो सिर्फ देश में भ्रष्टाचार ही खुलेगा। मैं महतारी वंदन योजना की बात करूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आप यहां पर जीप खरीदी की बात कर रहे हैं। भाई, यह बताईये कि इस साल छत्तीसगढ़ में क्या होगा?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के बात ला कहात हौ तो महतारी वंदन योजना में फारम भरवा डरेव ता फिर काबर भरवाथौ।

सभापति महोदय :- माननीय यादव जी, यह उचित नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आप आवश्यकता से ज्यादा खड़े हो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ए हा हमन के बारे में कुछ भी कहात रही ता हमन सुनत रहिबो ?

सभापति महोदय :- यादव जी, आप आसंदी की बात मानिए। जितना आप खड़े हुए हैं उतना अभी तक कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में भी मोदी जी का उल्लेख हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का उल्लेख हुआ है। माननीय अजय चन्द्राकर जी देश के प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। वह प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके ऊपर में माननीय सदस्य आपत्ति ले रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। इतना ज्यादा interference करना, मुझे लगता है कि आपको या तो यह निर्णय देना चाहिए कि अब वह जो बोलेंगे, वह लिखा नहीं जाएगा। वह सभा की कार्यवाही में नहीं आएगा।

सभापति महोदय :- मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूँ। वक्ता के भाषण के बीच में माननीय सदस्य टोका-टाकी न करें। मैं आपको अवसर दे दूंगा। यहां दो, तीन, चार लोग खड़े होकर, हर बात, हर लकीर में एकदम आपत्ति ले रहे हैं, ऐसे में किसी माननीय सदस्य का भाषण नहीं हो पाएगा। जब आप

भी बोलेंगे। अगर यह ऐसा करेंगे तो आप भी अपनी बात नहीं बोल पायेंगे। इसलिए संसदीय परम्परा की मर्यादा का पालन करिये। वक्ता के भाषण के बीच में मत खड़े होईए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, उनको भाषण देते आधे घण्टे का समय हो गया। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसे मोदी ने बनाया। उसे अमित शाह ने बनाया। क्या उसे कवासी लखमा ने नहीं बनाया ? एक समाज के आदमी होने के कारण उनके नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं करेंगे। केवल मोदी-मोदी की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- देखिए। मैं उनको यह नहीं बोल सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप इसको तो निकाल दें। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह सभी जातियों के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्ग के हैं। उनके साथ बार-बार यह शब्द जोड़े तो यह मुख्यमंत्री जी का अपमान है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य एकाध बार बोलें तो ठीक है।

सभापति महोदय :- मैं एक चीज जानता हूँ कि अभी तक उन्होंने किसी भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अगर कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग हो तो आप आपत्ति करेंगे, मैं उस पर विचार करूंगा, लेकिन यहां बार-बार खड़े होकर, किसी भी सदस्य का कोई भी भाषण बाधित करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे बहुत तकलीफ भी होगी और मैं, आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार भाषण चलने तो दीजिए। वह आधे घण्टे से बोल रहे हों या पौन घण्टे से बोल रहे हों। अभी यहां पर कोई Compretive समय नहीं बता रहा हूँ। वह अपनी बात बोल रहे हैं मैं उनको अपना भाषण खत्म करने कहूंगा तब हम आगे बढ़ेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात बोलिए। मैंने आपको कहां मना किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में कहना चाहूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय चन्द्राकर जी, आप महतारी वंदन योजना की बात बता रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना में 45000 करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है। मैं जल जीवन मिशन योजना में एक बात बता देता हूँ। उस दिन विषय आया कि हमारा 35 वें नंबर पर परफारमेंस था अर्थात् यदि नीचे से गिनते तो हम पहले थे। यह हाथ उठा सकते थे। हम मेज थपथपा सकते थे। हम 24 वें नंबर पर आ गये। आप इसकी पृष्णभूमि थोड़ी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में यह दो साल पीछे क्यों हुई ? यह बिल्कुल जाकर शरणागत हो गए। यदि कैबिनेट सेन्ट्रल ठेका देगा तो माननीय बघेल जी, जहांपनाह, हम लोग भूखे मर जाएंगे। आप इसे डिसेन्ट्रलाईज कीजिए। हम लोगों को दादागिरी करते बनेगा और ठेका लेते बनेगा। आप इसे जिले में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दीजिए। हम लोगों ने सत्ता बनायी हैं हम कांग्रेसी हैं। हमारे कांग्रेसी होने के कुछ prvilaged हैं वह इन्हें कैसे दिखेगा? यह कैबिनेट में गये और कैबिनेट ने अपना निर्णय बदला, जिले में ठेका दिया। उसका कोई भगवान मालिक नहीं है। वे जल संसाधन मंत्री कहां हैं ? वह अब आये हैं। यह तीन महीने में दिखने लगा। हम 35 वें नंबर से 24 नंबर पर आ गये। जब हम तीन महीने के बाद जुलाई वाले सत्र में एकत्र होंगे तब आप देखिएगा कि यह कौन से नंबर पर रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, शहरी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में बताना चाहूंगा। मैं क्या बताऊ, माननीय भूपेश बघेल जी को इस शब्द से ही चिढ़ थी। यानी उनको आवास देना ही नहीं था। छत्तीसगढ़ में गरीब नहीं है। उन्होंने सर्वे करवाया। उसमें उतने आवासहीन हैं। 72 लाख और 56 लाख के बीच आवास हैं, करेक्ट 17-18 लाख आवास बैठता है। आवास 47 हजार को दिया। ग्रामीण आवास न्याय योजना, सबसे ज्यादा कहां दी गई? दुर्ग, सक्ती में सबसे ज्यादा आवास योजना दी गई। दुर्ग और सक्ती में कौन लोग रहते हैं और biefurcate करेंगे तो पाटन निकलेगा। 05 साल में छत्तीसगढ़ स्तर की मानसिकता नहीं बनाये और यह लोग विष्णुदेव साय जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इनका कृत्य देखिये, मैं कूकृत्य नहीं बोल रहा हूं। गरीब का मतलब पाटन, दुर्ग, सक्ती और थोड़ा बहुत बलौदाबाजार, जांजगीर, बिलासपुर को मिल गया और वह भी उन्हीं के एप्रोच में मिला। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज का एक प्रश्न है, रायपुर में 186 अवैध कॉलोनी हैं जिसमें जांच हुई, कॉलोनी तो ज्यादा हैं। आज उस उत्तर को अभी देख लीजिए। 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां छत्तीसगढ़ में हैं जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग, रायपुर, छोटा सा धमतरी जिला, एक और कोई जिला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कैसे लोग हैं? रायपुर में 186 के 186 अवैध कॉलोनियां जांच में प्रकियाधीन हैं और 12 अवैध कॉलोनियों के ऊपर एफ.आई.आर. की और 174 अवैध कॉलोनियों को पैसा लेकर छोड़ दिया, रायपुर को जाओ बेच खाओ। अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास हो रहा था। बृजमोहन जी के साथ मैं रोज बैठता हूं, उनकी पीड़ा को रोज सुनता हूं। माना के नया रायपुर के एयरपोर्ट से यदि रेलवे स्टेशन तक जायेंगे तो उतने पैसे में आप बस किराया में नागपुर पहुंच जायेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जीरो था। जो हमने शुरू किया था, हमने पी.एस.यू. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई थी, समितियां बनीं थीं। वह ध्वस्त हो गईं। 05 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं। सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ में मंहगा है। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी है, यह स्टेट केपिटल रिजन में प्रस्तावित है। सबसे ज्यादा अपराध इस स्टेट केपिटल रिजन मे है। अनियंत्रित है। रायपुर तो कलकत्ता बन रहा है, जाम का शहर बन रहा है। 05 साल में तो एक फ्लाईओवर नहीं बन सका। एक एक्सप्रेस हाईवे हम बंद करके रखे थे। अभी आप जाकर देख लीजिए। ग्रील उखाड़कर दुकान बन रही है, इन लोगों ने उसकी अनुमति दी है। यह किस मुंह से बात करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आवास नियोजित शहरीकरण एक विषय है। उसको वैसा नौजवान वित्त मंत्री और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नियोजित विकास को समझ सकते हैं। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई है और मैं तो कहता हूं इधर अभनपुर, आरंग, धरसींवा, तिल्दा तक उसको सुविस्तारित करना चाहिए और उसका मस्टर प्लान संयुक्त रूप से बने। एक विजन के साथ जो नगर निवेशक हैं, उनको बुलाकर करना चाहिए। अभी नगर निवेशक कौन हैं? जो भूपेश बघेल जी बोलें कि यहां पर मूर्ति लगेगी, यहां पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का पोस्टर लगेगा, यहां पर इस चौक का नामकरण इसके नाम पर हो जायेगा, ये गली इधर खुल जायेगी, यह बूढ़ातालाब का रास्ता बंद हो जायेगा, डिग्री गर्ल्स कॉलेज का रास्ता बंद कर दो, पानी निकासी को रोक दो, is equal to रायपुर का विकास है। आज आपने राजेश मूणत जी का पूरा ध्यानाकर्षण सुना है कि क्या स्मार्ट सिटी है? यह पता नहीं चला कि हजारों करोड़ रुपये किधर गये। जादू की सड़क, माननीय मंत्री जी ने संभागायुक्त से जांच कराने की घोषणा की है। यह सब कमजोरियां दूर होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और माननीय मंत्री जी ने जो स्तंभ बताये हैं, निवेश के लिए सबसे बेहतरीन नियोजित शहर यह केपिटल सिटी बनेगी जो भिलाई, दुर्ग, रायपुर को मिलाकर बनेगी। मैं उस दृष्टिकोण की, उस जज्बे की प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। अब विष्णु अवतार हो गया है तो छत्तीसगढ़ के लोग राम लला के दर्शन करेंगे ही। यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, यह बड़ा संवेदनशील विषय है। संस्कृति से छेड़छाड़ करने वाले एक ही आदमी भूपेश बघेल जी भर यहां पैदा हुए हैं। आपके बिलासपुर में ही पैदा हुए हैं। माता कौशल्या जी, ज्ञात इतिहास में चंदखुरी से उसका कोई संबंध ही नहीं है। यह फिर मैं पुस्तक टेबल कर दूंगा या वह लोग कर दें। हमारे भांजा, पुन्नूलाल जी मान लो धोखा से मरही ना, वैसे वो अमर खा के आये थे, अभी 5 घांव और जितही वोहा। मरही तो कोई भांजा एकर संग नखरा नई मार सकै। ये बोलही मैं अयोध्या ले ओरिजनल भांजा के दर्शन करके आ गये हौं, तैं नखरा मारबे त जा। छत्तीसगढ़ के लोग अपने भांजा का दर्शन करेंगे, छत्तीसगढ़ भर है जहां हम लोग अपने भांजा का चरण छूते हैं। लोगों की क्या अनुभूमि होगी? आपने योजना रखी है। मैं तो कहूंगा कि जो सालाना 35 करोड़ 20 हजार रखे हैं, उसको बढ़ाईये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ये भांचा के चरण छुए के परंपरा ला हमर भूपेश बघेल जी हा बनाए हे या ओखर बबा, पूरखा मन बनाए हे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तैं हर मोर बबा तक आ ही गए हस।

सभापति महोदय :- वह तो छत्तीसगढ़ की परम्परा बता रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओइ ला तो मैं हा पूछत हौं कि भांचा के पांव छुए के परंपरा हमन चालू करे हन का या हमर सरकार बने हे, ओ हर शुरू करे हे का?

सभापति महोदय :- उन्होंने तो सरकार कहा ही नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ओहर ओइ बात तो कहत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं शक्तिपीठ के बारे में कहना चाहूंगा। हमको Writist माने जाते है, हमको Orthodox माने जाते हैं, हमको दक्षिणपंथी माने जाते हैं। मेरे को नहीं मालूम कि हमको और कितने तरह से नवाजे गए। बीजू पटनायक देश के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे, वह पूंजीपति थे, उसके बाद भी वह समाजवादी धारा में थे। वह देश के पहले पायलट थे। उन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया। उनके सुपुत्र ने जगन्नाथ जी का जीर्णोद्धार कराया, परिक्रमा बनाई, केपिटल को बनाया। उन्होंने मां समलेश्वरी जी को समर्पित किया। एक साल में 40 से 45 लाख लोग देखने के लिए बनारस आते थे। आयोध्या मंदिर बनने के बाद 3 साल में 7 करोड़ ला चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) आयोध्या में प्रतिदिन 3 लाख का अनुमान था। शुरूआत के दिनों में 60 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। यह संकीर्णता से ऊपर उठकर सोचे कि सनातन स्थापति हो रहा है। उसके बारे में जानने, समझने और धार्मिक पर्यटन हिंदुस्तान में एक नया आकार ले रहा है। उसके लिए योगी जी यदि ओंकार का कमिटमेंट करते हैं । मैंने कहा कि ब्रम्हाण्ड का पहला शब्द, जिसका यह किताब प्रकाशित हो रहा है। यदि उसको साकार करने के लिए योगी जी कमिटमेंट करते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों है, भाई? हमको दस तरह के दक्षिणपंथी, Orthodox और क्या-क्या बोलते हैं न, वह सब बोलने की जरूरत क्यों है? माननीय सभापति महोदय, मैं इनवेस्ट छत्तीसगढ़ के बारे में बोल चुका हूं। इक्यूबेशन सेंटर के लिए 7 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के बारे में कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर में खतम कर रहा हूं। 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार बेरोजगारी क्या है, इसको परिभाषित नहीं कर सकी। इनके आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण में बेरोजगारों की संख्या 20 लाख है। इन्होंने एक सी.एस.एम.आई.आर. संस्था को पकड़ा था। उन्होंने लिखा था कि दशलव एक प्रतिशत बेरोजगारी दर है। रोजगार चाहने वालों की संख्या 19 लाख कुछ हजार है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में 2 करोड़ के विज्ञापन छप गए कि सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यह पागलपन है? आप 19 लाख रोजगार चाहने वाले बोलते हैं, 20 लाख बेराजगारों की गणना करवाते हैं, 10.1 प्रतिशत का पोस्टर लगवाते हैं तो यह बेराजगारों के साथ मजाक है या नहीं है? उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? आपको इसीलिए वोट मिला था? आप लोगों को इसीलिए 71 विधायकों का मेंडेट मिला था कि उस जवानों के साथ खिलवाड़ करें? विष्णु सरकार ने यह कहा है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को छोड़कर यह बूढ़ी होती जवानी है, जो विजन दस्तावेज जवान हिंदुस्तान होगा। वर्ष 2047 तक सबसे जवान हिंदुस्तान रहेगा। छत्तीसगढ़ की जवानी की दिशा क्या हो? रोजगार के अवसर कैसे बने? बृजमोहन जी आज मुझे बता रहे हैं कि मैंने 5 हजार

भर्ती के लिए लिख दिया है। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। उद्यम क्रांति योजना में ब्याज की सब्सिडी देंगे, स्टेट गारंटी देंगे। मैं आपको कहूंगा कि जो ई-विश्वकर्मा योजना है, उसका भी छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम विश्वकर्मा योजना में विस्तार करें। मान लीजिए कि यहां के लोगों को भी कोई कनरा छूट गया हो, कोई बेल मेटल वाला छूट दिया होगा, कोई शिल्प वाला छूट दिया होगा तो छत्तीसगढ़ अपने स्त्रोतों से क्या उसको प्रधानमंत्री ई-विश्वकर्मा योजना को विस्तार करके उनके लिए धातु का बैंक बनाकर, उसके लिए मिट्टी का बैंक बनाकर, उसके लिए बांस का बैंक बनाकर ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे विष्णु देव जी ने एक लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इसके लिए बजट में कहीं भी प्रावधान नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तीन महीना होए हे। मैं कहे हौं न कि 9 महीना के बाद बात करबे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, 3 महीने में बहुत से योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाता है। अभी तक न किसानों को, न युवाओं के, न महिलाओं के योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इंट्रेस्ट सब्सिडी और गारंटी फीस, यह बड़ी चीजें हैं। सभापति महोदय, प्रोजेक्ट बघुवा। प्रोजेक्ट बघवा लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इनकी दृष्टि में जैव विविधता का क्या मतलब है ? वन्य जीवों का क्या मतलब है ? पारिस्थितिक तंत्र का क्या मतलब है, कुछ नहीं । बाबा जी का ठुल्लू ।

श्री लखेश्वर बघेल :- यह ठुल्लू क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह बिल्कुल असंसदीय नहीं है । आप जाकर सेंसर बोर्ड से लड़िये, मैं किसी सीरियल के शब्दों का उपयोग कर रहा हूं । यदि गलत होगा तो आपके दिमाग में गलत होगा, मेरे शब्दों में गलती नहीं है । माननीय सभापति महोदय, 60 से ज्यादा हाथी और अभी एक सप्ताह पहले एक बघवा करेंट लगाकर मारा गया । एक के ऊपर तो कार्यवाही हुई हो । उसकी तस्करी हमारा मुख्य धंधा है तो फिर उसमें कार्यवाही का सवाल कहां से उठता है ? अब इन प्रयत्नों से, रोजगार के अवसरों से अतिरिक्त आप देखिये कि दृष्टिकोण का प्रभाव कैसे होगा ? पूंजीगत निवेश से प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जीवनस्तर सुधरेगा, व्यापार-उद्योग को बढ़ावा मिलेगा । पूंजीगत व्यय बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो प्राथमिक सेक्टर हैं उन सबमें हमको फायदा होगा । माननीय सभापति महोदय, अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ता हूं ।

माननीय वित्तमंत्री महोदय, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोवेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन (Milton friedman) ने कहा था कि अक्सर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम नीतियों व योजनाओं का मूल्यांकन उनके ईरादे से करते हैं न कि उनके परिणाम से । इस बजट के ईरादे न केवल नेक हैं अपितु

इसमें परिणामों का भी उल्लेख है । अर्थशास्त्री ने कहा है कि असली बजट यह होता है और इस विष्णु सरकार ने ऐसा बजट लाया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय चंद्राकर जी, 500 रूपये में गैस-सिलेण्डर देबो कहे रहेओ । तेकर उल्लेख आप नइ करे हओ । उहू ला बोल देतेओ ता हमन सुन लेतेन । महतारी वंदन योजना अउ 500 रूपये में गैस-सिलेण्डर ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी ओला झन बोल । तें बोलथस ता ओला सांप सूंघ जात हे ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जी । मैंने तो सबको रख दिया, मैं खाली हाथ हो गया हूं । जितनी योजनाएं हैं वह बिग पुश (Big push) है, एक कमिटमेंट है, एक जज्बा है । छत्तीसगढ़ के जो असली धरती पुत्र होते हैं वह लूटते नहीं हैं, लूटते नहीं तो ये सामना करते हैं, गायब नहीं होते । हर बात में, किसी भी विषय में बात कर लें, करप्शन के सिवाय नहीं निकलेगा । इनकी ओर से पहला जो बजट आया, इस नौजवान वित्तमंत्री की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रिगण जिन्होंने अपने विभाग में नयी बातें कही हैं उन सबकी प्रशंसा करते हुए और पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, पहला वक्ता बढिया बोले । लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बोली । (व्यवधान) चूंकि वित्तमंत्री ने बोला था कि 157 साल का यह बजट उसका उल्लेख नहीं किये । (व्यवधान) उन्होंने 157 साल बोला, आपने उसके बारे में नहीं बोला, क्या आप उसके विरोधी हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने उज्जवला योजना और महतारी वंदन योजना की बात ही नहीं की है ।

सभापति महोदय :- लखमा जी, आप जब बोले तो मैंने पूरी तरह से आपको भी समय दिया । उधर से पहले वक्ता वे थे, उनको भी समय दिया । बाकी सभी से जल्दी करने के लिये आग्रह है । एक-दूसरे को टोकेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, नहीं टोकेंगे तो बढ़िया बोलने दीजिये । अपनी-अपनी बात कहिये न, कौन रोक रहा है । बोलिये ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का विरोध करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । अभी-अभी अजय चंद्राकर जी का भाषण सभी लोग सुन रहे थे तो बजट भाषण और इनके भाषण में हमारी सरकार को खूब कोसने का प्रयास इनकी बजट पुस्तिका में है और इन्होंने बेबुनियाद आरोप भी लगाये हैं । हम चुनौती देते हैं कि

हम उनके एक-एक बेबुनियाद आरोप पर बोलने का प्रयास करेंगे । अपने अमृत काल, मोदी की गारंटी को महत्व देते हुए हर शब्दों में मोदी जी की चर्चा करते हुए अपने बजट के भाषण में कम, अन्य मुद्दों को लेकर इस सदन को गुमराह करने का प्रयास, उकसाने का प्रयास रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- समय बोलने से आपका नाम लिया। पहले नहीं बोलता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आथो, एक मिनट में पानी पीकर आथो। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, अलग-अलग रीति-रिवाज, अलग-अलग खान-पान, रहन-सहन होने के बावजूद हम लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक साथ जीवनयापन करते हैं और अभी से नहीं आदिकाल से और एक-दूसरे की संस्कृति और परंपरा का हम लोग सम्मान करते हैं। जब भक्त माता कर्मा की रैली निकलेगी तो आदिवासी भाई उसका सम्मान करते हैं। जब आदिवासी का त्यौहार होता है तो सतनामी समाज के लोग उनका सम्मान करते हुए उस गांव की रैली में शामिल होते हैं और जब गुरू घासीदास जी की रैली निकलती है तो उसमें नारियल चढ़ाने की और उसमें सम्मान करने की परंपरा है। हमारे देहातों में गांव में देवी-देवता का वास है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा, वे अपने गांव के पटेल और सरपंचों से पूछेंगे कि अपने गांव में कितने नारियल फोड़ते हैं और कितना त्यौहार मनाते हैं? तो कहीं कहीं गांव में 17 नारियल, 18 नारियल, 20 नारियल फोड़ते हैं और वह नारियल फोड़ने का मकसद है कि हमारे पूर्वजों ने पूरे देवी-देवताओं के साथ आस्था जगाने का प्रयास पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते आये हैं। उन्हीं के कारण हम एक-दूसरे की संस्कृति और परंपरा और मान्यताओं और देवी-देवताओं का सम्मान करने का हमें संस्कार मिला है। माता देवाला का निर्माण किसने किया? अब मैं पूछूंगा तो एक भी इनके दादा और पिताजी कोई बताने वाले तैयार नहीं रहेंगे। उसकी स्थापना देखो कि किसने किया? और आज भी वह परंपरा चली आ रही है और आज भी हम लोग वह नारियल फोड़ते हैं। आज भी उस त्यौहार को मनाते हैं और आज भी उस गांव के पटेल और जो बैगा हैं, उस रीति-रिवाज को निभाते हैं। धर्म के साथ जोड़ने का काम किया है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- आदरणीय सभापति महोदय, हमारे सदस्य ने जिस तरह से कहा कि हम ग्राम पंचायतों में नारियल फोड़ते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली जो सरकार थी, उसमें किसी भी ग्राम पंचायत को कहीं पर भी एक भी नारियल फोड़ने का मौका नहीं मिला। जितना भी ग्राम पंचायत में काम हुआ है, पूरे टेण्डर में काम हुआ है। ग्राम पंचायत ने कहीं भी नारियल नहीं फोड़ा है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं देवी-देवताओं की बात कर रहा हूं। यह कोई निर्माण कार्य का नारियल फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। गांव के रीति-रिवाज की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप बोलिए न, आप अपनी बात कहिए।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- सदस्य बोलते हैं कि रीति-रिवाज में फोड़ते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में कभी भी..।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- वे दूसरी बात बोल रहे हैं। आप बैठिए न।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। आप तो विरोध करने के आदी हो गये हो तो विरोध ही नजर आयेगा न।

सभापति महोदय :- आप उधर देखकर मत बोलिए न। आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री दलेश्वर साहू :- जी सर। सभापति महोदय, ये परंपरा धर्म के साथ जोड़ने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है और यह हमारे संस्कार में है। जब से हम जन्म लेते हैं और थोड़ा सा होश संभालते हैं तो हमारे घर के किसी कोंटा पर देवी-देवता का वास, दिवालों में प्रभु श्रीराम की फोटो तो कभी शंकर जी की फोटो, आप चिंतन करो, मनन करो, बचपन से श्रीराम की फोटो को देखते आ रहे हैं। शंकर जी की फोटो को भी देखते आ रहे हैं। गांव-गांव में पीपल की छांव में हनुमान जी का एक त्रिकोणीया टाइप का पत्थर लगाकर बंदन लगाना, धर्म के साथ जोड़ने का काम ये हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में है। आज धर्म के उन्माद राम इन्हीं का है। राम हमारा नहीं है। राम हम सब लोगों का है। सभापति महोदय, अभी आपको बताउंगा हमारे लोक मड़ई महोत्सव होता है और 20 साल से मध्यप्रदेश शासनकाल से है। ये परंपरा है तो हमने कहा कि हर साल कभी भोरमदेव का मंदिर, कभी जगन्नाथ का मंदिर बनाकर दृश्य, कलकत्ता वाले बनाने वाले आते हैं और महोत्सव को, संस्कृति को, परंपरा को एक धर्म के साथ जोड़ने का हमारा मकसद रहता है और 21 साल से परंपरा चली आ रही है तो हमने कहा कि इस समय अयोध्या का मंदिर बनायेंगे। संस्कृति विभाग से पैसा आता है।

समय
4.00 बजे

कृषि मेले का भी आयोजन होता है । हमने एक मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया और कलकत्ता से मंदिर बनाने वाले कारीगर भी आ गए हैं । हमने ले-आऊट दे दिया और बनाना भी शुरू कर दिया । इस समय के महोत्सव में राम मंदिर बनेगा और वहां राम लला विराजित होंगे । चूंकि मैं कांग्रेसी हूं इसलिए इन्होंने इसका भी विरोध किया कि इसको बांस नहीं मिलना चाहिए, बल्ली नहीं मिलना चाहिए । मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं । चूंकि धर्म का मामला है, हमारे अजय चंद्राकर जी ने बहुत सारी बातें कही तो मैंने कहा कि राम तो आपके भी हैं और हमारे भी हैं । सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप 23, 24, 25 तारीख को आप जरूर आइएगा । आज भी वृहद स्तर पर काम चल रहा है । किंतु वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह मंदिर मैं बनवा रहा हूं । तुम उसी काम को करो तो सही, यदि उसी काम को मैं करूं तो अनर्थ, ऐसी इनकी मानसिकता

है । हमारे भूपेश बघेल जी ने कितना बढ़िया राम वन गमन पथ के विकास का कार्य प्रारंभ किया । राम जी 14 साल के वनवास में से 10 साल छत्तीसगढ़ में रहे हैं । 10 साल यहां रहे तो राम जी चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे, इधर-उधर कहीं न कहीं गुजरे होंगे । वे जहां-जहां गए उस स्थान को राम गमन पथ के रूप में जोड़ने का काम किया है । मैंने कहा ग्रामीण अंचलों में देवी, देवताओं का वास है, देवगुड़ी आदि के लिए बहुत से काम उन्होंने किये । इन योजनाओं को बजट के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए ।

वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है । इन्होंने लिखा है कि GYAN हमारे आर्थिक विकास का केन्द्र बिंदु है । GYAN में जी अर्थात गरीब, वाय अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी । सभापति महोदय, ऐसा भी हो सकता है कि GYAN में जी का अर्थ गरीब तो है, इसके अलावा घमंड भी हो सकता है । उस G को घमंड के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं । यदि नीयत साफ़ नहीं रही तो घमंड भी पैदा करेगा । गरीब का पैसा गबन भी होगा, गरीब का पैसा कोई भी गबन करने का प्रयास करेंगे । ये इन्हीं की भाषा है । Y अर्थात युवा, युथ जैसी इनकी प्रवृत्ति है । देखो, पुरानी बातों को लेकर कैसे लड़ाई कर रहे थे । यमन होता है, युवाओं के हक को नियम से बांधने का काम इस बजट में इनकी सोच है । A अर्थात अन्नदाता, A से अहंकार भी झलकता है, किसानों के साथ अन्याय का प्रयास इस बजट में झलकता है, ऐसा परिदृश्य दिख रहा है । N का मतलब नारी, N से निराशा नज़र आती है । नारी के साथ अन्याय । इन्होंने नेल्सन मंडेला के कथन को भी इसमें जोड़ा है । किसी देश को तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती, शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना ही काफी है । नेल्सन मंडला ने यह भी लिखा है कि मनुष्य की अच्छाई, ज्योति के लौ के समान है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता । आप अपने स्तर पर परिभाषित करना अलग विषय है लेकिन किसी महापुरूष के वचन को धरातल पर उतारना कठिन है, लिखने से कुछ नहीं होता । जब अगले बजट में जाएंगे तब बात करेंगे । जैसे कि सेवा शब्द कितना सरल है, जब उसको प्रमाणिकता के साथ उतारेंगे। विधायक दल की जब बैठक हुई थी, इस समय भी प्रबोधन हुआ था, एक अच्छे विधायक बनने का सबको गुरूमंत्र मिलता है और अनुभवी आदमी को बुलाया जाता है, मैं इस समय नहीं पहुंच पाया। उस समय प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि जीवन में प्रमाणिकता होना चाहिए। अगर प्रमाणिकता है तो सब कुछ किया जा सकता है, जब आप प्रमाणिकता की भाषा बोलोगे तो कितना कठिन काम होता है, आप जरा सोचिए। जैसे मेरे पास एक मरीज आया। उन्होंने कहा मेरा बॉप हास्पिटल में है, ईलाज करा दीजिएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं टेलीफोन उठाऊंगा और डॉक्टर से बात करूंगा। उस टेलीफोन में डॉ. का नंबर कवरेज एरिया से बाहर है। उन्होंने देखा है कि आपने प्रयास किया है। क्या उनका काम हुआ, नहीं हुआ ? आप चाहोगे तो और दूसरा काम कर सकते हो। उस शहर में आपका कोई और आदमी होगा, उनको फोन लगाईए। जाईए उनकी मदद करिए, मेरा आदमी वहां पर हास्पिटल में भर्ती है, उनका ईलाज करना है। चलो आप जिनको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाह रहे हो, वह आदमी भी नहीं मिला। वह आदमी बैठा-बैठा सुन रहा है। वह संतुष्ट हो गया, चलिए मेरे लिए प्रयास किया। लेकिन वह जो व्यथा लेकर आया है, वह जो सोचकर आया है, क्या उनका ईलाज हुआ ? जब तक उनकी डॉ. से बात नहीं होगी, वह संतुष्ट नहीं होगा। डॉ. से बात होने पर वह अपने कर्तव्य के प्रति आपकी बातों को कितनी तवज्जह देगा, उसके उपर भी डिपेंड होता है। वह लिंक कहीं ना कहीं एक दूसरे के कारण से मकसद पूरा होता है। प्रमाणिकता शब्द को परिभाषित करके जीवन में उतारना बहुत कठिन काम है। वित्त मंत्री जी, हमने आपका बजट पढ़ लिया, जब और बात होगी तो एक-एक करके गिनाएंगे। जैसे हमारे चंद्राकर जी गिना रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य समाप्त करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- जी। सभापति महोदय, अभी चंद्राकर जी बोल रहे थे, अभी पैसे के दुरूपयोग की बात कर रहे थे। हमारे दयाल साहब संस्कृति मंत्री हुआ करते थे। अभी चंद्राकर जी ने कहा कि मद परिवर्तन करके कैसे खर्च कर दिया। कलाकारों के पैसे से अपने गांव में लाटा महराज का कार्यक्रम करा दिए। अब वे सुनते तो मैं बताता, इधर ध्यान ही नहीं है। ऐसे कई बजट को परिवर्तन करके...।

खाद्य मंत्री (श्री दयाल दास बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं। मैंने किसको नहीं दिया है, आप पूछिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है? उसमें कितना बजट रहता है? दूसरी बात, वन गमन पथ की बात करते हो, उसका मैप किसके कार्यकाल में तैयार हुआ है। आप उसको देख लीजिए। पूरा मैप मेरे ही कार्यकाल का संस्कृति विभाग का है। सैद्धांतिक स्वीकृति भी उसी कार्यकाल का है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ओ समय कहां के तुंहा छत्तीसगढ़िया कलाकार लाव, ओ समय सलमान खान, चिरहा पहिन के आतिस, दो करोड़ रूपा ओला धरा दे। ऐश्वर्या राय आतिस ओला 2 करोड़ रूपया धरा दे। अइसे ओ समय चलत रिहिस हावए।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे कार्यक्रम में सभी विधायकों को दिया गया था। गांव में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था। पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम हुआ है। आप जाकर पता कर लीजिए। (मेजों की थपथपाहट) जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, सबको पूछ लीजिए। सबको काम दिया गया था।

सभापति महोदय :- वे आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप बैठिए, आपने अच्छा कहा। आपने अपनी बात बता दी। आप समाप्त करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने आरोप नहीं लगाया। सभापति जी, मैंने परिवर्तनगत बात की, आपने नहीं दी, मैंने तो बोला ही नहीं है। आपने सबकी मदद की है। आपके एक सक्षम मंत्री जब ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, आपको उसमें ब्रेक लगाना चाहिए, उन कलाकारों के पैसे से हम कैसे धार्मिक आयोजन करेंगे? आयोजन हुआ है और कभी मौका लगेगा तो मैं आपको सबूत बताऊंगा।

मेरे बोलने का मकसद यह है। दयाल जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप तो सीधे-सादे हैं। एक सामर्थ्यवान मंत्री के पैसे का यूटिलाइजेशन दूसरी तरफ किया गया। मैंने इसके उदाहरण के लिए यह बात कही।

श्री धर्मजीत सिंह :- हो गया, वह समझ गये। आप आगे बढ़िये और समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में दिल छूने वाली कई योजनाएं संचालित कीं। ठीक है, एक नयी योजना होने के कारण वह धरातल पर दिखनी चाहिए। शुरूआती तौर पर कोई भी योजना इतनी जल्दी स्वरूप नहीं लेती है। आप जितनी भी योजनाओं को देखेंगे। अभी इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए शुरूआत की। हम भी कुछ फिगर बताने का प्रयास करेंगे। आप यह बताइये कि गरीबी हटाने के लिए मनरेगा योजना (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना) किसकी देन है? शुरूआती तौर पर इसको लांच करने के लिए इसे कानून बनाया गया और गरीबी को मिटाने के लिए 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार के माध्यम से हुआ। लोग उनका हंसी-मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज भी वह योजना लागू है और उसको लागू करना मजबूरी है। यदि उसको लागू नहीं करेंगे तो इन्होंने जो वातावरण बनाने का प्रयास किया है, वह संभव नहीं होता।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वालों के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से काम हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, त्योहार, परंपरा को संजोने का प्रयास किया। हरेला किसानों का कितना शानदार त्योहार होता है। जब हम किसान के हित की बात करते हैं। हरेली के त्योहार को लोग भूल रहे थे। यदि सुबह से बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएं और उस परपंरा, रीति-रिवाज और पूजा करने की स्थिति को न देखें तो क्या स्थिति पैदा होगी ? इस परंपरा को कैसे निभाया जा सकता है ? हमारे दिल को छूने वाले ऐसे भूपेश बघेल जी ने हरेला, तीजा, कर्मा जैसे अनेक त्योहारों और आदिवासी का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए आदिवासी विश्व दिवस के रूप में स्थापित किया। पूरे लोक कलाकारों को बुलाकर आदिवासी महोत्सव के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करने का काम किया।

सभापति महोदय :- अब समाप्त कीजिए। श्री अनुज शर्मा जी।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा एक पर्सनली मामला है इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि अभी मैं तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं। अभी इनकी नीयत और नियती में इतनी सोच बदल गई है। मेरा क्षेत्र 60 प्रतिशत नक्सल प्रभावित बेल्ट है। मैंने ध्यानाकर्षण लगाया। मैंने अध्यक्ष महोदय से भी रिक्वेस्ट किया था कि मैं कम से कम जंगल में दौरे पर तो जा सकूं। आप मेरे घर की सुरक्षा हटा दीजिए, परंतु आपने परंपरा बनाई थी कि जब हम

नक्सल बेल्ट में दौरे पर जाते थे तो किसी थाने का T.I. चला जाता था या किसी पुलिस की व्यवस्था कर देते थे या फॉलोगार्ड भेज देते थे। जैसे ही मैंने तीसरी बार चुनाव जीता है तो सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह बहुत गंभीर बात है। यह विधान सभा की सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री दलेश्वर साहू :- यह कितनी गंभीर बात है। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हमारे साथ भी यही स्थिति है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मेरा आपसे इसमें निवेदन है। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसमें आदेशित करें।

सभापति महोदय :- यह बोल रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कम कर दी गई, तब भी इनको चिंता करनी चाहिए थी।

श्री रामकुमार यादव :- ए नक्सलवाद के मामला हे। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- यहां विधान सभा सदस्य की बात हो रही है।

सभापति महोदय :- एक मिनट। पहले उनको अपनी बात तो कह लेने दीजिए। सामने में बहुत वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हैं और सुन रहे हैं। एक वरिष्ठ सदस्य अपनी पीड़ा बता रहे हैं इसलिए उनको व्यक्त करने दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पर्सनली S.P. साहब से बात की कि मुझे जंगल पट्टी में जाना है। मैं अपने क्षेत्र में दौरा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने डॉ. रमन सिंह जी से कहा कि आप मेरे क्षेत्र के वरिष्ठ हैं इसलिए मेरा ध्यानाकर्षित स्वीकार कर लीजिए, जिससे मैं अपनी बात तो रख लूं। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं। चूंकि वह बहुत सीनियर हैं इसलिए उनको ज्यादा बोलना उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यदि आपको मौका मिलेगा तो उनसे जरूर बोलियेगा। माननीय सभापति महोदय, आप मेरे वरिष्ठ हैं। आप हमेशा अच्छी बात करते हैं और मदद भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा। क्या मैं जंगल में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके कार्यक्रम अटेण्ड न कर पाऊं ?

सभापति महोदय :- ठीक है। आपने अपनी बात कह दी। मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री भोलाराम साहू :- सभापति महादेय, ये व्यक्तिगत उनकी ही बात नहीं है, पूरे विधायकों की समस्या है ।

सभापति महोदय :- आपने सदन में अपनी भावना व्यक्त कर दी । माननीय वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, वे सुन रहे हैं । वे निश्चित रूप से वे देखेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, आप आदेशित कर दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, जो इनकी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनको आज भी एक्स और वाई श्रेणी की सुरक्षा अभी भी उनके घरों में दी जा रही है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, हमारा एरिया नक्सल क्षेत्र नहीं होता तो हम नहीं बोलते ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय सभापति जी, अपने कार्यकाल का तो बताईए । मैं दो कार्यकाल तक मंत्री रहा हूं । मैंने आपके गृहमंत्री जी के पास जाकर निवेदन किया था । आपके गृहमंत्री का जवाब है कि मेरी नहीं चलती ।

सभापति महोदय :- मैं पहले भी कह रहा हूं कि भोलाराम जी, मैंने आपको भी अवसर दिया ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सदस्य उचित बात कह रहे हैं । मंत्री जी, बदले की भावना मत कीजिए, आप सहयोग कीजिए ।

सभापति महोदय :- सुनिए न । इसमें बहस की कोई जगह नहीं है । वह एक गंभीर मामले पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, आप भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं । शासन के संज्ञान में आपकी बात आ गई है । शासन इस संबंध में विचार कर निर्णय लेगा । माननीय मंत्री जी बैठे हैं । अब आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिए। अब अनुज शर्मा जी बोलेंगे । अब इस बात को समाप्त करिए । दोबारा अवसर आएगा। अभी गृह विभाग के बजट पर चर्चा होगी, उसमें बोल लीजिएगा ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, अमृत काल का यह छत्तीसगढ़ विजन 2047 और एक ऐसा बजट है, जब यह बजट यहां इस पवित्र सदन में रखा गया, उस वक्त ही यह स्पष्ट हो गया कि यह बजट छत्तीसगढ़ को किस ओर लेकर जाने वाला है । तकनीक को लेकर इस बजट की पहली शुरूआत होती है और जिस तरीके से बजट प्रस्तुत किया जाता है, वह वहीं पर एक इतिहास गढ़ देते हैं कि बजट को प्रस्तुत करने का एक यह भी तरीका होता है । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से बजट प्रस्तुत किया, इसमें यह किसान के अभिमान का बजट है, ये गरीब के सम्मान का बजट है, मजदूर का बजट है, युवा का बजट है, महिलाओं का बजट है, संस्कृति की पहचान का बजट है और परम्परा के गुमान का बजट है, विकास की रफ्तार का बजट है और शिक्षा के दान का बजट है । यह बजट जैसे ही इस सदन में रखा जा रहा था, उसी में टोका-टाकी हो रही है । यह इस बात के अंतर को बताता है कि सरकार छत्तीसगढ़ को किस राह पर लेकर जाना चाहती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में टॉप के देश में खड़ा हो, उस ओर ले जाने वाला बजट है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, महाराज जी, हीरो मन बर छत्तीसगढ़ फिल्म निगम के लिए एको रूपिया रखे हे का ? तहूं तो ऊंही ले चुनकर आए हवस । फिल्म निगम बस कुछू बजट नहीं हे, छत्तीसगढ़िया मन हीरो-हीरोईन नहीं बनय । मिथुन चक्रवती, श्री देवी छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाएं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, अभी तैं हीरों से बात नहीं करथस, अपन क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक चुनकर आए हे, ओकर से बात करथस । वो ह बजट में अपन बात रखथे । हीरो अपन बात नहीं रखथे, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि बजट में अपन बात रखथे ।

श्री रामकुमार यादव :- जब ओ ह चुनाव बर गे रिहीसे तो का केहे रिहीसे । मैं ए हीरो आवं, छत्तीसगढ़ के हीरो के रूप में देखथन । आज भी ओ ह मोर हीरो हे । ओ ह हीरो के रूप में बतावए कि बजट में फिल्म निगम बर का करे हे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- लेकिन अभी वह हीरो के पद में नहीं हे, एक विधायक के पद ला सुशोभित करथे, ओ ह ओखर बात करथे ।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, पहीली ओ ह हीरो रिहीसे । अभी भी हीरो के रोल हे, ओकर लिए का होए हे, वहू ला बतइहव ।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप उधर देखकर सीधे बात शुरू कर देते हैं, यह ठीक नहीं है । आप इधर देखकर बोलिए न ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी,

सुबह मगरूर को वह शाम भी कर देता है,
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है ।
शोहरते छीन कर गुमनाम भी कर देता है ।
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है,
शोहरते छीन कर गुमनाम भी कर देता है ।
वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो,
वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो,
वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति जी, यह बजट एक ऐसा बजट है, जो संतुलित है, सुगठित है, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को दिखा रहा है, जिसमें एक सशक्त राष्ट्र को बनाने में छत्तीसगढ़ एक सशक्त राज्य के रूप में अपना क्या योगदान देगा।

समय :
4:20 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति जी, यह एक ऐसा बजट है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लांग टर्म विजन है, उसे मजबूत बनाने वाला बजट है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर का उद्योग चलता था। अगर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई उद्योग फला-फूला, तो वह ट्रांसफर का उद्योग है। कहां किस अधिकारी को किस शर्त पर बैठाया जायेगा, उससे तय होता था।

एक माननीय सदस्य :- उसके लिए एक देवी के पास जाना पड़ता था।

श्री अनुज शर्मा :- अभी देवी अपनी सही जगह पर है। सभापति महोदय, यहां ट्रांसफर का उद्योग चलता था। पुलिस का मनोबल ऐसा था कि जयस्तम्भ चौक पर चाकूबाजी की घटना घट जाती थी। एक पार्किंग में एक महिला का बलात्कार हो गया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र के टेकारी में एक महिला की लाश मिलती है और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती है, उस समय ऐसा मनोबल था। यह बजट, पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला बजट है। (मेजों की थपथपाहट) जब आपरेशन में हमारे जवान जाते थे तो उनके पास उचित खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। मैं चाहता हूं कि इस बात का स्वागत इस पूरे सदन में होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) उन्हें रेडी टू ईट उपलब्ध कराने का फैसला, इस बजट में किया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, हमारे सदस्य साथी ने कहा कि यहां कहीं बलात्कार नहीं हो रहा है।

श्री अनुज शर्मा :- मैंने नहीं कहा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं एक बात बता देना चाहती हूं कि कल की ही घटना है। आपके भिलाई में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। (शेम-शेम की आवाजें)

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं इसके बाद बालोद जिले की बात करूंगी। वहां तीन-तीन बलात्कार हो चुके हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज, आप लोग बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, जो भी ऐसा करेगा, उसको सबक सिखा दिया जायेगा। कल व्ही.आई.पी. रोड में घटना हुई तो उनका सिर मुंडा कर जुलूस निकाल दिया गया, ऐसी हमारी सरकार है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये, आप लोग बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ऐसी बात नहीं है। आपके शासनकाल से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तब से लगातार घटनाएं हो रही हैं।

सभापति महोदय :- एक साथ दो लोग मत बोलिये। आप लोग बैठिये। निषाद जी एक साथ दो लोग मत बोलिये। आप तीनों का नाम बोलने वाली सूची में है, तब आप लोग बोलियेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, हत्या बलात्कार के बात हे। मोर विधानसभा क्षेत्र मा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले सामूहिक बलात्कार की घटना में उस पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। यह आपकी सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप लोगों का नाम है, जब आपका समय आयेगा, तब बोलियेगा न।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, मेरे विपक्ष के साथी बहुत छाती ठोक रहे हैं। बिलासपुर के तड़ीपार के साथ प्रदेश के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ एक सार्वजनिक फोटो छपती थी, तब ये क्यों चुप रहते थे ? मैं आपसे जवाब चाहता हूं।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, एक ठन हाना हे, ऐ कोलिहा हुंवा-हुंवा तब कोलिहा हुंवा-हुंवा। बोलन दे करा भाई।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ये आपत्तिजनक हे। हमन कोलिहा नइ हन महाराज, हमन शेर हन।

श्री अनुज शर्मा :- हाना हे, हाना हे।

श्री रामकुमार यादव :- मौका आही तो बता देबो। तुमन दो चार ज्यादा हो गय तो तुमन शेन नइ हा। कोलिहा कोन ला कहत हा ? कोलिहा आप हा।

श्री अनुज शर्मा :- हो गय ? माननीय सभापति जी, यह आपत्तिजनक है। मैं हाना बोले हव, कोई ला इंगित नइ करे हव। ओ हर इंगित करके बोलत हे, मैं चाहत हव कि आप अपन कोई व्यवस्था दे दव।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि ये कानून व्यवस्था के स्थिति रहिस हे। ये बजट मा पुलिस के मनोबल बढ़ाय के काम करे गय हे। ये बुलडोजर सरकार हे, जो भी ऐसे काम करने वाला असामाजिक तत्व होही, ओखर ऊपर कड़ा से कड़ा कार्यवाही करे जाही। आज भिलाई में 5 जगह बुलडोजर चले हे, मैं आप ला जानकारी देना चाहत हव। (मेजों की थपथपाहट) भिलाई में 5 जगह बुलडोजर चले हे । वोखर बर दृढ़ इच्छाशक्ति के जरूरत होथे । ये विष्णु देव सरकार हरै, विषणु देव साय के सरकार ए, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करने वाला सरकार ए, आपसे कहना चाहथंव, पुलिस वाले मन बर पहली बार, छुट्टी के व्यवस्था करे गे हे । ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हरै, वोखर साथ सरकार के तरफ से मानवीय दृष्टिकोण से जो व्यवहार करे जाथे, वोहा बहुत महत्वपूर्ण बात हरै सभापति महोदय । माननीय सभापति जी, मैं आपसे एक बात अऊ कैइहंव कि कहाई ले कराई ठीक, कथनी ले करनी ठीक पे आधारित ये बजट हरै । हमन कहने वाला नई, करने वाला सरकार अन । (मेजों की थपथपाहट) 266 करोड़ के तकनीक के इस्तेमाल बर विजन लेके ए सरकार अऊ हमर माननीय वित्त

मंत्री जी जो बजट रखे हे, ये अतका रूपया तकनीकी विकास बर ए, एहा छत्तीसगढ़ ला अग्रणी राज्य बनायके काम करही, बहुत आगे तक ले के जाही, एहा बहुत महत्वपूर्ण फैसला हरै ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, मैं सदन में 20 साल से बजट देखा हूँ, 21 वां बजट में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अंग्रेजी, हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, नेल्शन मंडेला जैसे बड़े-बड़े लोगों का जिक्र पहली बार एक बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) आप उसके विजन को पढ़िये, समझिये । विरोध के लिये विरोध मत कीजिए । अभी वख्त दीजिए । यह पहला बजट है । अगर इसका इम्पलीमेंट ठीक से नहीं होगा तो अगले बजट में क्रिटिसाईज करियेगा । अभी से संगीता जी ने दो ही महीना सरकार का नहीं हुआ है, कोई कहता है कि गिट्टी उखड़कर फेंकाने लगा, कोई बोल रहा है कि रोड का बोल्डर फिंकाने लगा, कोई बोल रहा है कि अत्याचार हो गया, कोई कहता है कि इसको बिहार बना दिया, कोई कहता है कि उत्तरप्रदेश बना दिया है । कहीं कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु देव की सरकार है....। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, विष्णु देव की सरकार है तो लक्ष्मी में कमी क्यों कर दिये ? लक्ष्मी जी को कम कर दिये हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन एक महीना में काट के पका देहव । (व्यवधान) पांच साल में जो पेड़ नई कटे होही, वोला तुमन 1 महीना में काट के पका देहव । उतका उपई तुमन करे हव ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, बजट में लक्ष्मी की वर्षा नहीं है ।

सभापति महोदय :- आपको अवसर दिया जायेगा । आप बाद में बोलियेगा ना । शर्मा जी, आगे बढ़िये । (व्यवधान) रामकुमार जी, प्लीज बैठिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 18 लाख आवास की घोषणा किये हैं । (व्यवधान) हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के बारे में तो सोचिये ।

श्री कवासी लखमा :- पेड़ की बात कर रहे थे, पेड़ कट रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- लखमा दादी, पेड़ इसलिये कट रहा है कि उसको काटने की अनुमति आपकी सरकार ने दे दी थी । (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह गलत बात है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये । प्लीज बैठिये । लखमा जी बैठिये । रामकुमार जी बैठिये । प्लीज बैठिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पेड़ ला काटेव तुमन, नाम धरैव हमर । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी प्लीज बैठिये ।

श्री संगीता सिन्हा :- स्मृति ईरानी जी का बयान आया था, लेकिन इस बार वह चिल्लाना बंद कर दिये । वह भी बयान दे ना ?

सभापति महोदय :- संगीता जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इस सदन में खुद उस अशासकीय संकल्प को लाया था। एक घण्टे का भाषण दिया था, उसमें सारे तथ्य रिकार्डेड हैं, मैंने यह कहा था कि दिल्ली की सरकार को अनुमति निरस्त करके भेजने से पहले सारे आदेश, क्लियरेंस, फारेस्ट क्लियरेंस, इन्वायर्नमेंट क्लियरेंस, जो आपकी सरकार ने....(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, सरकार इनकी आ गई है...(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमारी सरकार में एक डाल भी नहीं कटा था, पेड़ कटने की बात तो दूर है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जंगल को बचाना, आदिवासियों की रक्षा करना..(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अब दिल्ली भेज दो । अब उसको दिल्ली भेज दीजिए।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये । (व्यवधान) संगीता जी, बार-बार मत खड़ा हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने तो अनुमति पहले से ही दे दिया था । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह आपका अधिकार है । आप सरकार चला रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 3 दिसम्बर को सरकार को बहुमत मिला । 13 दिसम्बर को श्री विष्णु देव साय जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली । उसके दो दिन पहले पेड़ काटने का आदेश दिया गया । (व्यवधान) वह शक्ति कौन है जो मुख्यमंत्री बनने के दो दिन पहले पेड़ काटने का आदेश दिया गया ? उसका जवाब आपके पास है ?

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई। धर्मजीत जी, प्लीज बैठिये।

एक माननीय सदस्य :- रामकुमार जी, आज तो बजट की बात हो रही है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिये। उनको बोलने दीजिये। आपकी बात आ गयी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यदि यह सरकार चाहती है तो रोक आदिवासियों का दहन रोक सकती है, आदिवासियों की रक्षा कर सकती है। आप चाहे तो (व्यवधान) रूकवाने का आदेश कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पूरा सक्ति जिला, जांजगीर जिला, सब ओ मा बर्बाद हो जाही। किसान मन नइ रहे।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप अभी आदेश कर दीजिये की नहीं काटा जायेगा। आप आदेश करवाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप हमारे वित्त मंत्री जी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं और कम से कम छत्तीसगढ़ में यह दूसरे व्यक्ति हैं, जो अपनी आई.ए.एस. की

आलीशान जिंदगी को छोड़कर यहां पर छत्तीसगढ़ के गरीबों की सेवा के लिये आये हैं। उनके दिल में सब्र है, आप उस सब्र को समझने की कोशिक करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी देर नहीं हुई है। आप आदेश करवा सकते हैं कि जंगल की कटाई को रोक दिया जाये।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई। अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा :-

मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं,
मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, (मेजों की थपथपाहट)
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत,
यह एक चराग कई आंधियों पर भारी है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्लीज आप बैठिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जिस बजट की बात हो रही थी। पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पहले यह 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होती थी, यह वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने जो वादा किया था कि गरीबों को रहने के लिये पक्का मकान मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले गरीबों को मिलने वाले पक्के आवास के कागजात पर दस्तखत करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) इस वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निभाया और सबसे पहले उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये। वह आज तक अपने घर का गृह प्रवेश नहीं किये हैं। यह ऐसी वादा निभाने वाली सरकार है। यह कमिटमेंट इस बजट में दिखाई दे रहा है। कृषि की उन्नति के लिये और पिछले दिनों केंद्र की नल जल योजना की जो दुर्गति हुई, उससे उबरने के लिये और हर घर तक पानी पहुंचे, इस बात की व्यवस्था करते हुए नल जल योजना के लिये 14 हजार 500 करोड़ प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर घर में नल से पानी मिले। तेंदू पत्ता के लिये प्रति मानक बोरा 5500 रूपये देने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी बात, ऐसे मजदूर जो किसानी का काम करते थे लेकिन भूमिहीन होते थे, उनके लिये 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, यह हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटमेंट था, जिसे हमने इस बजट में निभाया है।

माननीय सभापति महोदय, पी.एस.सी. जैसे मामले में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी सी.बी.आई. की जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। उसमें जो भी दोषी होंगे, उन्हें जहां होना चाहिए, वहां पहुंचाया जायेगा, यह इस सरकार का संकल्प है। यह बजट इस बात की गवाही है कि हमने अपने संकल्प को निभाया है। यदि आप कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो विगत वर्ष की तुलना में कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों के हितों का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ध्यान रखा गया है। मैंने कहा था कि यह किसानों का बजट है। यदि आप देखें तो 05 करोड़ रूपये पांचों शक्तिपीठ के लिये प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की देवी-देवताओं से है। पांचों शक्तिपीठों को जोड़ने का काम और उसे सर्किट के रूप में इस्टेब्लिस्ड करने का काम इस सरकार की मंशा है। यह छत्तीसगढ़ आस्था की भूमि है। इस बजट में ऐसी भूमि के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।

सभापति महोदय, स्टेट केपिटल रीजन के बारे में बोलना चाहता हूं। आज आप देखेंगे कि नवा रायपुर से लेकर भिलाई-दुर्ग तक, सबकुछ एक जैसा महसूस होता है। इस क्षेत्र के लिये एक साथ योजना बनाने की जरूरत थी, जिस बात को हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने अनुभव किया और उसके हिसाब से यह योजना बनाई गई है।

सभापति महोदय, इस बजट में खाद्यान्न के लिये हो या फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिये, सभी के लिये प्रावधान किया गया । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 01 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार ने जिन युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम किया था। यह सरकार उस युवा को सम्मान देने का काम करेगी, इस बजट के माध्यम से होगा, जिसमें प्रावधान किया गया है। प्रदेश के युवाओं को सम्मानित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे देश की न्याय व्यवस्था में जो जिम्मेदारी है, संख्या है उसको ठीक करने के लिए हमारे प्रदेश में 40 व्यवहार न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है ताकि लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया में तीव्रता आए, उसे गति मिल सके।

माननीय सभापति महोदय,यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट या वॉटर ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। यह परिसर कहीं कहीं न युवाओं को रास्ता दिखाने वाला होगा। यह युवाओं को प्रेरित करने वाला परिसर होगा। हमारे वित्त मंत्री जी खुद आई.ए.एस. रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपनी मेहनत से एक सामान्य घर, एक छोटे से परिवार से आकर जीवन में किन ऊंचाईयों को हासिल किया जा सकता। ऐसे एक नहीं, हजारों प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा कि वह नालंदा परिसर की तर्ज पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन में जाकर पढ़ाई कर सकें और आगे अपना कैरियर बना सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं Environment की बात करूंगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा अंतर्गत वाहनों के क्रय एवं संचालन हेतु कुल 103 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश समय के साथ चलने वाला है इसलिए इस बजट में इन बारिक बातों का भी प्रावधान किया गया और

अब Electric Vehicles का समय आ गया है। अब Electric Vehicle ही भविष्य हैं। यह बात दिखाने वाला बजट है।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं अब पर्यटन एवं संस्कृति में संस्कृति मंत्रालय की बात करूं। संस्कृति मंत्रालय में जो कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार होता था मेरे लिए उसे बताना, बहुत दु:खद है। किसी कलाकार को कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कह देता था कि यह संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है, वह कलाकार व्यथित होकर, स्टेज शो करता था। "तुम्हारे बाप का नहीं है" के शीर्षक के साथ वह नाटक करता था। वह इतना व्यथित था। हमारे कलाकार ऐसे दुर्व्यव्यवहार के शिकार हुए हैं।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, आपको 20 मिनट हो गए। अब आप समाप्त करें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उस समय कलाकारों के साथ ऐसा व्यवहार होता था। पिछले 5 सालों में राजभाषा आयोग, फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका। यहां फिल्म विकास नीति बनाई गई, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आपसे केवल दो मिनट और लूंगा। जबकि इस सरकार द्वारा इस बजट में गोंडी भाषा के विकास, बचाने हेतु हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्ट वेयर का निर्माण करने के लिए प्रावधान किया गया है। अभी कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके आदेश का पालन करते हुए, मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- भईया, महतारी वंदन योजना ला घला बता दूहू।

श्री अनुज शर्मा :- दीदी, मैं बतात हौं। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा :-

"एक राम दशरथ घर डोले।

एक राम घट-घट में बोले।

एक राम सब जगत से न्याया।

और एक राम जगत से प्यारा।" अइसे सब राम के मानने वाला मन बर रामलला दर्शन योजना शुरू करे हे। उहू मा लेके जाबो अउ आप बोलत रहेव। मैं इस बजट के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी, हमारी सरकार जो चाहती है उनको दो पंक्तियां समर्पित करता हूँ :-

"चल मेरे साथ ही चल

पीछे मत देख न शामिल हो, गुनाहगारों में।।

सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में

बात बनती है अगर दिल में इरादे हों अटल

चल मेरे साथ ही चल।"

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें। धन्यवाद्।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, केवल और केवल हम विपक्ष हैं इसलिए विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, महोदय ऐसा नहीं है। हम विरोध प्रदेश के उन आदिवासी भाईयों के हित में करना चाहते हैं । नि:सदेश वित्त मंत्री जी जब राजनीति में आये तो हमें भी खुशी थी कि एक विद्वान आदमी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इसका लाभ कभी न कभी छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, किसानों को, विशेषकर युवा शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। अब दल चुनना तो उनका अधिकार है, उनके राजनीति में प्रवेश से मुझे जो खुशी हुई थी, थोडा सा दल प्रवेश में कहीं न कहीं.. चलिये अब यह उनका व्यक्तिगत मामला है। दूसरा अवसर प्रदेश के युवाओं को मिला कि इतने विद्वान व्यक्ति वित्त मंत्री बने हैं। यह सही है कि जब बहुत ज्यादा आई.ए.एस. जैसे पढ़े-लिखे लोग राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। कुछ लोगों को मानना यह है कि आज की राजनीति उतनी अच्छी नहीं है कि अच्छे लोग नहीं आना चाहते, उस चीज को भी आप राजनीति में प्रवेश करके छत्तीसगढ़ में विराम दिये हैं। लेकिन जब आप राजनीति में प्रवेश किये और वित्त मंत्री बने तो मुझे ऐसा लगा कि आप अपने मन से बजट भाषण नहीं बनाये हैं। यदि आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती, पूर्ण अधिकार दे दिया जाता कि वित्त मंत्री जी आप अपने हिसाब से 2024-25 का बजट प्रस्तुत कीजिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट का स्वरूप कुछ अलग होता।

श्री रामकुमार यादव :- कका, तैहां बहुत अच्छा बोलत हस। सभापति जी, हमर वित्त मंत्री ला देख के छत्तीसगढ़ के जनता मन, युवा मन भयभीत होगे हे। ओमन के दिमाग घूम गेहे। कैसे? अजय चन्द्राकर कस नेता बनी या चौधरी कस कलेक्टर बने, दोनों मा ओमन भ्रमित हो गये हे। कलेक्टर ला बने पड़ही या नेतागिरी करही।

सभापति महोदय :- आपकी बारी आयेगी तो उसमें उल्लेख करियेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी, इस बजट में सबसे ज्यादा मोदी जी की गारंटी की बात आई है। आज बजट प्रस्तुत किये हैं। मुझे इसलिए संदेह हो रहा है कि मोदी स्वयं अपने बजट में, अपनी सरकार में 10 साल में सम्मिलित किये गये वादा को पूरा नहीं किये हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- मामा, आप कम से कम इतना असत्य मत बोलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसीलिए ही थोड़ा सा इस बजट में... बजट तो आप अच्छा प्रस्तुत किये हैं..।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप मान रहे हैं न ?

श्री अनुज शर्मा :- आप मान गये कि अच्छा बजट प्रस्तुत किये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, मैं आगे पढ रहा हूं न। चलिये, मैं उसमें भी आ जाता हूं। अगर आप इस बजट में जितनी बातें बोले हैं और जितनी चीजों को सम्मिलित किये हैं, उसको आप पूर्णत: स्वीकृति प्रदान करेंगे या उस क्षेत्र में कार्य हो जायेगा तो हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन शर्त है कि बजट में दिये गये कार्य पूरे होने चाहिए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तारीफ करेंगे।

श्री मोतीलाल साहू :- आप लोग विपक्ष में बैठे रहिये, आपको हमेशा वहीं रहना है।.. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मोतीलाल साहू जी, बैठिये। प्लीज, आप लोग बैठिये

श्री अनुज शर्मा :- द्वारिकाधीश यादव जी, प्लीज एक लाईन सुन लीजिए। "सच को तमीज ही नहीं बात करने की, असत्य देखो कितना मीठा बोलता है।"

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप जो बात बोल रहे हैं न, वह बात मेरे को बोलना था। मेरी बात कहकर आपने मेरे समय को बचा दिया, वही उसमें शामिल है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी की सोच तो अच्छी है, परंतु कहीं अदृश्य शक्ति उनको जकड़ न ले, हमको यह चिंता है।

श्री रामकुमार यादव :- का हे न हमन ओ डहर से आ गये हन, तुमन 9 नंबर की जगह, ऐला 10 नंबर दे दो, 10 नंबर ले 11 नंबर देवा, तभी छत्तीसगढ़ के नेता डरात हे।

सभापति महोदय :- यादव जी, कृपया बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बहुत सरल, अच्छे अनुभवी व्यक्ति आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बनें, उनके काम की शुरूआत जंगल को बचाने से होनी थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि ऐसी कौन सी शक्ति वन विभाग के अधिकारी को प्राप्त है जो वन मंत्री को पता नहीं है और मुख्यमंत्री की शपथ के पहले हसदेव के जंगल कटने लग गये। सरकार विवश क्यों है ? सरकार को पहली कार्रवाई यह करनी चाहिए कि उस वन विभाग के जिस अधिकारी ने जंगल काटने का आर्डर दिया, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ठीक है कि केन्द्र की सरकार ने खदान एलाट किया है लेकिन वन विभाग की अनुमति राज्य सरकार चाहे तो निरस्त भी कर सकती है और सारी औपचारिकता पूर्ण होने तक उनको रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी की है तो आदिवासी भाईयों का है। जिस प्रदेश के मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है कि जैसे-जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी आरक्षण उनको स्वमेव प्राप्त होगा। लेकिन आज पुरानी जनगणना के आधार पर आदिवासी वर्ग को केवल 32 प्रतिशत आरक्षण कहा जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की यदि 36 प्रतिशत भी जनसंख्या बढ़ी होगी तो इस बजट में पिछड़ा वर्ग की, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति की जनगणना की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका

बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार क्यों आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नहीं करवाना चाहती? यह सरकार आदिवासियों के आरक्षण से क्यों अन्याय कर रही है? माननीय सभापति महोदय, जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है तो उस संविधान से उनको पीछे के रास्ता से क्यों बाहर किया जा रहा है? एक दिल्ली की सरकार है, जो आरक्षण को खतम करने के लिए सब सरकारी संपत्तियों को एक उद्योगपति को दिया जा रहा है ताकि आरक्षण का लाभ उनको न मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाईयों की जनगणना होनी चाहिए और जनगणना होगा तो निश्चित रूप से आदिवासी भाईयों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमारे विद्वान साथी और हमारे बहुत ही विद्वान भांचा जी हैं, वह बोल रहे थे कि पिछला सरकार यदि एक काम भी किया होगा तो बता दें। मैं बताना चाहता हूं और मैं केवल बोल ही नहीं रहा हूं, उसके परिणाम भी हुए हैं और रिकॉर्ड में भी है। छत्तीसगढ़ में बरसों से किसान कर्ज से दबे हुए थे। खेती घाटे के सौदे की स्थिति में आ गई थी। लोग खेती नहीं करना चाह रहे थे और किसान जमीन बेच रहे थे। दो घंटे के अंदर 9,500 करोड़ रूपये की कर्जामाफी की घोषणा की गई। पहली हस्ताक्षर कर्जा माफी, दूसरा 1870 या 1872 रूपये, मैं दो रूपये कम या ज्यादा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भूल रहा हूं। धान बिक रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हमने 2500 रूपये के दाम से धान खरीदा। बात केवल किसानों के हित में यहीं नहीं रूकी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में या देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो संपत्ति सरकार खरीद चुकी है, किसान बेच चुके हैं, उसकी भी दाम 1872 वाले दाम को 2500 रूपये की अंतर की राशि देने का काम कोई सरकार ने किया, तो हमारी सरकार के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। मैं उनको आज भी धन्यवाद देता हूं और इस काम के लिए विपक्षी दल के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। चूंकि वह भी किसान हैं और किसान के हित में काम हुआ है तो आपको भी इस अवसर में धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है कि बजट में अगर जितनी बातें बोली गईं, लिखी गईं, बताई गई हैं और छत्तीसगढ़ के जितने विभाग में सम्मिलित किए गए हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- आप शराबबंदी के बारे में भी बता दीजिए कि कब शराबबंदी होगी?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन तो अगरबत्ती जलात हौ। तुमन तो भट्ठी मा आथे, तेखर स्वागत करत हौ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- शराबबंदी बंद कर दीजिए।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से वित्तमंत्री जी के द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने की व्यवस्था किया गया है और किसी भी सरकार और राज्य की जो पूंजीगत आभूषण होती है। सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाती है तो निश्चित रूप से वह प्रदेश की आभूषण होती है।

अगर वास्तव में जितनी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, अब चूंकि मैं भी अभी दूसरी बार ही आया हूं तो पूरा अध्ययन करने के बाद भी नहीं समझ पाया हूं । मैं महसूस कर रहा हूं कि बढ़ जाये तो प्रदेश के हित में अच्छा है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि बढ़ना भी चाहिए लेकिन कैसे बढ़ेगा ? चूंकि बजट भाषण विस्तृत रहता है उस दिन वित्त मंत्री महोदय को भी यह नहीं बोला जा सकता है कि आपने नहीं बताया लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप बतायेंगे कि इस पूंजीगत व्यय को इतना बढ़ाने में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे यह बढ़ेगा । माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की एक और बात बोल देता हूं ।

सभापति महोदय :- चलिये, 11 मिनट हो गये हैं । आप बोलिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली सरकार में संसदीय सचिव था । मैं कुछ बोल नहीं पाया, सुनते रहता था । आप लोग बोलते थे, पहली बार तो बोलने का मौका मिला है । (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- इन लोगों ने मना करके रखा था कि मत बोलो ।

सभापति महोदय :- चलिये, बोलिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, विद्वान सदस्य जो हैं । उन्होंने इस बात को बोला कि छत्तीसगढ़ के हित में एक काम हुआ होगा तो बता दें, वह विद्वान सदस्य मेरे भांचा जी ही हैं । एक तो किसान के धान का दाम और कर्जा माफी यह दो ही बताया है । मैं तीसरा और बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पहले आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिये, मैं सहमत हूं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिरी 15 सालों में 1 लाख-डेढ़ लाख रूपये, 3 लाख-5 लाख रूपये जमीन का दाम होता था और जब हमारी सरकार बनी तो धान का रेट बढ़ा, कर्जा माफ हुआ तो 10 एकड़ के किसान को अगर 2 लाख-5 लाख जो भी नगदी इंकम हुई होगी लेकिन पूंजी में अगर उसकी पूंजी 50 लाख रूपये की थी तो वह पूंजी 50 लाख रूपये बढ़ी । हमने किसानों की पूंजी बढ़ायी है । हमारे वित्तमंत्री जी बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन हमने 5 साल में परिणाम लाया है, उस नीति से किसानों की जमीन का दाम बढ़ा । पहले केवल सड़क किनारे की जमीन की पूंजी और उसकी कीमत बढ़ रही थी । छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक-साथ जिस जमीन में चलने के लिये रास्ता नहीं है, उस जमीन का भी दाम चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति का परिणाम रहा कि 50 लाख रूपये, 1 करोड़ रूपये की भी पूंजी बढ़ी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात । निश्चित रूप से हर सरकार की नीति होती है लेकिन नीयत वैसी ही होनी चाहिए जैसे नीति में हम बोलते हैं । नीयत साफ होनी चाहिए । मैं माननीय वित्त मंत्री जी की उस बात का समर्थन करता हूं कि किसी भी प्रदेश को बर्बाद करना है तो शिक्षा की नीति या शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दो यह सही है लेकिन यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15

सालों में इस छत्तीसगढ़ राज्य को पूर्ववर्ती सरकार ने पीछे किया उसी का परिणाम है कि आप इन 15 सालों के परीक्षा परिणाम को भी देख सकते हैं । हमारी सरकार द्वारा हम पीछे हों ऐसी कोई नीति लागू नहीं की गयी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, परीक्षा का परिणाम आ चुका है और जो प्रथम आये थे वह जेल में हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं । मैं उस परिणाम को बोल रहा हूं कि कितने लोगों ने इन 15 सालों में हमारे वित्तमंत्री जी जैसी सफलता हासिल की, मैं उस ओर ध्यानाकर्षित कराना चाह रहा था। माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें रासायनिक खाद, गुणवत्ता में भारी व्यापक कालाबाजारी होती है । इसका नियंत्रण भी आवश्यक है । निश्चित रूप से रासायनिक खाद में जो भ्रष्टाचार ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें, 15 मिनट हो गये हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में 9 परसेंट बजट प्रावधान कम किया गया है । मैं इस पर एक मिनट बोलना चाहूंगा कि ऊर्जा में आज केवल उद्योगपति ही शामिल नहीं हैं, किसान भी शामिल हैं । किसान इससे परेशान होंगे, किसान ठगे जायेंगे क्योंकि अभी भी बोर का स्थायी कनेक्शन लंबित है और कम कर देने से नया कनेक्शन तो उनको सरकार दे नहीं पायेगी। किसान सड़क में घूमेंगे और अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से..।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2024-25 के बजट पर मैं अपना पक्ष रखने के लिए खड़ी हुई हूं और उसका भरपूर समर्थन करती हूं। आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा अमृतकाल का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित ही कहीं न कहीं वर्ष 2047 का जो विजन भारत कैसा होना चाहिए, विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसकी एक आधारशिला के रूप में हमें दिखाई देता है। आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट में ज्ञान भी है और नवनिर्माण भी है और हर नारी का सम्मान भी है। गारंटी के इस बजट में कर्म की नींव भी है और सपनों का आसमान भी है। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो हमारे वित्त मंत्री को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और इस सदन को भी बधाई इसलिए देना चाहती हूं कि पहली बार इस सदन में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि पेपर का यूज़ जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा और दूसरा जो हम digitalization की बात

करते हैं तो निश्चित ही पेपरलेस बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सदन में प्रस्तुति होनी चाहिए, जितना कम से कम पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, शायद उतना अच्छा होगा। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो बजट था, मुझे पहली बार देखने को मिला है, जब बजट के बाद में क्षेत्र के दौरे में गये, कल-परसों क्षेत्र में जब घूमे हैं तो पहली बार मैंने महिलाओं से चर्चा सुनी कि हमने टी.वी. पर बजट देखा है। मुझे लगता है और शायद जहां तक मेरी जानकारी है, पहली बार ऐसा अवसर आया है कि महिलाएं बजट को सुनी हैं और सुनने के बाद उन्होंने बजट को समझा भी है। (मेजों की थपथपाहट) जब मैंने उनसे पूछा कि आपको बजट में क्या समझ में आया? उन्हें यह जरूर पता थी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका निश्चित ही 15 साल का कार्यकाल था, तो महिलाएं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्योंकि महिलाओं को घर का मुखिया बनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला था। राशन कार्ड की मुखिया में महिला का नाम था। तो कहीं न कहीं उनको विश्वास था कि आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार में निश्चित ही महिलाओं को बहुत ही अच्छा कुछ मिलने वाला है जो महतारी वंदन योजना के रूप में हमें देखने को मिला है। 3 करोड़ की जो हम आबादी मानते हैं, उसमें 3 हजार करोड़ रूपये सिर्फ महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के लिए रखा गया है तो निश्चित ही यह भा.ज.पा. की सरकार में वित्त मंत्री जी के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। माननीय सभापति महोदय, चूंकि महिला हूं, इसलिए महिलाओं की ही बात पहले कहूंगा। जो महतारी सदन की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि जो विपक्ष में हमारी बहनें है, वे और सभी सदस्यगण इससे सहमत होंगी। जब हम क्षेत्र में जाते थे तो हमेशा ही ये समस्याएं आती थीं कि जो 30 लाख के आसपास जो स्व-सहायता समूह की जो बहनें हैं, उनकी बैठकों की व्यवस्था में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। कभी किराये का कहीं भवन लेकर, कहीं व्यवस्था करके उन्हें भवन की तैयारी करनी पड़ती थी। कहीं न कहीं महतारी सदन की महिला, जो हर पंचायत में बात आ रही है तो कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारा यह मानना है कि जब-जब कमल खिला है, तब-तब नारियों का सम्मान हुआ है और जिस GYAN की बात हमारे वित्त मंत्री कर रहे थे, G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से जो नारी है निश्चित ही इस बजट से सब संतुष्ट हैं। और अभी हमारे भाई शायद यहां पर हैं नहीं, उन्होंने GYAN की परिभाषा अपने तरीके से दी है तो मैं थोड़ा सा GYAN की परिभाषा को उन्हीं के शब्दों में जरूर समझाना चाहूंगी। G से होता है जो गरीबों का उन्होंने 16 लाख आवास छिना है, वह उनके लिए G का मतलब था कि गरीबों का आवास छिनना। दूसरा, जो उन्होंने Y की परिभाषा दी थी, युवाओं के साथ पी.एस.सी. में जो छल हुआ था, जो घोटाला हुआ था तो कहीं न कहीं उनके लिए Y

का मतलब है जो युवाओं के साथ घोटाला हुआ है। कहीं न कहीं A से अगर अन्नदाता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं तो जो 2 साल बकाया बोनस के बाद सरकार बनाने के पहले उन्होंने अपने संकल्प-पत्र में कही थी, कहीं न कहीं अन्नदाताओं के साथ A की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ छलावा है। अगर मैं N की बात करती हूं तो N विषय है-नारी। N से नारी शुरूआत होती है। महिला के नाम की शुरूआत होती है तो कहीं न कहीं यह विषय बहुत ही गंभीर है और मुझे लगता है कि बजट में जो मैंने प्रस्तुत किया था, उसका विषय प्रारूप बहुत अलग था, लेकिन कुछ विषय मुझे यहां पर लगता है कि इस सदन में जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वह अतिमहत्वपूर्ण है। कुछ विषयों पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। उसके बाद बजट के विषय पर और जो कुछ बिंदु हैं, वह मैं रखना चाहूंगी। आदरणीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मेरी बहनें अभी पक्ष-विपक्ष में होना एक अलग बात है, लेकिन जहां बहनों की सेफ्टी की बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो महिला होने के नाते फिर हम किसी भी पार्टी की हों, किसी भी राज्य में निवास करती हों । मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में महिलाओं के सुर, महिलाओं की बोली एक ही होनी चाहिए । हमारी बहनों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, मैं सदन में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, दिसम्बर 2020 में उनका वक्तव्य आया था कि महिलाएं या लड़कियां पहले आपसी संबंध बनाती है, उसके बाद उसको रेप का नाम देती हैं । सभापति महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है । मैं इसलिए बोलना चाह रही हूं कि एक महिला होने के नाते हम उस महिला की दृष्टि से सोचें जिसके साथ यह केस हुआ है । मुझे लगता है कि इन विषयों पर वाद-विवाद करने के बजाय, उसका रास्ता निकालने पर चर्चा करनी चाहिए, फिर चाहे आप पक्ष में हों या विपक्ष में । सभापति महोदय, मैं एक विषय और लेना चाहूंगी, लगातार महिलाओं की बात आ रही है, लगातार आदिवासी शब्द का जिक्र हो रहा है, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है । मैं आपको अपने ही क्षेत्र की एक घटना याद दिलाना चाहूंगी । आदिवासी महिला रात में 11 बजे अल्पसंख्यक समाज के सरपंच के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकाल में ही उसको बीच सभा में घसीटकर लाया गया था, जो मेरे गांव के पास की घटना है, मैं जहां निवास करती हूं उसके दो गांव के बाद के गांव की घटना है । सिर्फ इसलिए घसीटकर लाया गया क्योंकि उसने आपने गांव के बीच में नंदी की मूर्ति की स्थापना की बात की गौठान के बीच में । महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते उस समय मेरा दायित्व था, हमने थाने का घेराव किया उस समय आदिवासी भाई बहन भी मेरे साथ थे । वहां ए.एस.पी. एक महिला थी । जैसे ही हम थाने के अंदर पहुंचे, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, आदिवासी महिला की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, वहां पदस्थ ए.एस.पी. की रिकार्डिंग इनके तथाकथित मंत्री ने करवाया और एक दिन के अंदर न सिर्फ आदिवासी महिला को सामाजिक प्रताड़ना के तहत न सिर्फ उनके अध्यक्ष को प्रताड़ित किया गया । बल्कि ए.एस.पी. का ट्रांसफर दो घंटे के अंदर कराया गया । उसके बाद मेरे विषयों की जांच की गई कि जिला पंचायत सदस्य एक महिला है इनके विषयों की जांच कराई जाए कि

इनके विरूद्ध किस तरह से एफ.आई.आर. हो सकता है । मुझे लगता है कि भले ही आप विपक्ष में हों, लेकिन जहां महिलाओं की बात आती है। सदन हो या सदन के बाहर हो, हमें आवाज उठानी चाहिए बजाय यह देखे कि हम किस पार्टी से बिलांग करते हैं। सभापति महोदय, मैं तुलना नहीं करना चाहती लेकिन पिछले पांच सालों में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए, चाहे मैं जशपुर की बात करूं, चाहे बिलासपुर की बात करूं, चाहे एस.पी. कार्यालय की पार्किंग में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की जो घटना हुई थी उसकी बात करूं । पिछले पांच सालों में इस तरह के केस बहुत बढ़े हैं । केस बढ़े हैं लेकिन चिंता का विषय यह था कि उस समय केस को खींचा जाता था, कोई निर्णय नहीं आता था । लगातार गुहार लगाते रहते थे, लगातार मेरे पास भी रात को 11 बजे फोन आता था कि मुझे घर से निकाला गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है । इसलिए सदन में इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना जरूरी था क्योंकि विषय वाद-विवाद का नहीं है, महिला के सम्मन का है । मुझे लगता है कि यह जो बजट आया है इसमें महिलाओं के लिए पांच थानों की, पांच सेल की स्थापना की गई है, जो सुदूर वनांचल क्षेत्र हैं वहां महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय लिया गया क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आते हैं । मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं उसमें करीब 70 बूथ ऐसे हैं जो घोर आदिवासी क्षेत्र हैं, बैगा आदिवासी क्षेत्र हैं । मुझे पता है आज भी वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं । वहां से बच्चियों की तस्करी भी की जाती थी । पिछले पांच वर्षों में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन्हें दबा दिया गया लेकिन जिनका रिकॉर्ड हमारे पास आज भी मौजूद है तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी पहल है कि सुदूर वनांचल में जो महिलाएं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं । कम से कम उनके लिए महिला थाने की, महिला सेल की स्थापना की गई ताकि मानव तस्करी रूक पाए । मुझे लगता है कि इससे अच्छा महिला सशक्तिकरण का बजट इस विषय पर कुछ और नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्रीराम लला हम सबके लिए बहुत आदरणीय हैं और अद्भुत संयोग है कि आज छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । मैं बहुत स्वागत् करना चाहूंगी, हमारी संगीता दीदी, आदरणीय सदस्य ने कहा था कि हम भी दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं । निश्चित ही अयोध्या दर्शन के लिए भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है । महोदय, हम इसमें पक्ष-विपक्ष नहीं देखेंगे (मेजो की थपथपाहट) । हमारी बहन ने कहा, हालांकि उनका विषय थोड़ा बदल गया था । उस समय वे यह नहीं समझ पाईं कि उन्होंने धार्मिक रूप से कहा है । लेकिन उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि कांग्रेस के कार्यकाल में हम जनप्रतिनिधि होने के बाद भी एक नारियल फोड़ने के लिए मजबूर थे लेकिन हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पक्षपात करने की नहीं है इसलिए आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत निमंत्रण है कि रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर एक साथ अयोध्या चलेंगे । महोदय, इसके अलावा एक और अच्छा विषय यह है कि नालंदा लायब्रेरी की तर्ज पर 22 नई लायब्रेरियों की स्थापना होना है । कहीं न कहीं चाहे हमारे मोदी जी

की बात करें जिनका अभी थोड़ी देर पहले उपहास उड़ाया जा रहा था कि कभी वे चाय बेचने वाले बन जाते हैं, कभी वे और कुछ बन जाते हैं । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, जो जिस परिस्थिति से निकलता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिस परिस्थिति से आए हैं, चाहे उनके पिता ने स्टेशन में चाय बेचा हो, चाहे उनकी माता ने घरों में जाकर बर्तन धोया हो, वे जिस बैग्राउंड से आए हैं, इसी का नतीजा है कि आज अंतिम व्यक्ति तक वे चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने सारे विषयों को उसमें समाहित किया है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कोचिंग की व्यवस्था की गयी है, वह बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। बजट में बहुत सारे विषय हैं, जिन पर काफी सारे लोगों ने प्रकाश डाला है। मुझे बहुत खुशी है, चूंकि हम नये प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और इस महत्वपूर्ण बजट में जिसे हम अमृतकाल का बजट मानते हैं, हमें इस बजट को सुनने का अवसर मिला है। मैं हमारे वित्त मंत्री जी का निश्चित ही खुले मन से तारीफ करना चाहूंगी जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों में, इतने सरल शब्दों में और आत्मविश्वास के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है। वह भी उसके साथ खाली खजाना मिला था। मुझे याद है, जब चर्चा होती है, बात आती है कि खाली खजाने के साथ बजट की बात की गयी थी। कहीं ना कहीं हम दुगुना करने की बात कह रहे हैं, पांच लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ जी.डी.पी. बढ़ाने की बात कह रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास, लोगों का समर्थन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साथ, निश्चित ही इस बजट में हर वर्ग को समाहित किया गया है और हम सब लोग भरपूर सहयोग और समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज बजट भाषण में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, मैं बहुत दिल से, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की ओर से इस बजट का विरोध करती हूं। मैं अपने भाषण की शुरूआत गोस्वामी तुलसी दास जी के कहावत से शुरू करती हूं। जो उन्होंने पूरे राम राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कहा है।

मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक।
पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।। (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय सभापति महोदय, मुखिया को मुख के समान ही होना चाहिए। मुख से ग्रहण कर रहे हैं और पूरे शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं। मैं इस सरकार से यह उम्मीद करती हूं कि जैसे सबकी रक्षा के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की रक्षा के लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध हैं लेकिन यहां विष्णु की बात करते हैं, विष्णु राज अलग है, यहां धोखाधड़ी की सरकार है। मैं कहना चाहती हूं कि यह बजट न ही प्रदेश के लिए है, न ही प्रदेशवासियों के लिए है और ना यह बजट किसी आम जनता के लिए है, यह बजट सिर्फ भाजपाईयों के लिए है। (मेजों की थपथपाहट) यह बजट सिर्फ उस क्षेत्र के लिए है, जहां पर

भा.ज.पा. के विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां भेदभाव किया गया है। तुलसी दास जी ने ऐसा नहीं कहा है। तुलसी दास जी का कथन है कि पूरे का समानता से पालन पोषण करिए लेकिन आज विष्णु राज के राज में अगर एक जगह फलीभूत हो रहा है तो एक जगह शोषण हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को विकलांग बना दिया है। यहां सब जगह एकतरफा बजट में शामिल किया गया है लेकिन अगर वह जिला पूरे कांग्रेस का हो, अगर एक जिले में कांग्रेस के प्रत्याशी हों तो उनका एक भी जगह बजट में प्रावधान नहीं है कि उनका कोई स्कूल जोड़ा जाए, उनका कोई भवन जोड़ा जाए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरी सहयोगी को अध्ययन की कमी है, अगर सक्ती जिले का, जांजगीर जिले का, बजट में अध्ययन करेंगे तो वहां पर सर्वाधिक दूसरे दल के सदस्य चुनकर आए हैं। संगीता दीदी के शब्दों को थोड़ा सुधारने की जरूरत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाह रही हूं। मेरे क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय चाहिए था, उसके लिए मैंने 10 बार आवेदन किया था, क्योंकि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ प्रधान राज्य है, छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत जनता कृषि करती है और उनको अधिकार है, खासकर बालोद जिले में सभी कृषि करते हैं तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि आपकी सरकार विकलांगता दिखा रही है। साथ में यह मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो मैं मोदी की गारंटी के बारे में इतना कहना चाहती हूं कि यह लोगों को उजाड़ने का काम करते हैं, उसकी गारंटी है, जनता को प्रताड़ित करने की गारंटी है, देश को लूटने की गारंटी है और मोदी की इस गारंटी में गरीब को और गरीब बनाने की गारंटी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम ही अपने आप में गारंटी है। मैं इस विषय पर आपत्ति दर्ज करता हूं कि यदि आप गलत शब्दों और असंसदीय व्यवस्था का परिपालन करेंगी तो यह आपत्तिजनक विषय है।

श्री रामकुमार यादव :- शुक्ला महाराज, गारंटी हे ता हमर 15 लाख रूपये ला दिलाओ न। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पहले 23 करोड़ गरीब थे। उस 23 करोड़ गरीब जनता को 80 करोड़ बनाने का कार्य यह सरकार और मोदी की गारंटी कर रही है। आज हम देखते हैं कि जब से विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, तब से हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपकी सरकार को बने हुए कुछ महीने ही हुए थे, 2-4 दिन ही हुए थे और जशपुर में घटना हुई कि 5 साल की गुड़िया के साथ 9-9, 7-7 लोगों ने बलात्कार किया था। साथ में मेरे जिले में आज तक 5 साल हो गये।

श्री सुशांत शुक्ला :- बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, जशपुर के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार में जशपुर में विकलांग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार में..।(शेम-शेम की आवाज)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार में झड़ियावाली काण्ड भी हुआ था। उस समय मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। संगीता जी, आप आगे बढ़िये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रही थी कि हर महिलाएं तो सुरक्षित नहीं हैं। साथ में हमारी जो छोटी-छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। चूंकि अभी पर बजट की चर्चा कर रही हूं तो बजट की चर्चा में सबसे मुख्य विषय महिलाएं हैं। महतारी वंदन योजना, जिसके लिए मैंने आदरणीय अजय चंद्राकर जी से 4 बार कहा कि आप महतारी वंदन योजना पर बोलिये। लेकिन वह नहीं बोले। मैंने उनको पुश किया कि आप सिलेण्डर के बारे में बोलिये, लेकिन वह नहीं बोले। यहां तक कि हमारे सभी आदरणीय खड़े थे, लेकिन उन्होंने महतारी वंदन योजना या 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देने की बात नहीं की। जब आप चुनाव के समय जनता के पास गये और वहां आपने लोगों से फॉर्म भरवाया। मैं पैसे की बात नहीं करती, आपने आधे लोगों को पैसा दिया है। 1000 ए बोनस ला रख अऊ दूसरा ले निकालबे। मोर सरकार आही ता मोला दे देबे। यह बात कही गई है। आप सभी विधान सभा क्षेत्रों में पता कर लीजिए कि उनके पास इनके लोग गये और 1-1 महिला से यह कहा गया कि आप यह फॉर्म भरिये और यदि 1 घर में 3 महिलाएं तो तीनों से फॉर्म भरवाया गया था और उनको दिया गया।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय सभापति महोदय, यह जो असत्य आरोप लगाया जा रहा है उसको आप ध्यान से मत सुनिये। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपका तो वीडियो वायरल हुआ है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं ऐसे हजारों फॉर्म पेश कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन फॉर्म देहौं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने फॉर्म भरवाया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप बैठिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपने महिलाओं से असत्य कहा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने महिलाओं के साथ छल किया है उसका आपको भुगतना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री प्रणव कुमार मरपची :- आपको बोलने का मौका मिला है और आपके पक्ष के सभापति महोदय बैठे हैं तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, 1 हजार रूपये मतलब सालाना 1,200 रूपये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी बहन को टोक रहा हूं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो नियमावली तय की गई है उस पर इस सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि यह सुनिश्चित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की एक-एक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना के तहत् विष्णुदेव सरकार में सम्मान मिलेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने उस समय नियमावली नहीं बतायी थी।

श्री रामकुमार यादव :- पेंशन देथो, तेन ला काट देथो। ओला पूरा-पूरा दो ना।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आपस में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप न करें। माननीय सदस्य का भाषण होने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपकी बात का पालन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति महोदय, जो कलेक्टर के घर वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए, जो विधायक के घर वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है कि इन्होंने फॉर्म भरवाया। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सबको मिलने वाला है। संगीता जी, सुनिये।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- भैया, किसी को नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है ? आप यह बताइये कि क्या आपकी घर वाली को मिल रहा है ? विजय भैया तो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, एक मिनट। मैं आपको रेस्ट दे रहा हूं। सबको मिलेगा। अब एक महीने में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को थोड़ी न मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो उसी कैटेगिरी में हैं। आपको 1000 रूपये थोड़ी न मिलेगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अंबनी के घर वाली ला झन मिले। ओ झाड़ू-पोछा लगाने वाली मितानीन ला मिलही या नहीं मिलही ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यादव जी, बार-बार टोका-टाकी न करें। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, 5 साल पहले प्रति महिला सालाना 6 हजार रूपये देने वाले लोग एक रूपये नहीं दिये। आज वह प्रश्न कर रहे हैं। यह आपत्तिजनक है। (शेम-शेम की आवाज)

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, इन्होंने फार्म भरवाया, वहां तक भी ठीक है । हमें खुशी थी कि आपकी सरकार आई है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपको खुशी है, लेकिन आपको प्रश्न का जवाब देना होगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बता रही हूं, मेरी बात तो सुनिए । हम खुश हैं, हम सभी महिलाएं खुश हैं कि हमें महतारी वंदन योजना से 1-1 हजार रूपए मिल रहा है क्योंकि हर पति लोग पत्नियों को पैसा नहीं देते, आप लोग मानते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इसका क्या सबूत है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति जी, अभी संगीता जी बोली हैं कि पुरूष लोग महिलाओं को पैसा नहीं देते । आप देते हैं या नहीं, आप वहां बैठे हैं, बता दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, नारी वंदन योजना सरकार की बहुत महत्वपूर्ण घोषणा और नीति में आ भी रहा है, लेकिन इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य काका जी (श्री पुन्नूलाल मोहले की ओर इशारा करते हुए) बैठे हैं । जैसे ही इसका भुगतान शुरू होगा, उनके यहां काकी खुश होंगी तो वे अगली बार बता देंगे । असली अन्याय तो वहीं होने वाला है, आप देख लीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- ये सरकार ला गरीब कर दिही, ओकर 12-14 झन हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पहिली ओकर बर काकी खोज देवव ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी श्रीमती ही नहीं है ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए, संगीता जी, अपनी बात आगे बढ़ाईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात रख रही हूं । हर महिलाओं को सालाना 12 हजार रूपए मिलेंगे, लेकिन जो शर्त लगाई जा रही है, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो उसमें 70 लाख महिलाएं हैं और सभी 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इस योजना में इतने सारे बंधन लगा दिया गया है, बहुत सारे नियम और शर्त लगा दी गई है । जब इन्होंने फार्म भरवाया तो कभी शर्त नहीं लगाए थे कि आयकर देते हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये वाली बात कभी नहीं किये थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी, आपको टोक नहीं रहे हैं, आप अच्छा बोलिए । आप (श्री पुन्नूलाल मोहले की ओर इशारा करते हुए) इधर देखकर बोलिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की 10 से 15 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, बाकी 65 लाख महिलाओं को इसका लाभ बिल्कुल नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलेगा । मैं इसका घोर विरोध करती हूं । आपको 70 लाख महिलाओं को देना पड़ेगा क्योंकि आपके बजट में वह प्रावधान नहीं है । आपके बजट में जो लक्ष्मी माता है, वह कम है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय सदस्या भी एक महिला हैं और छत्तीसगढ़ की आधी आबादी का अपमान कर रही हैं कि इस योजना से वे वंचित रहेंगी । वे सदन के माध्यम से उनको दिग्भ्रमित कर रही हैं । सदन छत्तीसगढ़ का केन्द्र है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी जो बजट आया है, उसमें इस योजना के लिए कम राशि रखी गई है । आप 70 लाख महिलाओं के लिए उस राशि को जोड़िए । जो 70 लाख महिलाएं आपको वोट दी हैं, आपकी सरकार बनाने में मदद की हैं, उनके साथ धोखाधड़ी मत करिए । यहां तक कि इसमें एक और नियम ला दिया है कि जो विधवा महिलाएं हैं, उनको पेंशन के रूप में 500 रूपए मिलता है। इस महतारी वंदन योजना में 500 रूपए को काटकर 500 रूपए उनको दिए जाएंगे । यह नियम आपने पहले कहां रखा था ? यह नियम तो था ही नहीं । यह आपके लिए बहुत लज्जा की बात है ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ समय तो ओला नहीं बोले रेहेव कि ओला जोड़के देबो करके ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं । जो महिला अकेले रहती हैं, अपने घर में बच्चों का लालन-पालन करती हैं, उन्होंने भी इस महतारी वंदन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको वोट दिया है, उनके साथ धोखाधड़ी मत करिए । उनको 500 रूपए नहीं देकर उनको 1 हजार रूपए दिया जाये, यह मैं आपसे निवेदन करती हूं । इस बजट में आप उसको जुड़वाईए ।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक बहुत ही सुन्दर योजना बिजली बिल हाफ योजना चलाई थी, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि आपने बिजली बिल हाफ योजना को जारी रखा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोगों ने तो पिछले बार बिजली ही साफ कर दिया था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिए । हमारी सरकार का दिल कितना बड़ा है । आपकी अच्छी योजना का सम्मान हुआ न । अब नरवा, गरूआ, घुरूओ, बारी बोलोगे तो कहां से मन करेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैंने बिजली बिल हाफ योजना के लिए सम्मान किया । दूसरी बात कहना चाहती हूं । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में दो दिन पहले गए थे, वहां महिलाओं ने आन्दोलन किया था । जो रसोइया खाना बनाती है, उनके मानदेय का कहीं कोई चर्चा नहीं है । इस बजट में रसोइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं है । क्या रसोइयों ने आपको वोट नहीं दिया है ? सफाई कर्मचारियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, मितानीन बहनों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री जी, वह सब आपसे उम्मीद करते हैं। वित्त मंत्री जी सामने बैठे हैं। वित्त मंत्री साहब, मैं चाहती हूं कि अभी बजट पारित

नहीं हुआ है, बजट पारित करने के लिए 24 घण्टे का समय है। आप इनको बजट में डालिये और उनके साथ न्याय कीजिये। उन महिलाओं के साथ न्याय कीजिये, जो 40 रूपये मजदूरी पर काम करती है।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, जेन महिला के सम्मान नइ करय, तो बहिनी हर बहरी-मुठिया ला भी धरे जानथे।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, थोड़ा समय दीजिये।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, हो गया। आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि ..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरी बड़ी बहन की आंख बहुत जल्दी 60 दिन में ही खुल गई कि छत्तीसगढ़ की महतारियों को क्या-क्या समस्या थी, 60 दिन में हृदय परिवर्तन हुआ, इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं कि अभी बजट पारित नहीं हुआ है। वित्त मंत्री साहब उसमें अभी भी संशोधन कर सकते हैं। मैं क्षेत्र की जनता के लिए निवेदन कर रही हूं कि जो महिलाएं बहुत कम पैसे में काम कर रही हैं, यदि आप उन जरूर निर्णय लेंगे तो उन बेचारियों को हक मिलेगा। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि आप महिलाओं को खुश करिये।

श्रीमती प्रबोध मिंज :- संगीता जी, उनको भी मिलेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, मैं कृषि की बात करूंगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि दो लाख रूपये तक का कर्ज माफ होगा। अगर आप दो लाख रूपये तक का कर्ज माफ कर देते तो लोग आत्महत्या नहीं करते। आज उन लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि बजट में उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। आज उन लोगों का दो लाख तक का कर्ज माफ करें। धान का समर्थन मूल्य 3100 रूपया एकमुश्त देंगे, कहा था, यह बहुत बड़ी बात है। इसमें किसानों को 3100 रूपया एकमुश्त देने का कोई प्रावधान नहीं है। उनको एकमुश्त दीजिये। क्षेत्र के किसान आपको देख रहे हैं। हमारे 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जो बोनस दिया है, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। उस परिवर्तन को ध्यान दीजिये। आपका जो पूर्व में पंचवर्षीय कार्यकाल था, उसमें केवल दो साल का बोनस दिया है। वर्ष 2017-18 का बोनस देना छूट गया है। आप कृपा करके वर्ष 2017-18 का भी बोनस इस बजट में जोड़ देंगे, तो बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय जी, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। मुझे समय कम मिला। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि विष्णु राज चला रहे हैं, उसमें लक्ष्मी का पूरा सौ प्रतिशत सहयोग रहता है। विष्णु और लक्ष्मी मिलकर पूरा बैकुण्ठ धाम चलाते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और इस पृथ्वी की सेवा करते हैं। मैं विष्णु राज से कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता देख रही है, निहार रही है, जो बजट में छूटा है, उसमें आप जोड़ने का प्रयास कीजिये, हमारा निवेदन है। हमारे साथी इस बात को रखना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानदेय छूट गया है, उसको जोड़ दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करें। मैं इस बजट की घोर निंदा और विरोध करती हूं। अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस बजट पर पर कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय विषणुदेव साय जी की सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश को अग्रसर करने वाला बजट है। यह बजट प्रदेश के युवाओं के सपनों को, माताओं की उम्मीदों को, किसानों के अरमानों को और आदिवासियों के इच्छाओं को पूरा करने वाला बजट है । मैं इस बजट के माध्यम से माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का ख्याल रखते हुये आज जो बजट पेश हुआ है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग खुश नजर आ रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में, पूर्व में हमारी बहन महतारी वंदन के बारे में बोल रही थी । मैं इस पर कहना चाहूंगा कि अभी हमारी सरकार की जो योजना है, जो आज हर विवाहित महिला को 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 12 हजार सालाना देने की बात की गई है, जिससे आज हमारी सरकार पहले ही बजट में प्रमुखता के साथ हमारी माताओं का सम्मान करते हुये इस बजट को पेश किया है । आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी माता और बहनें बड़े खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, इस महतारी वंदन योजना में भाग ले रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार चाहे किसान की बात हो, नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा जो गारण्टी पत्र जारी हुये थे, उसे पूरा करने के लिये बड़े हौसले के साथ, छत्तीसगढ़ के हमारे किसानों को जो दो साल के बोनस के लिये बात किये थे, सभी किसानों के खाते में प्रति एकड़ 9 हजार की दर से सभी किसानों के खाते में जमा हो रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिनहा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जब भुगतान किये तो दो साल का प्रमाण पत्र किसान को जरूर दिये हो, लेकिन एक साल का ही बोनस आया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम का रहने वाला हूँ । राजिम को छत्तीसगढ़ में प्रयाग का जो दर्जा मिला है, उस राजिम विधान सभा का रहने वाला हूँ और वहीं से चुनकर आया हूँ । सभापति महोदय, राजिम की महत्ता के बारे में हम सभी अवगत हैं । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पवित्र त्रिवेणी संगम राजिम तीर्थ को कुंभ के रूप में पुन: स्थापित किये हैं । यह मेला पुरातन काल से लग रहा है । (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके लिये छत्तीसगढ़ सरकार को हृद्य से धन्यवाद देता हूँ । आज हमारे पूरे राजिम के महत्ता को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रसर है । सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती में कांग्रेस की सरकार रही है, जो कांग्रेस की सरकार बनते ही कुंभ मेले के दर्जे को समाप्त करके पुन: माघी पुन्नी मेला कर दिये थे, जिससे हमारे क्षेत्रवासी के मन में विश्वासघात करने का काम किया है । आज जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पुन: राजिम विधान सभा के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था को फिर से बढ़ाने का काम किया है । माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राजिम के कुंभ मेले में पूरे देश विदेश से भी हमारे पूज्य साधु-महात्मा जी आते हैं, शंकराचार्य जी आते हैं । मैं माननीय धर्मस्व मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे राजिम को पुन: कुंभ का दर्जा प्राप्त हुआ है । मैं एक बार पुन: धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आप सभी को हमारे विधान सभा के इस सत्र में न्यौता भी दे रहा हूँ कि राजिम कुंभ 24 तारीख से पुन: प्रारंभ हो रहा है । मैं उसके लिये सभी को आमंत्रित भी करना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह भव्य आयोजन आप सभी की उपस्थिति में संपन्न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो योजना प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये भाजपा सरकार प्रत्येक क्षेत्र में कारगर प्रयास किये जा रहे हैं । प्रदेश के जनता के जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है, जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है ।

<u>सदन की सूचना</u>

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्ष 2024 2025 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति के लिये आवास उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है । हमारे विष्णु देस साय जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीब जो आवास के लिये भटकते रहे हैं, पांच साल तक अपने घर में झिल्ली डालकर, खपरा डालकर, पैरा डालकर पांच साल तक इंतजार कर रहे थे। मैं सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार बनते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास की चिंता की है और छत्तीसगढ़ के लिये 18 लाख आवासों को पुन: स्वीकृति प्रदान की है। यह इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से सुनने को मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। आज पूरे जन-जन में एक आवाज उठ रही है कि पहली बार ऐसा बजट देखने का मिला है, जिससे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की धरा में, छत्तीसगढ़ की नस-नस में राम बसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को हमारे भगवान राम की जन्म स्थली, अयोध्या की भव्य मंदिर में पुन: हमारे प्रभु श्री राम की वापसी हुई है। जिसके लिये हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के नस-नस में राम बसे हुए हैं। हमारी सरकार उस राम लला के दर्शन के लिये, अयोध्या जाने के लिये, प्रदेश के वृद्धजनों के लिये श्रवण कुमार के रूप में काम कर रही है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां सभा में हमारे सभी दल के सदस्य बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे गांव, गरीब, किसान के क्षेत्र में हो, चाहे आदिवासी भाई-बहनों के क्षेत्र में हो, चाहे नक्सल समस्याओं के उन्मूलन की बात करें या चाहे कानून का राज स्थापित करने की बात हो, चाहे धर्म की बात हो या पर्यटन की बात हो, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश के कोने-कोने तक, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुंचाने के लिये कृतसंकल्पित है। जिसके लिये मैं हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(05 बजकर 33 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ 24, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 12 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं